भारत जीवन बीमा निगम

बनाम

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एवं अन्य

19 दिसंबर, 1985

{ 0. चिनाप्पा रेड्डी, ई. एस. वेंकटरमैया, वी. बालकृष्ण

इराडी, आर. बी. मिश्रा और वी. खालिद, जे. जे.]

ए. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, धारा 29 (1) (बी)- क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिनियम की धारा 29 (1) (बी) के तहत "पूर्व-कार्योत्तर" अनुमति देने की शक्ति या अधिकार था। निगमित न की गई कंपनी द्वारा भारत में शेयरों की खरीद के लिए भारत में या क्या ऐसी अनुमति आवश्यक रूप से पूर्व अनुमति होनी चाहिए-शब्द और वाक्यांश "अनुमति" का अर्थ है।

बी. कॉर्पोरेट लोकतंत्र, की अवधारणा, समझाया गया।

ग. कंपनी कानून-शेयर शेयर-शेयरों में संपत्ति की प्रकृति कानून के तहत शेयरों में संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव को समझाया गया-कंपनी अधिनियम, 1956, धारा 2 (46), 82,84, 87 , 106 , 108 (1) , 108 (1 - ए) (ए) और (बी), 108 से 108 एच, 110,111 (1) और 3,206,207,397,398,428,439 और 475 की धारा 27 के साथ पढ़ें प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, माल की बिक्री अधिनियम, धारा 2 (7), 19,20 से 24 और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, धारा 6।

घ. कंपनी अधिनियम, 1956, धारा 291-293 स्थिति और कंपनी में निदेशकों की विवेकाधीन शक्तियों की प्रकृति।

ई. किसी कंपनी के शेयर, हस्तांतरण के लिए इनकार का हस्तांतरण शेयरों की सीमा-क्या कंपनी द्वारा एफ. ई. आर. ए., उचित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 (1) और (3) के तहत रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भी शेयरों को हस्तांतरित करने से इनकार किया गया था।

एफ. शेयर, भारतीय विदेशी निवेशक द्वारा की गई खरीद राष्ट्रीयता/उत्पत्ति-उदाहरण मामले के तथ्यों पर, क्या इसमें गैर-निवासी निवेश योजना के विदेशी मुद्रा विनियमन का कोई उल्लंघन शामिल है।

जी. कॉर्पोरेट पर्दा उठाने का सिद्धांत द्वारा किए गए निवेश -विदेशी मुद्रा विनियमों के साथ भारतीय राष्ट्रीयता के गैर-निवासियों के स्वामित्व वाली कंपनी, गैर-निवासी बाह्य खाता नियम, 1970, पोर्टफोलियो निवेश योजना, विनिमय नियंत्रण नियमावली, स्टॉक एक्सचेंज नियंत्रण (विनियमन) अधिनियम, 1956 और इसके उपनियम क्या न्यायालय इन नियमों को भेद सकता है। लेन-देन का पर्दा।

एच. मांग पर असाधारण आम बैठक बुलाने का शेयरधारकों का अधिकार या तो संघ के लेखों को बदलने के लिए निदेशकों को हटाना/बदलना-राज्य और शेयरधारक होने के नाते इसके साधनों को सामान्य

शेयरधारक कंपनी अधिनियम, 1956, धारा 169,172,173 (3), 284, एल. आई. सी. अधिनियम, धारा 6 के समान अधिकार हैं।

I. भारत का संविधान, 1950, आदेश XXXIX नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 14,19,32,226-क्या न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। शेयरधारक के सामान्य निकाय की बैठक बुलाने और निषेधाज्ञा देने के अधिकार के साथ-न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 14 ने समझाया।

जे. राष्ट्रीय हित में अधिनियमित कानूनों का निर्माण, समझाया।

के. अंग्रेजी मामले, बाहरी सहायता अनुमत रूप के रूप में संदर्भ, क्या अधिनियम को नियंत्रित कर सकते हैं। एल. विनिमय नियंत्रण नियमावली-पैरा 24,24 ए-1 और 28 ए-1 जिसका शीर्षक है "भारत में विदेशी निवेश का परिचय-इसकी प्रकृति-" चाहे वैधानिक निर्देश हो।

एम. विदेशी मुद्रा विनियमन, 1973-एन. आर. पी. योजना के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति का अनुदान जिस कंपनी के शेयर एन. आर. आई. द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में खरीदे गए हैं, उससे पूछताछ की जा सकती है।

एन. पूर्वव्यापीता, की प्रयोज्यता के खिलाफ नियम।

0. भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के स्वामित्व वाली कंपनियों और विदेशी निकायों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजनाभारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एफ. ई. आर. ए. की धारा 73 (3) के तहत समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 17.9.83 और दिनांक 19.9.83 (दोनों) में निहित स्पष्टीकरण और भारत सरकार द्वारा जारी दिनांकित 19.9.83 पत्र के अनुसार, क्या वैध है।

पी. माला मानते हैं कि क्या भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम को 911 पर कहा जाए।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स

सामान्य बैठक की आवश्यकता के मामले में और क्रमशः कपारो कंपनियों द्वारा किए गए शेयरों की खरीद द्वारा निवेश में दुर्भावनापूर्ण कार्य किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे मौजूदा विश्व आर्थिक प्रणाली के तहत काम करना है, को अपनी विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। एक जलाशय अर्जित करने, उसके संरक्षण और निर्माण के उद्देश्य से और इसके उचित उपयोग में सुधार के लिए संसद और भारतीय रिजर्व बैंक सहित कार्यकारी सरकार समय-समय पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और उसके तहत बनाए गए अन्य संबद्ध अधिनियमों और नियमों के तहत कई कदम

उठा रही है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने गैर-निवासी बाहरी खाता नियम, 1970 नामक नियम बनाए। भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के गैर-निवासी व्यक्तियों को भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के लिए आकर्षित करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया और एक "पोर्टफोलियो निवेश योजना" तैयार की। इस योजना की घोषणा सरकार द्वारा 27.2.1982 पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 73 (3) के तहत जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या 9 दिनांक 14.4.1982 में की गई थी। इसके पैराग्राफ 4 (ए) में प्रावधान है कि उदारीकृत नीति के तहत भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के गैर-निवासियों को भारत में स्टॉक एक्सचेंजों पर उद्धृत शेयरों में पोर्टफोलियो निवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें निवेश की गई पूंजी और अर्जित आय के पुनर्वितरण का पूरा लाभ होगा, जो उसमें प्रावधानों के अधीन होगा। इसके बाद 10 नंबर के और परिपत्र जारी किए गए।

सभी परिपत्रों का शुद्ध परिणाम यह था कि भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले गैर-निवासी व्यक्ति कंपनियाँ, साझेदारी फर्म फर्म, समितियाँ, न्यास और अन्य निगमित निकाय जो भारत के अनिवासी व्यक्तियों के स्वामित्व में थे या जिनमें लाभकारी हित निहित थे।

60 प्रतिशत से कम की सीमा तक राष्ट्रीयता/मूल भारतीय कंपनियों के शेयरों में प्रत्यावर्तन के आधार पर ऐसी भारतीय कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के एक प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने के हकदार थे, बशर्ते कि इस तरह के पोर्टफोलियो निवेश का कुल 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक न हो। यह मायने नहीं रखता था कि निवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। आवश्यक बात यह थी कि 60 प्रतिशत स्वामित्व या लाभकारी ब्याज भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासी व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए। हालांकि 912

प्रत्येक निवेशक द्वारा शेयरों के अधिग्रहण पर एक प्रतिशत की सीमा लगाई गई थी जिसके अधिग्रहण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। एक ही परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा या एक ही परिवार (समूह) की प्रत्येक व्यक्तिगत कंपनी द्वारा अलग-अलग एक प्रतिशत की सीमा तक हिस्सेदारी।

गैर-निवासी पोर्टफोलियो निवेश योजना का लाभ उठाने और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों में निवेश करने की इच्छा रखते हैं।

(एक भारतीय कंपनी), तेरह विदेशी कंपनियों, जिनमें से बारह के शेयर आईडी1 के स्वामित्व में थे और तेरहवें के शेयर कपारो ग्रुप लिमिटेड के स्वामित्व में थे, ने पंजाब नेशनल बैंक को अपने बैंकर (अधिकृत

डीलर) और मेसर्स के रूप में नामित किया। राजा राम भसीन एंड कंपनी इस उद्देश्य के लिए उनके दलाल के रूप में

निवेश करें। उनके नामित बैंकर मेसर्स पंजाब नेशनल बैंक ई. सी. ई. शाखा ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि ओ. ए. सी. और आर. पी. सी. प्रपत्रों के अनुसार कैपारो समूह की कंपनियों को इंग्लैंड में निगमित किया गया था और इसके 61.6 प्रतिशत शेयर स्वराज पॉल फैमिली ट्रस्ट के पास हैं, जिनके सौ प्रतिशत लाभार्थी स्वराज पॉल और उनके परिवार के सदस्य हैं, जो सभी भारतीय मूल के गैर-निवासी व्यक्ति हैं और उन्होंने रिजर्व बैंक से राजा राम भसीन एंड कंपनी की एजेंसी के माध्यम से तेरह कंपनियों में से प्रत्येक के नाम पर गैर-निवासी बाहरी खाते खोलने के उद्देश्य से अपनी मंजूरी देने का अनुरोध किया। स्टॉक निवेश सलाहकार और दिल्ली स्टॉक एंड शेयर विभाग दिल्ली के सदस्य। रिजर्व बैंक को लिखे पत्रों में यह उल्लेख किया गया था कि प्रस्तावित खाते सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से प्रेषण द्वारा "प्रभावित" होंगे और गैर-निवासियों द्वारा निवेश के लिए योजना में निहित योजना के बीच ही क्रेडिट और डेबिट की अनुमति होगी। हालांकि श्री स्वराज पॉल ने स्वराज पॉल के नाम पर एन. आर. ई. खाता खोलने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग शाखा को 63,000 डॉलर का प्रेषण किया था, लेकिन उनके बैंकरों ने रिजर्व बैंक को सलाह दी कि कैपारो ग्रुप लिमिटेड से होल्डिंग कंपनी से केवल चार प्रेषण प्राप्त हुए हैं, जो कि आई. डी. 2, आई. डी 4, आई. डी 1 और आई. डी 3 पर आई. डी 8,000 के समतुल्य राशि है।

रु. 2,36,59,000, Rs.76,35,000 और रु. 1,31,38,681.13p।

स्टॉक एक्सचेंज नियमों के तहत भुगतान अनुबंधित खरीद के दो सप्ताह के भीतर किया जा सकता है। एम/एस। राजा राम

इसलिए भसीन एंड कंपनी ने एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयर खरीदे थे। 33,40,865 पंजाब नेशनल बैंक द्वारा घोषित पहली प्रेषण तिथि 9.3.83 से पहले मंगला एंड कंपनी से। हालांकि, उक्त दलालों द्वारा किए गए शेयरों की खरीद के विवरण से पता चलता है कि 14.3.83 से भी, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों की कीमत 913 है।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स

₹. 3,85,920 भारत भूषण एंड कंपनी से खरीदे गए थे और Rs.45,81,677 के शेयर मंगला एंड कंपनी से खरीदे गए थे। दलालों ने नामित बैंक को सलाह दी थी कि आईडी1 तक खरीदे गए एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 75000 शेयरों में से, बारह कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा खरीदे गए 35,560 शेयर और तेरहवीं कंपनी द्वारा खरीदे गए 35,667 शेयर उनके द्वारा एच. सी. भसीन और श्री भारत भूषण के नाम पर एस्कॉर्ट्स कंपनी लिमिटेड में कंपनी के बही में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से दर्ज किए गए थे। स्टॉक एक्सचेंज विनियमों के उपविधि 242 के तहत, जो दलालों को अपने प्रधानाचार्यों के बजाय अपने नाम पर शेयर

दर्ज करने की अनुमति देता है, यदि वे बही बंद करने से पहले औपचारिकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इस बीच, 31.5.83 पर, पंजाब नेशनल बैंक ने एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को पत्र लिखकर सूचित किया कि तेरह कंपनियाँ एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों में निवेश कर रही थीं।

विदेशी निगमित निकाय जो मुख्य रूप से कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के स्वामित्व में हैं और तेरह विदेशी कंपनियों ने उन्हें अपने रूप में नामित किया था।

बैंकर और मैसर्स राजा राम भसीन एंड कंपनी निवेश के उद्देश्य से उनके दलालों के रूप में। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक और दलालों से निवेशकों के नामों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी और यह भी बताया कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें अनुमति दी थी। चूंकि दोनों में से किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने अपनी पुस्तकों में शेयरों के हस्तांतरण के सवाल पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया और इसकी सिफारिशों के अनुसार निदेशक मंडल ने शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, हालांकि उन्होंने पहले ही शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था, पंजाब नेशनल बैंक को इसके लिए लिखा था।

कई बिंदुओं पर जानकारी जैसा कि वे बनाना चाहते थे

भारत सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही जांच में सहायता करना। उन्होंने कई लेख भी लिखेकी खरीद में की गई विभिन्न अनियमितताओं के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक को

तेरह विदेशी कंपनियों द्वारा उनकी कंपनी के शेयर, इस तथ्य को दबाते हुए कि उन्होंने पंजीकरण करने से इनकार कर दिया है

उनके पक्ष में शेयरों का हस्तांतरण।

भारत सरकार की ओर से दिनांकित 17.9.83 के स्पष्टीकरण पत्र के अनुसार, उसी तारीख की अपनी प्रेस विज्ञप्ति और दिनांकित 19.9.83 के अपने परिपत्र संख्या 18 के अनुसार, रिजर्व बैंक ने

पंजाब नेशनल बैंक को उनकी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] SUPP.3 S. C. R. को टेलेक्स संदेश भेजा गया।

914 कपारो ग्रुप लिमिटेड द्वारा डी. सी. एम. और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों के बदले भुगतान करने के लिए विदेश से प्रेषित धन जारी करने की अनुमति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने का एक और प्रयास किया गया। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड द्वारा एक बार फिर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, जिन्होंने अपने दिनांकित पत्र 13.10.83 में कहा कि भारतीय

रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने के सवाल के अलावा, शेयरों को पंजीकृत करने से इनकार करने का बोर्ड का निर्णय अन्य आधारों पर आधारित था जो वैध होने के लिए निहित थे। इसलिए प्रत्यर्थी ने कंपनी अधिनियम की धारा 111 (3) के तहत केंद्र सरकार से अपील की।

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड वित्तीय से अनुचित दबाव का आरोप लगा रहा है

जैसे संस्थान। आई. सी. आई. सी. आई., आई. एफ. सी., एल. आई. सी., आई. डी. बी. आई. और यू. टी. आई. ने शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए और आई. डी. 2 पर आयोजित बैठक से लेकर आई. डी. 1 तक की परिस्थितियों और उदाहरणों को समझाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आई. डी. 1 पर रिट याचिका दायर की।

सर्कुलर No.18 दिनांक 19.9.83 की वैधता और उसी तारीख की प्रेस विज्ञप्ति जो न केवल संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (c) और 19 (1) (g) का मनमाना और उल्लंघनकारी है, बल्कि विदेशी मुद्रा विनियमों के प्रावधानों,

प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम आदि।

रिट याचिका द लाइफ दाखिल करने के बाद

भारतीय बीमा निगम, जिसके पास अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ कंपनी में कुल शेयरों का 52 प्रतिशत हिस्सा था, ने इस उद्देश्य के लिए एक असाधारण आम बैठक आयोजित करने के लिए कंपनी को दिनांक 11.2.84 पर एक अनुरोध जारी किया:

कंपनी के नौ अंशकालिक निदेशकों को हटाने और उनके स्थान पर नौ अन्य को नामित करने के लिए। यह आरोप लगाते हुए कि भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी और भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और कपारो समूह लिमिटेड द्वारा कंपनी को पंजीकृत करने के लिए मजबूर करने के लिए एक ठोस कार्रवाई का हिस्सा थीशेयरों के हस्तांतरण और रिट याचिका को वापस लेने के लिए, रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में उपयुक्त रूप से संशोधन करने और बैठक को मनमाना, अवैध, अधिकार से परे घोषित करने के लिए प्रार्थना (आई. ए.), (आई. बी.), (आई. सी.) और (आई. डी.) जोड़ने की मांग की।

आदि। रिट याचिका में संशोधन किया गया। पैराग्राफ 149 ए (1) से (44) को जोड़ा गया और साथ ही प्रार्थना (आई. ए.), (आई. बी.), (आई. सी.) और (आई. डी.) को भी जोड़ा गया।

बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को मंजूरी दी और निम्नलिखित तरीके से राहत दी:

" एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (बी) अनिवार्य है। कोई भी अनिवासी भारतीय निवेशक भारतीय 915 में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स

एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (बी) के तहत आर. बी. आई. की पूर्व अनुमति के बिना कंपनी; इस तरह की पूर्व अनुमति के बिना शेयरों की कोई भी खरीद अवैध है: न तो भारत संघ और न ही आर. बी. आई. ।धारा 75 के तहत या एफ. ई. आर. ए. की धारा 73 (3) के तहत निर्देश जारी करके अन्यथा आदेश देने का अधिकार है और न ही उन्हें शेयर खरीदने के बाद अनुमति देने का अधिकार है।

पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना। प्रेस विज्ञप्ति डीटी। 17.9.83 (Ex. A.), वृत्ताकार dt। 19.9.83 (Ex. B) और पत्र dt। 19.9.83 (Ex. C) पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं कर सकता है ताकि

एन. आर. आई. कंपनियों द्वारा किए गए शेयरों की खरीद को मान्य करें जो खरीद की तारीख को अयोग्य थे; न ही वे पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना शेयरों की खरीद को अधिकृत कर सकते हैं।

एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (बी) के तहत आर. बी. आई. जहाँ तक विवादित प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र और अनुमति देने वाला पत्र

प्रत्यर्थी-आर. बी. आई. की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना खरीदे गए शेयरों को रखने वाली कंपनियाँ, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (बी) और एफ. ई. आर. ए. की धारा 73 (3) के तहत भारत संघ और आर. बी. आई. में निहित शक्तियां। इस हद तक वे शून्य और निष्क्रिय दोनों हैं।

संभावित और पूर्वव्यापी रूप से। हालाँकि, विवादित प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र, 14 अप्रैल, 1982 के परिपत्र संख्या 9 के तहत शुरू किए गए पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों के साथ पोर्टफोलियो निवेश योजना में संशोधन करने के बराबर है और ऐसे संशोधन केवल संभावित रूप से संचालित होते हैं। उत्तरदाता No.18 की कार्रवाई

आक्षेपित माँग सूचना संपार्श्विक उद्देश्य के लिए की गई एक मनमाना और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है; यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भारत संघ और आर. बी. आई., उत्तरदाता संख्या। 1 और 2, इस संबंध में एल. आई. सी. की कार्रवाई के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। उनके और केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ लगाए गए दुर्भावनापूर्ण आरोप निराधार हैं। माँग सूचना और संकल्प उक्त सूचना के अनुसरण में आयोजित बैठक में पारित किए जाने को रद्द कर दिया जाता है। उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित भारतीय जीवन बीमा निगम अपील में आया है, और

भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय संघ और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर सीए 4598/84 को अनुमति देना औरएस्कॉर्ट्स लिमिटेड और नंदा द्वारा दायर क्रॉस अपील No.497-499/85 को खारिज करते हुए, कोर्ट सुपर कोर्ट रिपोर्ट [1985] SUPP.3 S. C. R.

916

पकड़ना: 1.1 भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 11.2.84 दिनांकित माँग सूचना जारी करने की कार्रवाईएस्कॉर्ट्स कंपनी लिमिटेड की कंपनी के नौ अंशकालिक निदेशकों को हटाने और उनके स्थान पर नौ अन्य को नामित करने के उद्देश्य से असाधारण आम बैठक न तो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 284 के प्रावधानों के विपरीत है और न ही भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 6 के तहत जीवन बीमा निगम में निहित शक्तियों से परे है। यह नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। एल. आई. सी. की उक्त कार्रवाई को मनमाना और दुर्भावनापूर्ण और संपार्श्विक उद्देश्य के लिए नहीं कहा जा सकता है या

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। [1022 एफ]

1.2 एक कंपनी, कुछ मामलों में, एक राज्य की तरह एक संस्था है जो अपने "बुनियादी संविधान" के तहत काम कर रही है।

कंपनी अधिनियम और एसोसिएशन का ज्ञापन "। आम बैठक में सदस्य और निदेशालय एक कंपनी के दो प्राथमिक अंग हैं जिनकी तुलना संसदीय लोकतंत्र के विधायी और कार्यकारी अंगों से की जा सकती है, जहां विधायी संप्रभुता संसद के पास होती है, जबकि प्रशासन कंपनी के दो प्राथमिक अंगों पर छोड़ दिया जाता है। कार्यकारी सरकार, सरकार को बदलने के लिए मजबूर करने की अपनी शक्ति के माध्यम से पार्लिया द्वारा नियंत्रण के एक उपाय के अधीन। सरकार की तरह निदेशक भी आम बैठक द्वारा गठित संसद के प्रति जवाबदेह होंगे। लेकिन व्यवहार में (फिर से सरकार की तरह), वे संसद पर उतना ही नियंत्रण रखेंगे जितना उन पर। हालांकि सामान्य बैठक में कंपनी के लिए कंपनी की सभी शक्तियों का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से संभव होगा, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं होगा

इस तरह की बोझिल मशीनरी द्वारा दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए (एक या दो-आदमी कंपनियों के मामले को छोड़कर) व्यवहार्य। इसलिए आधुनिक प्रथा यह है कि निदेशकों को कंपनी की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया जाता है, सिवाय इसके कि सामान्य कानून स्पष्ट रूप से सामान्य बैठक में प्रयोग किया जाना चाहिए। बेशक, जो शक्तियां पूरी तरह से वैध हैं, वे निदेशकों को शक्तियों के प्रदान करने से प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान है कि किसी अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए एक विशेष संकल्प की आवश्यकता होगी -

आम बैठक में कंपनी। कंपनी अधिनियम के तहत, कई मायनों में कंपनी की तुलना में निदेशालय की स्थिति सरकार की तुलना में संसद की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। संसदीय संप्रभुता का सख्त सिद्धांत किसी कंपनी के लिए सादृश्य द्वारा लागू नहीं होगा क्योंकि कंपनी अधिनियम के तहत, निदेशकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई शक्तियां हैं जिनके साथ सामान्य बैठक में सदस्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वे सबसे अधिक निदेशालय को बर्खास्त कर सकते हैं और उनके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त कर सकते हैं या अनुच्छेदों में बदलाव कर सकते हैं ताकि भविष्य के लिए निदेशकों की शक्तियों को प्रतिबंधित किया जा सके। सामान्य रूप से सदस्यों के लिए एकमात्र प्रभावी तरीका 917

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स

बैठक लोकतांत्रिक तरीके से निदेशालय पर अपने नियंत्रण का प्रयोग कर सकती है, जिसका उद्देश्य संघ के अनुच्छेदों में बदलाव करना है ताकि भविष्य के लिए निदेशकों की शक्तियों को प्रतिबंधित किया जा सके या निदेशालय को बर्खास्त किया जा सके और उनके स्थान पर अन्य लोगों की नियुक्ति की जा सके। निगम के अधिकांश स्टॉक के धारकों के पास चुनाव द्वारा अपनी पसंद के निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति होती है और उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव द्वारा उन्हें विनियमित करने की शक्ति होती है। यही निगमित लोकतंत्र का सार है। [1010 जी-एच; 1011 ए-एच]

तत्काल मामले में, एस्कॉर्ट्स कंपनी के 52 प्रतिशत शेयर रखने वाले वित्तीय संस्थानों की इसके कामकाज और भविष्य में बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी और वे इस बात से दुखी थे कि प्रबंधन ने उनसे परामर्श करने या उन्हें सूचित करने का विकल्प भी नहीं चुना कि एक रिट याचिका दायर करने का प्रस्ताव था जो कंपनी के खिलाफ कठिन और महंगी मुकदमेबाजी शुरू करेगी और कंपनी को शामिल करेगी।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक। संस्थान रिट याचिका को वापस लेने और मामले पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थे

आगे। चूंकि प्रबंधन इस मार्ग के लिए सहमत नहीं था, इसलिए जीवन बीमा निगम ने सोचा कि उसके पास गैर-कार्यकारी निदेशकों को हटाने की मांग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि नया बोर्ड इस सवाल पर विचार कर सके कि क्या इस प्रक्रिया को वापस लिया जाए।

मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्णय। स्पष्ट रूप से वित्तीय संस्थान सरकार और रिजर्व बैंक के साथ टकराव से बचना चाहते थे और अधिक सुलहकारी दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे। साथ ही, जीवन बीमा निगम के प्रस्ताव में कार्यकारी निदेशकों को हटाने की मांग नहीं की गई थी, जाहिर है। क्योंकि उनका इरादा कंपनी के प्रबंधन को बाधित करने का नहीं था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने नौ गैर-कार्यकारी निदेशकों को हटाने और उनकी जगह लेने के लिए दुर्भावनापूर्ण कार्य किया था।

वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि। हटाने के लिए प्रस्तावित निदेशकों के खिलाफ कोई आक्षेप नहीं लगाया गया था। यह था कि एकमात्र तरीका जिसके द्वारा बोर्ड द्वारा मुकदमेबाजी शुरू करने में अपनाई गई नीति पर पुनर्विचार किया जा सकता है और

यदि आवश्यक हो तो उलट दें। यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। सत्ता की काठी में अल्पांश शेयरधारकों को मुकदमेबाजी में उतरने की नीति को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी

जिसका अधिकांश शेयरधारकों ने विरोध किया। कॉरपोरेट लोकतंत्र इस तरह से काम नहीं कर सकता है। [1010 ए-जी]

1.3 कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक को वैधानिक रूप से निर्धारित प्रक्रियात्मक और संख्यात्मक आवश्यकताओं के अधीन अधिकार है।

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार एक असाधारण आम बैठक बुलाना। उन्हें बैठक बुलाने से रोका नहीं जा सकता है और वे सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1985] SUPP.3 S. C. R. का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

बैठक में प्रस्तावित प्रस्ताव के कारण। न ही प्रस्तावों के कारण न्यायिक के अधीन हैं।

समीक्षा करें। [1016 बी-सी]

1.4 यह सच है कि कंपनी अधिनियम की धारा 173 (2) के तहत बैठक की सूचना के साथ एक राज्य संलग्न किया जाएगा।

प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धन अभिकर्ता, यदि कोई हो, सचिवों और खजाने, यदि कोई हो, और प्रबंधक, यदि कोई हो, के व्यापार के प्रत्येक मद से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को बैठक में निर्धारित करना, जिसमें प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धन अभिकर्ता, यदि कोई हो, की संस्था की प्रकृति या ब्याज, यदि कोई हो, शामिल हैं। यह प्रबंधन पर एक कर्तव्य है कि वह एक व्याख्यात्मक नोट में, आम बैठक से पहले आने वाले प्रस्ताव से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करे ताकि शेयरधारकों को बैठक बुलाकर उन प्रस्तावों के कारणों का खुलासा करने में सक्षम बनाया जा सके जिन्हें वे बैठक में पेश करने का प्रस्ताव करते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, हालांकि राज्य का एक साधन है, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के एक शेयरधारक के रूप में प्रत्येक शेयरधारक को कुछ निदेशकों को हटाने और उनके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के उद्देश्य से कंपनी की एक असाधारण आम बैठक बुलाने का समान अधिकार है। भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है और न ही वह प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के अपने कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य है। [1016 सी-एफ]

1.5 जब किसी शेयरधारक द्वारा कंपनी की आम बैठक बुलाने के लिए अनुरोध किया जाता है।

कंपनी अधिनियम एक निदेशक को हटाने और दूसरे को नियुक्त करने के लिए वैध रूप से कार्य करता है, न्यायालय द्वारा आम बैठक के आयोजन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। [1011 जी-एच]

शॉ एंड संस (सैल्फोर्ड) लिमिटेड बनाम शॉ [1935] 2 KB 113; आइल ऑफ वाइट रेलवे कंपनी v. तबौरदीन (1883) 25 चौ. D.320; इंदरविक वी. स्नेल 42 इंग. Rep.83; बेंटले-स्टीवंस बनाम। जोन्स [1974] 2 ऑल E.R.653; इब्राहिमी बनाम। वेस्टबोर्न गैलरीज लिमिटेड [1972] 2 सभी ई. आर. 492 का उल्लेख किया गया है।

1.6 राज्य की प्रत्येक कार्रवाई या राज्य का कोई साधन

राज्य को कारण से सूचित किया जाना चाहिए। उचित मामलों में, कारण से अनजान कार्यों को संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में मध्यस्थता के रूप में सवाल किया जा सकता है।

अनुच्छेद 14 को राज्य की कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए एक चार्टर के रूप में नहीं माना जा सकता है, ताकि राज्य को इस तरह के कार्यों के कारण बताते हुए अपनी कई गतिविधियों में अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। यदि राज्य की कार्रवाई राजनीतिक या संप्रभु प्रकृति की है, तो न्यायालय इससे दूर रहेगा। न्यायालय शैक्षणिक मामलों पर बहस नहीं करेगा या 919 की जटिलताओं से संबंधित नहीं होगा।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स

व्यापार और वाणिज्य। यदि राज्य की कार्रवाई संविदात्मक दायित्वों या अपकृत्य से उत्पन्न दायित्वों से संबंधित है, तो न्यायालय सामान्य रूप से इसकी जांच नहीं कर सकता है जब तक कि कार्रवाई में कुछ सार्वजनिक कानून की प्रकृति न हो। मोटे तौर पर, न्यायालय राज्य की कार्रवाइयों की जांच करेगा यदि वे सार्वजनिक कानून क्षेत्र से संबंधित हैं और यदि वे निजी कानून क्षेत्र से संबंधित हैं तो उनकी जांच करने से बचेंगे। [1017 सी-डी; ई-जी]

जब राज्य या राज्य का कोई साधन निगम जगत में प्रवेश करता है और किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो वह

स्वयं को एक शेयरधारक की सामान्य भूमिका मानता है और ऐसे शेयरधारक के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों के साथ एक शेयरधारक के वस्त्र धारण करता है। इसलिए, एक शेयरधारक के रूप में राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि वह जब बदलाव चाहता है तो अपने कारणों को बताए।

किसी भी अन्य शेयरधारक की तरह कंपनी के संकल्प द्वारा प्रबंधन। [1017 जी-एच; 1018 ए-बी]

ओ ैरली वी। मैकमैन [1982] 3 ए 11 ई. आर. 1124; डेवी बनाम स्पेलथॉन [1983] 3 ऑल ई. आर. 278; आई कांग्रेस डेल पार्टिडो [1981] 2 ऑल ई. आर. 1064; आर. वी. ईस्ट बर्कशायर स्वास्थ्य प्राधिकरण [1984] 3 सभी ई. आर. 425; और राधा कृष्ण अग्रवाल और अन्य। वी. बिहार राज्य [1977] 3 एस. सी. आर. 249 संदर्भित।

2. यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा (1) के मुद्दे के संबंध में लिया गया रवैया

इक्विटी से जुड़े डिबेंचर; (11) भारतीय वित्तीय संस्थानों को ऋणों का पुनर्भुगतान; और (3) एस्कॉर्ट्स के साथ गोएट्ज़ के विलय का प्रस्ताव दुर्भावनापूर्ण था और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड पर कैपारो समूह के शेयरों को पंजीकृत करने के लिए दबाव डालने का प्रयास था। इक्विटी से जुड़े डिबेंचर जारी करने के प्रस्ताव को

स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि एल. आई. सी. की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत रह जाएगी, जबकि सभी वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत से घटकर 1 प्रतिशत रह जाएगी। यदि एस्कॉर्ट्स के साथ गोएत्ज़े के विलय के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है तो भी यही स्थिति होगी। किसी भी कंपनी की इक्विटी पूंजी का बहुमत रखने वाला कोई भी व्यक्ति खुद को अल्पांश शेयरधारक बनने की अनुमति नहीं देगा। ऋणों के पूर्व भुगतान का उद्देश्य उन निदेशकों से छुटकारा पाना था जो वित्तीय संस्थान थे।

राष्ट्रों को नामित करने का अधिकार था। ट्रू एस्कॉर्ट्स ने श्री डावर को निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पेशकश की, भले ही वित्तीय संस्थानों को उन्हें नामित करने का कोई अधिकार न हो। लेकिन निर्देशक को नामित करने का अधिकार होना एक बात है और पीड़ित निर्देशक होना बिल्कुल दूसरी बात है। [1018 डी-ई; 1019 ए-बी; 1021 सी-डी]

3.1 कई वैधानिक प्रावधानों और न्यायिक उदाहरणों के समग्र दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि एक शेयरधारक के पास 920 है।

[1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक कंपनी में निस्संदेह रुचि, एक ब्याज जो उसकी शेयर होल्डिंग द्वारा दर्शाया जाता है। हिस्सेदारी ऐसी संपत्ति की सभी विशेषताओं के साथ चल संपत्ति है। शेयरधारक के अधिकार हैं (1) निदेशकों का चुनाव करना और इस प्रकार प्रबंधन में भाग लेना।उनके माध्यम से; (ii) कंपनी की बैठकों में प्रस्तावों पर मतदान करना; (111) लाभांश के रूप में कंपनी के लाभ का आनंद लेना; (iv) उत्पीड़न के मामले में राहत के लिए अदालत में आवेदन करना; (v) कुप्रबंधन के मामले में राहत के लिए अदालत में आवेदन करना; (vi) कंपनी को बंद करने के लिए अदालत में आवेदन करना; और (vii) बंद होने पर अधिशेष में हिस्सेदारी करना। [995 जी-एच; 996 ए]

3.2 एक शेयर हस्तांतरणीय है लेकिन जबकि हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता के बीच हस्तांतरण की तारीख से प्रभावी हो सकता है

हस्तांतरण, हस्तांतरण वास्तव में पूर्ण है और हस्तांतरणकर्ता एक शेयरधारक के सभी अधिकारों के साथ, अवधि के सही और पूर्ण अर्थों में एक शेयरधारक बन जाता है, केवल तभी जब हस्तांतरण कंपनी के रजिस्टर में पंजीकृत होता है। एक स्थानांतरण प्रभावी हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता के बीच हस्तांतरण की सूचना के बिना कंपनी और व्यक्तियों के खिलाफ तब तक प्रभावी नहीं है जब तक कि हस्तांतरण कंपनी के रजिस्टर में पंजीकृत नहीं हो जाता। वास्तव में जब तक हस्तांतरण कंपनी की पुस्तकों में पंजीकृत नहीं हो जाता है, तब तक वह व्यक्ति जिसका नाम केवल रजिस्टर में पाया जाता है, वह

लाभांश प्राप्त करने का हकदार है, भले ही वह पहले ही शेयरों में अपने हित के साथ भाग ले चुका हो। हालांकि, शेयरों के हस्तांतरण पर, हस्तांतरणकर्ता लाभकारी ब्याज का मालिक बन जाता है, हालांकि कानूनी स्वामित्व हस्तांतरणकर्ता के पास जारी रहता है। न्यासी और न्यासी का संबंध स्थापित हो जाता है और हस्तांतरणकर्ता उन सभी उचित निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है जो हस्तांतरणकर्ता दे सकता है। वह लाभांश के साथ-साथ मतदान के अधिकारों का भी संरक्षक बन जाता है। हस्तांतरणकर्ता के "रजिस्टर में शामिल होने" के अधिकार का उपयोग उचित परिश्रम के साथ किया जाना चाहिए और इक्विटी का सिद्धांत जो हस्तांतरणकर्ता को एक रचनात्मक ट्रस्टी बनाता है, उस मामले तक विस्तारित नहीं होता है जहां हस्तांतरणकर्ता "रजिस्टर में शामिल होने" के लिए कोई सक्रिय रुचि नहीं लेता है। [996 ए-डी]

3.3 जहां हस्तांतरण एक कानून द्वारा विनियमित किया जाता है, जैसा कि एक गैर-निवासी को हस्तांतरण के मामले में होता है जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, कानून द्वारा निर्धारित अनुमति, यदि कोई हो, प्राप्त की जानी चाहिए। अनुमति के अभाव में, हस्तांतरण तब तक हस्तांतरणकर्ता को "रजिस्टर पर जाने का अधिकार" नहीं देगा जब तक कि आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती। एक हस्तांतरणकर्ता जिसे रजिस्टर में शामिल होने का अधिकार है, जहां किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है या जहां अनुमति प्राप्त की गई है, वह कंपनी से हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए कह सकता है और जिस कंपनी से शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए कहा जाता है, वह हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकती है, सिवाय बोना 921 के।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स

उचित कारण, न ही मनमाने ढंग से, न ही किसी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए। सर्वोपरि विचार का हित है

कंपनी और शेयरधारक का सामान्य हित। दूसरी ओर, जहां एफ. ई. आर. ए. के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है, वह कंपनी के लिए खुली है, और वास्तव में, वह किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने के लिए बाध्य है यदि वह किसी अनिवासी का पक्ष लेती है। [996 ई-एच]

लेकिन एक बार अनुमति प्राप्त करने के बाद, चाहे वह पहले हो या बाद में।

शेयरों की खरीद के बाद, कंपनी शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकती है। न ही यह कंपनी या किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति के लिए खुला है कि वह खुद को संभाल ले, इसके बाद यह तय करने का कार्य कि क्या अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित रूप से दी गई थी। एफ. ई. आर. ए. इसे अपना अनन्य विशेषाधिकार और कार्य बनाता है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों को संरचित और बुना गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह केवल भारतीय रिजर्व बैंक को ही विचार करना है कि क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और समय-समय पर

जारी किए गए विभिन्न नियमों, निर्देशों और आदेशों की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और क्या अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम के तहत जारी नियमों, आदेशों और निर्देशों का पालन न करने के परिणामों का उल्लेख अनुभागों में किया गया है। 48 , 50 , 56 और अधिनियम की धारा 63। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को सक्षम बनाता हो।

अधिनियम की धारा 29 (1) के तहत अनुमति देने में रिजर्व बैंक सही था या गलत, यह अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए निर्धारित करने के लिए अधिनियम के बाहर कार्य करना। अधिनियम की योजना के तहत, यह विदेशी मुद्रा का "संरक्षक-सामान्य" है। प्रवर्तन का कार्य प्रवर्तन निदेशालय पर छोड़ दिया गया है,

लेकिन यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक को ही तय करना है कि अधिनियम की धारा 29 (1) के तहत अनुमति दी जा सकती है या नहीं। यह अधिनियम इसे अपना अनन्य विशेषाधिकार और कार्य बनाता है। किसी अन्य प्राधिकारी के पास कोई शक्ति नहीं है और न ही वह इस प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति ग्रहण कर सकता है कि क्या अनुमति दी जा सकती है या नहीं या क्या इसे दी जानी चाहिए थी या नहीं। इस प्रश्न को किसी भी न्यायालय के समक्ष सीधे या संपार्श्विक रूप से उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति देने पर एक इच्छुक पक्ष द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी कार्यवाही में इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि यह दुर्भावनापूर्ण था या यह कि दिमाग का कोई अनुप्रयोग नहीं था या यह अधिनियम द्वारा विचार किए गए राष्ट्रीय हित के खिलाफ था।

[996 एच; 997 ए-जी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

922

3.5 यह निश्चित रूप से उस कंपनी के लिए खुला नहीं है जिसके शेयर एक अनिवासी कंपनी द्वारा खरीदे गए हैं ताकि वह पंजीकरण करने से इनकार कर सके।

शेयर भारतीय रिजर्व बैंक से इस आधार पर अनुमति प्राप्त करने के बाद भी कि एफ. ई. आर. ए. के तहत अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 (1) के तहत अनुध्यात अनुमति का न तो इरादा है और न ही यह कंपनी या उसके किसी भी शेयरधारक के किसी भी तरीके या किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करती है। इसके विपरीत न तो कंपनी और न ही इसके किसी भी शेयरधारक को ऐसी किसी भी अनुमति पर सवाल उठाने का कोई विशेष अधिकार है। [997 जी-एच; 998 ए]

3.6 जहाँ लेखों ने निदेशकों को अस्वीकार करने की अनुमति दी थी

बिना कारण बताए शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए, न्यायालय आवश्यक रूप से निदेशकों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालेगा, लेकिन यह मान लेगा कि उन्होंने उचित और ईमानदारी से

काम किया है। जहां निदेशकों ने कारण दिए, वहां न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या कारण वैध थे और क्या निदेशक सही या गलत सिद्धांत पर आगे बढ़े। अगर लेख

निदेशकों को कारणों का खुलासा नहीं करने की अनुमति दी गई, उनसे पूछताछ की जा सकती थी और कारणों का खुलासा करने के लिए कहा जा सकता था। यदि वे उस कारण का खुलासा करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। [995 सी-एफ] मानेकजी पेस्टनजी भरूचा और अन्र। वी. वाडीलाल शेरभाई एंड कं. 52 आई. ए. 92; बैंक ऑफ इंडिया बनाम। जनशेतजी ए. आर. चिनॉय ए. आई. आर.

1950 पीसी 90; इन री फ्राय [1946] 2 ऑल ई. आर. 106; स्विस बैंक निगम बनाम। लॉयड्स बैंक लिमिटेड [1982] ए. सी. 584; चरणजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 41; माथेलोन और ओआरएस। वी. बॉम्बे लाइफ एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 385; वासुदेव रामचंद्र शेलट बनाम। प्राणलाल जयानंद ठक्कर [1975] 1 एस. सी. आर. 534; ए. के. रामैया बनाम रिजर्व बैंक (1970) 1 एम. एल. जे. पी. आई. संदर्भित।

4. कापारो ग्रुप लिमिटेड द्वारा या उसकी ओर से की गई शेयरों की खरीद को बंदरगाह का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

फोलियो योजना जितना हो सके: (1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (1) (बी) द्वारा अनुध्यात रिजर्व बैंक की अनुमति "पूर्व" या "पूर्ववर्ती" होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शेयरों की खरीद के लिए किसी स्तर पर अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। (11) स्टॉक एक्सचेंज नियमों के तहत भुगतान पहली खरीद के बाद दो सप्ताह के भीतर किया जा सकता है और विदेशी प्रेषण से भुगतान करने में कोई कठिनाई नहीं होती; (111) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 19 (4), 29 (1) (बी), 47,48,50,56 और 63 के प्रावधानों में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि -

923 की अनुमति प्राप्त किए बिना शेयरों की खरीद

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स

रिजर्व बैंक शून्य हो जाएगा। दूसरी ओर, इस तरह के लेन-देन से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्यवाही पर इस शर्त के अधीन विचार किया जाता है कि जब तक आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक किसी भी राशि को ऋण, क्षति या अन्य ज्ञान के रूप में वसूल नहीं किया जा सकता है। अगर

(iv) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम की धारा 27 के तहत, उक्त प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी के धारक के लिए किसी भी वर्ष के लिए कंपनी द्वारा घोषित किसी भी लाभांश को प्राप्त करना और बनाए रखना वैध होगा, इसके बावजूद कि प्रतिभूति उसके द्वारा पहले ही विचार के लिए स्थानांतरित कर दी गई है, जब तक कि हस्तांतरणकर्ता जो हस्तांतरणकर्ता से लाभांश का दावा करता है, उसने प्रतिभूति

और हस्तांतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज दर्ज नहीं किए हैं, जो कंपनी को लाभांश देय होने की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर अपने नाम पर पंजीकृत होने के लिए कंपनी के साथ आवश्यक हो सकते हैं।

नाम, यदि वे पुस्तकों के बंद होने से पहले औपचारिकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं; और (vi) योजना के तहत, कोई भी विदेशी

भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के व्यक्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व वाली कंपनी इस सुविधा का लाभ उठा सकती है।योजना द्वारा इस तथ्य की परवाह किए बिना दिया जाता है कि क्या विभिन्न कंपनियों में शेयरधारकों का एक ही समूह था। जहां कोई भी खरीद 2.5.83 के बाद की गई थी, वे कुल मिलाकर 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन थीं। केवल इसलिए कि अनुमति के लिए आवेदन करने वाली कई विदेशी कंपनियों के 60 प्रतिशत से अधिक शेयर एक न्यास के पास हैं, जिसके श्री.

स्वराज पॉल और उनके परिवार के सदस्य लाभार्थी हैं, कंपनियों को भारतीय कंपनियों में निवेश करने की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, यदि न्यास के छह लाभार्थियों में से ऐसे लोगों ने शेयरों की खरीद की अनुमति के लिए अलग से आवेदन किया था। भारतीय कंपनियों को इस तरह की अनुमति से वंचित नहीं किया जा सकता था। इसलिए केवल इसी कारण से यह नहीं कहा जा सकता है कि पोर्टफोलियो निवेश का कोई उल्लंघन हुआ है

योजना या कि दी गई अनुमति अवैध है। [1022 बी-सी; 988 एफ-एच; 989 ए-बी; 1004 ए-एच; 1005 ए-बी]

5. आम तौर पर और मोटे तौर पर, कॉर्पोरेट घूंघट को उठाया जा सकता है जहां एक क़ानून स्वयं घूंघट उठाने पर विचार करता है,

या धोखाधड़ी या अनुचित आचरण को रोकने का इरादा है या एक कर कानून या एक लाभकारी कानून से बचने की कोशिश की जाती है या जहां संबद्ध कंपनियां अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं जो वास्तव में एक चिंता का हिस्सा हैं। यह न तो आवश्यक है और न ही वांछित मामलों के वर्गों की गणना करने में सक्षम है जहां उठाने

कॉर्पोरेट घूंघट की अनुमति है, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से निर्भर करना चाहिए [

प्रासंगिक वैधानिक या अन्य प्रावधानों पर जिसका उद्देश्य प्राप्त करना चाहा गया था, विवादित आचरण, लोक हित के तत्व की भागीदारी और प्रभावित होने वाले पक्षों पर प्रभाव आदि। तत्काल मामले में "पर्दा उठाना" न तो आवश्यक है और न ही विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और

पोर्टफोलियो निवेश योजना की आवश्यक आवश्यकता से परे अनुमति है। इस अधिनियम का उद्देश्य विदेशी मुद्रा के प्रवाह का संरक्षण और विनियमन करना है।

ऐसी कंपनी या कानूनी व्यक्तित्व की जातीयता। इनमें से कौन?तब गैर-निवासी कंपनियों या कानूनी व्यक्तियों को भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका जवाब है -

यह पता लगाने के लिए कि क्या कम से कम 60 प्रतिशत शेयर भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के गैर-निवासियों के पास हैं, उस योजना द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है जो "निगमित पर्दा उठाने" का प्रावधान करती है। शेयरधारकों की राष्ट्रीयता या मूल का पता लगाने के लिए पर्दा उठाना आवश्यक है न कि व्यक्ति का पता लगाने के लिए।

प्रत्येक शेयरधारक की पहचान। कॉर्पोरेट पर्दा को केवल उस हद तक उठाया जा सकता है और उससे अधिक नहीं। इसके अलावा यह उच्च न्यायालय में रिट याचिका के दायरे से बाहर होगा। [1006 एफ-एच; 1007 ए-डी]

वाल्लरस्टीनर बनाम। मोइर, [1974] 3 ऑल ई. आर. 217; टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य, [1964] 6 एस. सी. आर. 885; आय कर आयुक्त v. मीनाक्षी मिल्स, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 819; कामगार बनाम। एसोसिएटेड रबर लिमिटेड, [1985] 2 स्केल 321; और सैलोमन बनाम। ए. सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, [1897] ए. सी. 22 संदर्भित।

6.1 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 द्वारा अनुध्यात रिजर्व बैंक की अनुमति "पूर्व" या "पूर्व" होने की आवश्यकता नहीं है। " और यह पूर्व पोस्ट फैक्टो बाद और सशर्त हो सकता है। [1021 एच]

6.2 विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1973 की धारा 29 (1) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "विदेशी मुद्रा अधिनियम की सामान्य या विशेष अनुमति" है।भारतीय रिजर्व बैंक "। यह "पूर्व" या "पूर्व" शब्द द्वारा योग्य नहीं है। जबकि "पूर्व" या "पूर्व" शब्द निहित हो सकता है यदि प्रासंगिक स्थिति या कानून का उद्देश्य और डिजाइन मांग करता है, यदि ऐसी कोई सम्मोहक परिस्थितियाँ नहीं हैं जो इस तरह के किसी भी निहितार्थ को पढ़ने को उचित ठहराती हैं।

धारा 29 (1)। हालाँकि संसद एक्सप्रेस 925 का उपयोग करके अपने इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता से बेखबर नहीं रही है।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स

" पूर्व अनुमति "। जब भी यह सोचा जाता है कि पूर्व अनुमति आवश्यक थी, उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 8 (1), 8 (2), 27 (1), 30 और 31, तो यह जानबूझकर योग्यता शब्द को टाल देता है।

" धारा 29 (1) में भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ हद तक लोच के साथ निवेश करने के लिए

गैर-निवासी कंपनियों को भारतीय कंपनियों में शेयर खरीदने की अनुमति देना। इसलिए, अनुमति शब्द की व्याख्या "पूर्व या बाद की अनुमति" के रूप में की जानी चाहिए और यह आवश्यक है कि गैर-निवासी कंपनियों द्वारा शेयरों की खरीद के लिए किसी स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। [979 एफ-एच; 980 ए-सी]

6.3 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की योजना धारा 29 (1) (बी) के तहत पूर्व अनुमति को अभेद्य नहीं बनाती है, हालांकि पूर्व अनुमति प्राप्त करने में विफलता विदेशी मुद्रा को उजागर कर सकती है।

अंततः अनुमति से इनकार कर दिया जाता है। अनुमति दिए जाने पर भी इसे सशर्त बनाया जा सकता है। अभिव्यक्ति "विशेष अनुमति" अपनी प्रगति में एक "सशर्त" के साथ लेने के लिए पर्याप्त व्यापक है। अनुमति ", कानून के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होने की शर्त, इस मामले में, विदेशी के संरक्षण और विनियमन

विनिमय करें। [981 एफ-एच]

6.4 न ही भारतीय रिजर्व बैंक पूर्व कार्योत्तर अनुमति देने के लिए बाध्य है जब भी यह पाया जाता है कि व्यवसाय किया गया है।

शुरू किया गया है या शेयरों को इसके पिछले बिना खरीदा गया हैअनुमति ली। ऐसे मामलों में, जहां भी भारतीय रिजर्व बैंक को किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य का संदेह होगा, वह न केवल अनुमति देने से इनकार करेगा

लेकिन न केवल अपराधी को दंडित करने के लिए बल्कि इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए भी धारा 50,61 और 63 के तहत कार्रवाई का सहारा लेगा। [981 ई-एफ]

6.5 संसद का इरादा पूर्ण रूप से निर्धारित करने का नहीं था

पूर्व अनुमति होना आवश्यक है। मुख्य उद्देश्य धारा 29 विनियमित करने के लिए है न कि पूरी तरह से ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए।

भारत में खंड (क) द्वारा अनुध्यात गतिविधि और भारत में चरित्र के किसी उपक्रम या शेयरों का अधिग्रहण

खंड (ख) में उल्लिखित। इसलिए, संसद ने अनुमति देने के लिए सबसे कुशल प्राधिकरण के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़ दिया

पूर्व या पूर्व कार्योत्तर, सशर्त या बिना शर्त। और यह रिजर्व बैंक से विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का उपयोग करने की उम्मीद की जा सकती है और

देश के सर्वोत्तम हित में और आगे बढ़ने के लिए

विदेश के मामले में घोषित सरकारी राजकोषीय नीति

विनिमय करें। [982 एफ; जी-एच] 926

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

6.6 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 13 और 67 और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 को एक साथ पढ़ने पर यह देखा जाता है कि धारा 13 एफ. ई. आर. ए. के तहत एक आदेश के रूप में कार्य करता है

निषेध और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निषिद्ध वस्तुओं के आयात को मान्य करने और प्रतिबंध से बचने के लिए बाद में अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।

सीमा शुल्क अधिनियम द्वारा निर्धारित परिणाम। इसलिए, धारा 19 और 29 की व्याख्या करने के लिए धारा 13 के सादृश्य को स्वीकार करना संभव नहीं है। [983 डी-ई]

6.7 यह सच है कि रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त न करने या निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के परिणाम गंभीर और गंभीर भी हैं। यह भी सच है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसके परिणामस्वरूप पुरुषत्व को खारिज किया जा सकता है। लेकिन इससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि अनुमति

धारा 29 द्वारा अनुध्यात अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमति है। [983 जी-एच; 984 ए]

6.8 यदि संसद का इरादा पिछली और बाद की अनुमति दोनों को समझना था, तो धारा 19 (5) में "पुष्टि" शब्द बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हालांकि "अनुमति" शब्द का व्यापक रूप से अर्थ निकालने की अनुमति हो सकती है, लेकिन "पुष्टि" शब्द का उपयोग कभी भी "पिछली अनुमति" के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। धारा 29 में "पुष्टि" शब्द पूरी तरह से गलत है।

[984 ई-एफ]

6.9 पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम को यहां प्रस्तुत स्थिति में आयात नहीं किया जा सकता है। पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम है

व्याख्या का एक नियम जिसका उद्देश्य अधिकारों को रोकना है जब तक कि स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया हो या आवश्यक रूप से निहित न हो। ऐसी स्थिति में जहां कोई निहित अधिकार शामिल नहीं हैं, पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम का आह्वान करना नियम के कारण को भूलकर व्याख्या के नियम को वैधानिक दर्जा देना है। [984 जी-एच; 985 ए-बी)

6.10 विनिमय नियंत्रण नियमावली का अनुच्छेद 24A.1 न तो एक वैधानिक निर्देश है और न ही यह एक अनिवार्य निर्देश है।

विदेशी मुद्रा विनियमन की धारा 73 (3) के तहत जारी किया गयाअधिनियम, लेकिन धारा 29 (1) (बी) पर टिप्पणी की प्रकृति में है। पैराग्राफ के लिए दिशानिर्देश का एक व्याख्यात्मक बयान है

अधिकृत विक्रेताओं का लाभ। इसमें ऐसा लिखा है जैसे कि यह प्रकृति में है और वास्तव में यह अधिकृत विक्रेताओं को दी गई सलाह है कि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए, ताकि बाद में कोई जटिलता न हो। यह एक जनादेश के बजाय एक सहायक सुझाव है। नियमावली अपने आप में अधिकृत विक्रेताओं, धन परिवर्तकों आदि के लिए एक प्रकार की मार्गदर्शक पुस्तक है और विभिन्न वैधानिक 927 का एक संग्रह या संग्रह है।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स

निर्देश, प्रशासनिक निर्देश, सलाहकार

राय,

टिप्पणियां, टिप्पणियाँ, स्पष्टीकरण, सुझाव आदि। पैराग्राफ 24 में "पूर्व अनुमति" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। ए (1) का उद्देश्य "सामान्य और विशेष" अभिव्यक्ति की सीमा को सीमित करना नहीं है।

धारा 29 (1) (बी) और 19 (1) (बी) में अनुमति दी गई है। इसका मतलब है

सामान्य प्रक्रिया को इंगित करें जिसका पालन किया जा सकता है।

[986 बी-ई]

6.11 प्रपत्र अधिनियम, नियमों या अधिनियम को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।

दिशा निर्देश। निर्धारित प्रपत्रों में से कोई भी, निस्संदेह, आवेदन और बाद की अनुमति के अनुदान के लिए प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आम तौर पर कोई व्यक्ति अधिनियम से पहले अनुमति लेने और दिए जाने की उम्मीद करेगा। [986 ई-एफ]

6.12 पोर्टफोलियो निवेश योजना किसी की बात नहीं करती है।

पूर्व या पूर्व अनुमति। इसके अलावा संसदीय कानून के तहत रिजर्व बैंक के पास मौजूद शक्ति को इस तरह से कम नहीं किया जा सकता है कि इसके प्रयोग को पूरी तरह से रोका जा सके। यह अधीनस्थ विधायी

निकाय के लिए एक शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने के लिए उचित नियम और विनियम बनाने के लिए खुला हो सकता है जो

संसद ने इसमें निहित किया है ताकि कानून के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, लेकिन वह खुद को शक्ति से वंचित नहीं कर सकती है। इसलिए, यदि रिजर्व बैंक के पास एफ. ई. आर. ए. के तहत पूर्व कार्योत्तर अनुमति देने की शक्ति है, तो वह योजना के तहत उस शक्ति से खुद को अलग नहीं कर सकता है। [987 ए-डी]

शाकिर हुसैन बनाम। कैंडू लाल और ओआरएस। , एयर 1931 ऑल। 567 ,

वासुदेव रामचंद्र शेलत बनाम। प्राणलाल जयानंद ठाकुर, [1975] 1 एस. सी. आर. 534 का उल्लेख किया गया।

7.1 जब राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियमित कानूनों का अर्थ लगाया जाता है

हित में, न्यायालयों को अनिवार्य रूप से अधिनियम द्वारा विचार की गई व्यापक तथ्यात्मक स्थितियों को लेना चाहिए और इसके प्रावधानों की व्याख्या करनी चाहिए ताकि आगे बढ़ सकें और उस विशेष राष्ट्रीय हित को विफल न किया जा सके जिसकी प्रगति कानून द्वारा प्रस्तावित है। वैधानिक व्याख्या के पारंपरिक मानदंडों को राष्ट्रीय हित की व्यापक धारणाओं के अनुरूप होना चाहिए। [980 जीएच; 981 ए]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उद्देश्य है -

विदेशी मुद्रा अर्जित करें, संरक्षित करें, विनियमित करें और संग्रहीत करें। पूरा मामला अधिनियम की योजना और प्रारूप उसी लक्षय की ओर निर्देशित है।

धारा 76 इस बात पर जोर देती है कि केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई प्रत्येक अनुमति या लाइसेंस को विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण की इच्छा से सक्रिय किया जाना चाहिए।

एक देश से।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, है

इसलिए, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हित में अधिनियमित एक क़ानून।

[980 सी-जी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

928

7.2 क़ानूनों की व्याख्या करने का उचित तरीका अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में योग्य शब्दों के उपयोग के लिए उपयोग के साथ-साथ चूक को उचित महत्व देना है। एक प्रावधान में योग्यता शब्द के उपयोग और दूसरे प्रावधान में इसके गैर-उपयोग के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। [980 बी-सी]

7.3 प्रत्येक शब्द के अलग-अलग अर्थ होते हैं और अलग-अलग शब्दों का एक ही अर्थ हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। [984 ई]

अलग-अलग कोणों से देखने पर अलग-अलग रोशनी। यदि सरकार के उच्च स्तर के लोगों के साथ पूर्ण चर्चा के बाद, जो नीति-निर्माण से संबंधित हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व नकारात्मक दृष्टिकोण को देश की अर्थव्यवस्था के हित में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण में बदल दिया, तो उसका निर्णयइसे मन के किसी भी दबाव या गैर-अनुप्रयोग का परिणाम नहीं कहा जा सकता है। और केवल इसलिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी से प्राप्त संचार का जवाब भेजने का विकल्प नहीं चुना, इसका मतलब यह नहीं था कि भारतीय रिजर्व बैंक ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था। [999 ई; जी-एच; 1000 बी]

10. भारत संघ को भी किसी दुर्भावना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। [1022 डीजे

11. पंजाब नेशनल बैंक की ओर से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत अधिकृत विक्रेताओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कपारो समूह की कंपनियों की ओर से की गई शेयरों की खरीद की कोई निगरानी नहीं की गई। [1022 डी-ई]

12. वह प्रश्न जिसमें साक्षय को जोड़ना शामिल होगा या जैसा कि तत्काल मामले में एक व्यक्ति की जांच होगी

शेयरों की खरीद चाहे वे विदेशी मुद्रा या स्थानीय रूप से उपलब्ध निधियों से खरीदे गए हों, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका के दायरे से बाहर होगी।

संविधान। [1004 जी] 929

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 4598

1984 .

बॉम्बे के 9.11.1984 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1983 के सिविल रिट सं. 3063 में उच्च न्यायालय।

के. परासरन, महान्यायवादी, एम. के. बनर्जी, अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल, वी. सी. कोतवाल, एफ. एस. नरीमन, के. के. वेणुगोपाल, सोली जे. सोराबजी, ए. बी. दीवान, ओ. पी. मल्होत्रा, टी. आर. अंधारुजिना, महेंद्र एच. शाह, एस. सी. माहेश्वरी, शार्दुल एस. श्रॉफ, श्रीमती पल्लवी एस. श्रॉफ, सिरिल एस. श्रॉफ, अमित देसाई, शशि प्रभु, सुश्री प्रेमा बख्शी, सुरेश ए. श्रॉफ, मैसर्स। जे. बी. दादाचंजी, बी. एच. अंतिया, अस्पी चोने, रविंदर नारायण, 0.सी. माथुर, राजीव साहनी, आर. एफ. नरीमन, श्रीमती ए. के. वर्मा, जोएल पेरेस, मिस रत्ना कपूर, डी. एन. मिश्रा, तलयारखान, ए. के. गांगुली, एच. एस. परिहार, ए. सुब्बा राव, ए. के. चक्रवर्ती, आर. एन. पोद्दार और आर. डी. अग्रवाल

पार्टियाँ।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था चिनाप्पा रेड्डी, जे. उच्च वित्त और व्यापक समस्याओं

राजकोषीय नीति जो वास्तव में प्रांत नहीं है और नहीं हो सकती है

अदालत बहुत ही सरल कारण से कि हमारे पास आवश्यक की कमी है

व्यापक कानूनी से जुड़े प्रश्नों में बदलने की मांग की गईउन्हें न्यायालय की चिंता बनाने के लिए सिद्धांत।

इसी तरह जिसे 'राजनीतिक राजनीतिक' प्रक्रिया कहा जा सकता है

' निगमित लोकतंत्र 'की जांच की मांग की जाती है

हमारे द्वारा कानून के शासन के सिद्धांत का आह्वान करते हुए, जोर देकर

मनमाना राज्य कार्रवाई के खिलाफ नियम पर। का खुलासा

वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलेगा कि कितनी कानूनी सरलता है

अदालतों को समझाने के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, सरलता से, इलाज करने के लिए

वित्त की दुनिया की विविध समस्याएं, मुकदमे के रूप में

मनमाना कार्रवाई के खिलाफ संकट संकेत। तो कॉर्पोरेट दिग्गज करते हैं न्याय के लिए पुकारते हुए हमारे पास आने में संकोच न करें। अदालत का कमरा

उनका युद्ध का मैदान बन जाता है और कॉर्पोरेट लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं

न्याय, निष्पक्षता और जनता के आकर्षक झंडों के नीचे।

ब्याज। हम कॉर्पोरेट दिग्गजों के अधिकार से इनकार नहीं करते हैं

हमारी सहायता के साथ-साथ कोई भी लिलिपुटियन खेत मजदूर या फुटपाथ

हालाँकि हम निश्चित रूप से अपना अधिक खर्च करना पसंद करेंगे।

बाद वाले पर समय और ध्यान दें। हम यह स्वीकार करते हैं कि

कभी-कभी दिग्गजों की लड़ाई की धूल उभर आती है

नया

सिद्धांत, समय के लायक। इस तरह कानून बना है

हाल तक प्रगति कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जनहित याचिका

गेशन और सार्वजनिक सहायता प्राप्त मुकदमे आज कई लोगों पर हावी हो रहे हैं।

अज्ञात क्षेत्र और गूंगे अपनी आवाज़ ढूंढ रहे हैं।

हमारे सामने मामले में, जैसे कि इसमें शामिल वित्तीय दिग्गजों की ताकत के अनुरूप, असंख्य दस्तावेज दायर किए गए थे।

हमारी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में कि हम ऐसा इस ज्ञान के साथ करते हैं कि कतार में लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कम पुरुषों के अधिक योग्य कारणों ने अवरुद्ध कर दिया है और परिणामस्वरूप कतार लंबी हो गई है। प्रस्तुतियों की अवधि और पृष्ठ की अवधि पर एक समय-सीमा लागू करने के लिए शायद समय उपयुक्त है। निर्णय। संक्षिप्त और समयबद्ध मौखिक प्रस्तुतियों द्वारा समर्थित संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियों पर जोर देने के लिए शायद समय उपयुक्त है। यह निश्चित रूप से संक्षिप्त और विनम्र तर्कों और संक्षिप्त और शुद्ध निर्णयों के लिए उपयुक्त समय है। इसी मामले में हमने 28 दिनों तक दलीलें सुनीं और हमारा फैसला 181 पृष्ठों का है और दोनों बहुत छोटे हो सकते थे। हम आशा करते हैं कि हम व्यर्थ में यह उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि यह दुष्चक्र जल्द ही टूट जाएगा और

इस तरह के विशाल मामलों में से यह अंतिम होगा। हम व्यवस्था को उस स्थिति से अलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिसमें यह मौजूदा प्रक्रियाओं द्वारा वर्षों से मजबूर किया गया है। न्यायिक बोझ के बढ़ते बोझ का अब सार्वजनिक अहसास हो गया है। बार का सहयोग भी आने वाला है, हालांकि धीरे-धीरे। द्रास्टिक समाधान आवश्यक हैं। हम उन्हें ढूंढ लेंगे और हम उम्मीद से जल्द परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। इतना पवित्र उपदेश के लिए और अब हमारे मामले पर वापस।

हमें एक पल के लिए भी संदेह नहीं है कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी हमारी जांच की आवश्यकता है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मामले की एकवचन और उल्लेखनीय विशेषता अर्थात् मंच से सिद्धांत नाटकीय व्यक्तित्व की अनुपस्थिति। नाटक के नायक श्री स्वराज पॉल उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही हमारे समक्ष उपस्थित हुए; न ही उनके दलाल और उनके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक, राजा राम भसीन एंड कंपनी। हालाँकि किए गए और विचाराधीन निवेश कई करोड़ रुपये के हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है जैसे कि वे उनके लिए एक बचत की परवाह करते हैं। जाहिर है, श्री स्वराज पॉल, एक विदेशी नागरिक, भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में खुद को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं और उनके दलाल राजा राम भसीन एंड कंपनी के पास अदालत से दूर रहने से खोने के लिए कुछ भी नहीं है और शायद अपने राजकुमार के पक्ष में खड़े होने से हासिल करने के लिए सब कुछ है। ये उनके लिए हमारे सामने उपस्थित होने का विकल्प नहीं चुनने के लिए उत्कृष्ट कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी गैर-उपस्थिति और अस्पष्टता 931

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

अदालत में खामोशी ने निश्चित रूप से मामले को जटिल बना दिया है और भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम को शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि यह उनकी नीतियां, निर्णय और निर्णय थे।

जिन कार्यों पर हमला किया गया था। हालाँकि, हमें स्वराज पॉल और राजा राम भसीन द्वारा अपनाए गए आचरण और रणनीति की कड़ी निंदा करनी चाहिए, जिसे हम निंदनीय मानते हैं। श्री स्वराज पॉल की कंपनियों का नामित बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हमारे सामने पेश हुआ, लेकिन उनकी उपस्थिति से अदालत को कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने खुद को ऐसी दयनीय स्थिति में डाल दिया था। यह शुरू से ही हमारे लिए स्पष्ट था कि अगर बहुत अधिक अग्रिम पंक्ति की युद्ध रणनीति थी, तो काफी अधिक बैक स्टेज 'राजनयिक' युद्धाभ्यास था, जैसा कि वित्तीय दिग्गजों के टकराव के समय उम्मीद की जा सकती है, हालांकि हमें डर है कि दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं था।

न्याय या लोक हित से संबंधित। उन दोनों के लिए अदालत का कमरा उनके युद्ध के लिए सिर्फ एक और अखाड़ा था, सिवाय इसके कि दिग्गजों में से एक ने सावधानीपूर्वक खुद को पर्दे के पीछे पीछे रखा। महाभारत युद्ध की याद दिलाई गई जिसमें अर्जुन ने भीष्म से लड़ते समय शिखंडी को अपने सामने रखा था, ऐसा नहीं है कि इस मामले में न तो योद्धाओं की तुलना भीष्म या अर्जुन से की जा सकती है और न ही भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को सिखंडियों के रूप में डाउनग्रेड किया जा सकता है। लेकिन यह मामला कुछ ऐसे सवाल उठाता है जो सार्वजनिक हित से संबंधित हैं और हम जनहित में लोक हित और प्रशासनिक न्याय के प्रशासन के लिए बहुत चिंतित हैं। हम केवल इसी दृष्टिकोण से मामले में उत्पन्न होने वाले कई प्रश्नों की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, जिसे मौजूदा विश्व आर्थिक प्रणाली के तहत काम करना पड़ता है, ऐसी है कि भारत को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और इसमें से बहुत कुछ इसकी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए है। विकासात्मक गतिविधियाँ। विदेशी मुद्रा के भंडार को अर्जित करना, संरक्षित करना और निर्माण करना आवश्यक हो गया है। इसलिए संसद और कार्यकारी सरकार समय-समय पर देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों को विनियमित करने, संरक्षित करने और सुधारने और आर्थिक विकास के हित में उनका उचित उपयोग करने के लिए कदम उठाती रही है।

देश से। उस उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 अधिनियमित किया गया था। ' विदेशी मुद्रा 'को सेक द्वारा परिभाषित किया गया है। 2 (ज) अधिनियम का अर्थ विदेशी मुद्रा है और इसमें शामिल हैं

" (i) किसी भी विदेशी मुद्रा में देय सभी जमा, क्रेडिट और शेष राशि और कोई भी मसौदा, यात्री चेक, क्रेडिट पत्र और विनिमय पत्र, जो भारतीय मुद्रा में व्यक्त या तैयार किए गए हैं, लेकिन किसी भी विदेशी मुद्रा में देय हैं;

((ख) भारतीय मुद्रा में या विदेशी मुद्रा में, आहरणकर्ता या उसके धारक या किसी अन्य पक्ष के विकल्प पर देय कोई भी लिखत या तो

आंशिक रूप से एक में और आंशिक रूप से दूसरे में।

' 'अधिकृत व्यापारी' को सेक के तहत कुछ समय के लिए अधिकृत व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। 6 विदेशी मुद्रा से निपटने के लिए।

' मालिक 'को सेक द्वारा परिभाषित किया जाता है। 2 (ग) किसी भी प्रतिभूति के संबंध में, जिसमें -

" कोई व्यक्ति जिसके पास प्रतिभूति को बेचने या हस्तांतरित करने की शक्ति है, या जिसकी अभिरक्षा है या जो प्राप्त करता है, चाहे वह अपनी ओर से हो या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, लाभांश या ब्याज, और जिसका उसमें कोई हित है, और जिस मामले में किसी न्यास पर कोई प्रतिभूति रखी जाती है या लाभांश या ब्याज का भुगतान न्यास निधि में किया जाता है, उसमें कोई न्यासी या कोई भी व्यक्ति शामिल है जो प्रतिभूति को बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार रखता है।

न्यास का निष्पादन या किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के साथ या उसके बिना, न्यास या उसकी किसी भी शर्तों को रद्द करना या बदलना, या न्यास के धन के निवेश को नियंत्रित करना।

धारा 3 में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना का प्रावधान है जिसमें प्रवर्तन निदेशक और अन्य शामिल हैं।

अधिकारी।

धारा 6 (1) रिजर्व बैंक को किसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत करने के लिए सक्षम बनाती है। सेक.

6 (2) यह निर्धारित करता है कि क्या अधिकृत किया जा सकता है और सेक। 6 (4) और सेक। 6 (5) अधिकृत विक्रेता के कर्तव्यों को निर्धारित करें।

धारा 8 (1) में प्रावधान है कि रिजर्व बैंक की पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति

अधिकृत विक्रेता विदेशी मुद्रा में सौदा करेगा। Sec.8 (2) प्रदान करता है कि पिछले सामान्य या विशेष को छोड़कर

रिजर्व बैंक की अनुमति से कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई लेन-देन नहीं करेगा जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत मुद्राओं के अलावा अन्य विनिमय दरों पर भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने का प्रावधान हो। धारा 13 (1) में निर्धारित किया गया है कि ऐसी छूट के अधीन, जो निर्दिष्ट की जाए, कोई भी व्यक्ति, सामान्य या एल. आई. सी. के अलावा नहीं होगा।

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

933

रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति, भारत में कोई भी सोना या चांदी या कोई विदेशी मुद्रा या कोई भी भारतीय लाना या भेजना।

मुद्रा। सेक. 13 (2) प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति या रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति की लिखित अनुमति के अलावा, कोई भी सोना, आभूषण या कीमती पत्थर या भारतीय मुद्रा या विदेशी मुद्रा के अलावा कोई अन्य विदेशी मुद्रा भारत से बाहर नहीं ले जाएगा या नहीं भेजेगा।

उसके द्वारा किसी अधिकृत व्यापारी या मुद्रा-परिवर्तक से प्राप्त विनिमय।

धारा 19 (1) (बी) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के अलावा,

किसी भी प्रतिभूति या ऋण को हस्तांतरित करना या प्रतिभूति में किसी भी ब्याज को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को या उसके पक्ष में हस्तांतरित करना।

धारा 19 (4) और (5) जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैं:

" (4) किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति, की अनुमति के अलावा

रिजर्व बैंक

(क) किसी भी रजिस्टर या पुस्तक में प्रतिभूतियों का कोई हस्तांतरण दर्ज करें जिसमें प्रतिभूतियां पंजीकृत हैं या

अंकित यदि उसके पास यह संदेह करने का कोई आधार है कि हस्तांतरण में प्रावधानों का कोई उल्लंघन शामिल हैइस धारा का, या

(ख) किसी भी प्रतिभूति के संबंध में, चाहे वह प्रतिभूति जारी करने या हस्तांतरण के संबंध में हो या अन्यथा, भारत के बाहर कोई पता दर्ज करें, सिवाय उसी देश में ऐसे किसी पते के प्रतिस्थापन के रूप में या किसी ऐसे लेनदेन के उद्देश्य के लिए जिसके लिए इस धारा के तहत अनुमति दी गई है, इस ज्ञान के साथ कि इसमें उक्त पते की प्रविष्टि शामिल है, या

(ग) भारत के बाहर किसी रजिस्टर से किसी भी शेयर का हस्तांतरण करना।

भारत में एक रजिस्टर।

(5) किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भारत में पंजीकृत कंपनी के किसी भी हिस्से का हस्तांतरण भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी विदेशी राज्य के नागरिक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाता है।चाहे वह भारत में निवासी हो या भारत के बाहर निवासी, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] SUPP.3 एस. सी. आर. होगा।

934

वैध जब तक कि इस तरह के हस्तांतरण की पुष्टि रिजर्व बैंक द्वारा इस ओर से किए गए आवेदन पर नहीं की जाती है

हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता "।

धारा 29 (1) जो इस मामले के प्रयोजनों के लिए भी प्रासंगिक है, निम्नानुसार है:

" 29 (1) एस के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। 28 और एस। 47 और किसी भी चीज़ में निहित होने के बावजूद

इस अधिनियम के अन्य प्रावधान याकंपनी अधिनियम, 1956, भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति (चाहे वह भारत का नागरिक हो या नहीं) या एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन भारत में निवासी

है, या एक कंपनी (बैंकिंग कंपनी के अलावा) जो भारत में या भारत में लागू किसी कानून के तहत निगमित नहीं है।

जो गैर-निवासी ब्याज चालीस प्रतिशत से अधिक है, या ऐसी कंपनी की कोई शाखा, रिजर्व की सामान्य या विशेष अनुमति के अलावा नहीं होगी।

बैंक(क) भारत में व्यापार, वाणिज्यिक या औद्योगिक किसी भी गतिविधि को चलाने के लिए एक शाखा, कार्यालय या व्यवसाय के अन्य स्थान की स्थापना करना।

प्रकृति, एक गतिविधि के अलावा जिसके संचालन के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की गई है

सेक के तहत। 28 ; या

((ख) भारत में किसी भी उपक्रम या किसी भी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग को चलाने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के पूरे या किसी भी हिस्से का अधिग्रहण करना या ऐसी किसी कंपनी में भारत में शेयर खरीदना।

धारा 29 (2) अधिनियम के प्रारंभ के बाद धारा के खंड (ए) में उल्लिखित प्रकृति की किसी भी गतिविधि को जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करने का प्रावधान करती है। 29 (1) जो हो रहा था अधिनियम के प्रारंभ में जारी रखा गया, जबकि एस। 29 (4) रखने की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए इसी तरह का प्रावधान करता है

अधिनियम के प्रारंभ के बाद धारा में निर्दिष्ट कंपनी के शेयर। 29 29 ((1 1)) ((ख) जो अधिनियम के प्रारंभ में किसी व्यक्ति द्वारा धारण किए गए थे।

धारा 30 में निर्धारित किया गया है कि कोई भी विदेशी राज्य का नागरिक नहीं है।

रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना

(1) भारत में कोई भी रोजगार लें, या 935

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

((ii) किसी भी पेशे का अभ्यास करें या

किसी भी पर ले जाएँ

भारत में व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय।

धारा 31 किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित करती है, जो देश का नागरिक नहीं है।

भारत या भारत में निगमित नहीं कोई कंपनी या जिसमें गैर-निवासी ब्याज 40 प्रतिशत से अधिक है, जो रिजर्व बैंक की पूर्व सामान्य या विशेष अनुमति के अलावा, भारत में स्थित किसी भी अचल संपत्ति के अधिग्रहण या धारण या हस्तांतरण या बिक्री, बंधक, पट्टा, उपहार, निपटान या अन्यथा निपटान से होता है।

धारा 47 अधिनियम की चोरी में अनुबंधों से संबंधित है। सेक.

47 (1) किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अनुबंध या समझौते में प्रवेश करने से रोकता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संचालन से बचता है या किसी भी तरह से बचाता है। इसके तहत बनाए गए नियम, निर्देश या आदेश। धारा 47 (2) में प्रावधान है कि अधिनियम का कोई भी प्रावधान जो यह अपेक्षा करता है कि कोई काम केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, उस काम को करने के लिए किसी भी समझौते को अमान्य नहीं करेगा यदि यह समझौते की अवधि है कि वह काम तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अनुमति नहीं दी जाती है। जहाँ ऐसा शब्द स्पष्ट नहीं है, वहाँ इसे प्रत्येक अनुबंध में निहित किया जाना है। धारा 47 (3) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि, कुछ निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी भी कार्य को करने के लिए केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता वाले अधिनियम या अनुबंध की किसी भी अवधि के प्रावधानों के अलावा और उसके बावजूद, किसी भी सूर्य की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

धारा 50 में जुर्माना लगाने का प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति

अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है सिवाय कुछ प्रावधानों के

गणना किए गए प्रावधानों के अनुसार, निर्णय प्रवर्तन निदेशक या प्रवर्तन के सहायक निदेशक के पद से कम के अधिकारी द्वारा किया जाना है, जो उस संबंध में विशेष रूप से सशक्त है। धारा 51 जांच और करने की शक्ति प्रदान करती है

न्यायनिर्णायक। धारा 52 अपील के लिए अपील का प्रावधान करती है।

बोर्ड और सेक। 54 उच्च न्यायालय में आगे की अपील के लिए कानून के प्रश्न। धारा 56 अभियोजन के लिए प्रावधान करती है, क्योंकि

इसके तहत दिए गए निर्देश या आदेश। धारा 57 में कहा गया है कि न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफलता या

अपीलीय बोर्ड या उच्च न्यायालय या अनुपालन करने में विफलता

उन अधिकारियों द्वारा जारी किसी भी निर्देश के साथ, एक अपराध

कारावास से दंडनीय। धारा 59 एक अनुमान निर्धारित करती है

अधिनियम के तहत अभियोजन में पुरुषों का अधिकार और उन पर फेंका जाता है

के बोझ का आरोप लगाया, यह साबित करते हुए कि उनके पास कोई दोषी मानसिक 936 नहीं था

[1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभियोजन में आरोपित अधिनियम के संबंध में राज्य। धारा 61 अपराधों के समरूपता का प्रावधान करती है। धारा 61 (1) (ii) अदालत को बाध्य करती है कि वह धारा 56 या 57 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान न ले, सिवाय (ए) प्रवर्तन निदेशक; या (बी) किसी अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के।बल निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत; या (ग) किसी सामान्य या विशेष द्वारा रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी।

आदेश दें। इस प्रावधान के परंतुक में आदेश दिया गया है कि किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए कोई शिकायत नहीं की जाएगी

उसके अधीन बनाया गया अधिनियम, नियम, निर्देश या आदेश जो निषेध करता है। बिना अनुमति के अधिनियम को करना, जब तक कि

पर

अपराध के अभियुक्त को यह दिखाने का अवसर दिया गया है कि उसके पास ऐसी अनुमति थी। धारा 63 धारा 63 के तहत किसी भी उल्लंघन का निर्णय लेने वाले कार्यालय विज्ञापन को सशक्त बनाती है। 51 और धारा के तहत उल्लंघन का प्रयास करने वाला कोई भी न्यायालय। 56 , यदि वह किसी मुद्रा, प्रतिभूति या किसी अन्य को जब्त करने का निर्देश देना उचित समझता है। धन या संपत्ति जिसके संबंध में उल्लंघन हुआ है।

धारा 67 सेक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का इलाज करती है। 13 ,

18 (1) (ए) और 19 (1) (ए) एस के तहत प्रतिबंधों के रूप में। 11 सीमा शुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू करता है

तदनुसार।

धारा 71 (1) यह साबित करने का भार डालती है कि उसके पास था

अधिनियम या नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक अनुमति याउसके तहत दिया गया निर्देश या आदेश जो उसे बिना अनुमति के अधिनियम बनने से रोकता है।

धारा 73 (3) भारतीय रिजर्व बैंक को "देने" में सक्षम बनाती है।

बैंकरों द्वारा अधिकृत विक्रेताओं, मुद्रा-परिवर्तकों, स्टॉक दलालों, उप-धारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा भुगतान करने और अन्य कार्यों को करने के संबंध में निर्देश। (1) सेक. 32 या अन्य

ऐसे व्यक्ति जो रिजर्व बैंक द्वारा कुछ भी करने के लिए अधिकृत हैं

उनके व्यवसाय के दौरान इस अधिनियम का अनुसरण, जैसा कि दिखाई देता है

इसे सुरक्षित करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन होना

इस अधिनियम और किसी भी नियम के प्रावधानों का अनुपालन,

इसके तहत दिए गए निर्देश या आदेश।

धारा 75 केंद्र सरकार को देने में सक्षम बनाती है और

सामान्य या विशेष निर्देशों का पालन करने के लिए रिजर्व बैंक

पूर्व ठीक सोच सकता है।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

937

धारा 76 के तहत केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक से कोई अनुमति या लाइसेंस देने की आवश्यकता होती है। अधिनियम, निम्नलिखित सभी या किसी भी कारक को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् -

((i) विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण

देश को;

((ii) देश को उपार्जित होने वाली सभी विदेशी मुद्रा

उचित रूप से गणना की गई;

((ग) देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का उपयोग आम भलाई के लिए किया जाता है; और

((iv) परिस्थितियों जैसे अन्य प्रासंगिक कारक

मामले की आवश्यकता हो सकती है।

धारा 79 केंद्र सरकार को आम तौर पर और विशेष रूप से विभिन्न निर्दिष्ट नियमों को बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

उद्देश्य।

सेक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। 79 एफ. ई. आर. ए. के गैर-निवासी (बाहरी) खाता नियम, 1970 नामक नियम बनाए गए हैं, नियम 3 नियमों के प्रावधानों के अधीन, भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत में एक अधिकृत व्यापारी के साथ खाता खोलने और बनाए रखने में सक्षम बनाता है, जिसे गैर-निवासी (बाहरी) खाता कहा जा सकता है। नियम 4 (1) में निर्धारित किया गया है कि उसमें उल्लिखित राशियों के अलावा कोई भी राशि अनिवासी (बाहरी) खाते में जमा नहीं की जाएगी। इनमें से एक है 'भारत के बाहर से खाताधारक द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भेजी गई कोई भी राशि जो एक अनिवासी (बाहरी) खाते में जमा की जा सकती है'। नियम 4 (4) में प्रावधान है कि शेयरों, प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के रूप में उपार्जित राशि

या भारत में रखी गई जमा राशि, गैर-निवासी बाहरी खाते में तब तक जमा नहीं की जाएगी जब तक कि कुछ शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं। शर्तों में से एक यह है कि खाताधारक ऐसे शेयरों, प्रतिभूतियों या जमाओं का पंजीकृत धारक है। एक अन्य शर्त यह है कि खाताधारक ने प्रमाण पत्र जमा कर दिए हैं।एक अधिकृत विक्रेता के साथ शेयरों के संबंध में लिखित रूप में एक वचन पत्र के साथ कि वह किसी भी शेयर का निपटान नहीं करेगा, सिवाय इसके कि उसकी पूर्व मंजूरी के।

रिजर्व बैंक। कुले 5 में आगे यह निर्धारित किया गया है कि नियम 4 (1) में निर्दिष्ट कोई भी राशि गैर-निवासी (बाहरी) खाते में तब तक जमा नहीं की जाएगी जब तक कि रिजर्व बैंक गैर-निवासियों द्वारा भारत में रखे गए धन के प्रेषण की अनुमति देने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, 938 देता है।

इस संबंध में अनुमति। नियम 6 में प्रावधान है कि भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति जो अनिवासी (बाहरी) खाता खोलना चाहता है, वह इस संबंध में एक अधिकृत विक्रेता को आवेदन करेगा। अधिकृत विक्रेता, जब तक कि रिजर्व बैंक का कोई सामान्य या विशेष आदेश इस तरह का निर्देश नहीं देता है, ऐसे प्रत्येक आदेश का उल्लेख करेगा।

विवरण के साथ रिजर्व बैंक को आवेदन।

रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित विनिमय नियंत्रण नियमावली

भारत

इसमें विभिन्न वैधानिक और प्रशासनिक शामिल हैं।

समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश, सलाहकार राय, टिप्पणियां, टिप्पणियाँ, स्पष्टीकरण आदि। पैराग्राफ 24.1 (1) में कहा गया है,

" भारत के गैर-निवासियों द्वारा भारत में निवेश

राष्ट्रीयता या मूल एक अलग समूह के अधीन है

उन्हें व्यापक निवेश देने के लिए नियम

अवसर। आम तौर पर निवेश की अनुमति स्वतंत्र रूप से दी जाती है यदि प्रस्तावित निवेश अवांछनीय प्रकृति का नहीं है, लेकिन इस शर्त के अधीन है कि निवेश की गई पूंजी और उस पर अर्जित आय के प्रत्यावर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। गैर-निवासी निवेशक को भी छोड़ने के लिए सहमत होने का वचन देना आवश्यक है।

प्रत्यावर्तन के लाभ। के साथ निवेश करें

केवल प्रतिबंधित क्षेत्रों में ही प्रत्यावर्तन लाभों की अनुमति है।

कुछ शर्तों के अधीन क्षेत्र। योजनाएँजिनके अंतर्गत ऐसे निवेशों की अनुमति है -

इस अध्याय में समझाया गया है।

हालांकि, अनुच्छेद 24.1 (11) में कहा गया है

" भारत में विदेशी निवेश भी इसके अधीन है -

विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से विनियमनविदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973। सेक. 19

प्रतिभूतियों को जारी करना और उनके पक्ष में हस्तांतरण करना

गैर-निवासियों के लिए, सेक। 29 गैर-निवासियों द्वारा व्यवसाय के स्थान की स्थापना को संचालित करना

व्यापार, वाणिज्यिक या औद्योगिक गतिविधियाँ या ऐसे उपक्रम या शेयरों का अधिग्रहण करना

भारत में कंपनियाँ और सेक। 31 अधिग्रहण को नियंत्रित करना,

भारत में अचल संपत्ति का निपटान आदि। लेकिन

एक बार जब सरकार द्वारा अपनी विदेशी निवेश और औद्योगिक नीति के तहत विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है,

संबंधित धाराओं के तहत आवश्यक अनुमतियाँ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 अधिक या अधिक है।

कम स्वचालित रूप से जारी किया गया "।

अनुभाग 24A.1 एल. आई. सी. v प्रदान करता है।

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

939

" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (1) (बी) के संदर्भ में, भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, फर्म हो या कंपनी (जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 (1) (बी) के अंतर्गत नहीं आता हो)।

बैंकिंग कंपनी) भारत के बाहर निगमित हो सकती हैव्यापार करने वाली किसी भी कंपनी के शेयर प्राप्त करना,

भारत में वाणिज्यिक या औद्योगिक गतिविधि बिना रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति। साथ ही, सेक के तहत। 19 (1) (बी) और अधिनियम के 19 (1) (डी) में किसी भी प्रतिभूति (जिसमें शेयर शामिल हैं) का हस्तांतरण और जारी करना।

सरकार, भारतीय इकाई न्यास की इकाइयाँ और भारत सरकार के राष्ट्रीय बचत/योजना प्रमाण पत्र (देखें)अनुच्छेद 24B.2)। अन्य सभी निवेश आवश्यक हैं।

रिजर्व बैंक की विशिष्ट अनुमति "।

पैराग्राफ 28A.4 में कहा गया है, -

" अधिकृत विक्रेता स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों के नाम पर एक अनिवासी (बाहरी) खाता खोल सकते हैं।

भारतीय राष्ट्रीयता या मूल, बाहर का निवासीभारत, इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई धनराशि हस्तांतरित की जाती है।

देश से अनुमोदित तरीके से भारत को

भावी खाताधारक के निवासी या

अन्य विदेशी देश यदि

खाताधारक का निवास स्थान और देश

कौन सा प्रेषण प्राप्त होता है दोनों बाहरी रूप में होते हैंसमूह "।

पैराग्राफ 28A.4 (111) हालांकि, निर्धारित करता है कि फर्म, कंपनियां और अन्य कॉर्पोरेट निकायों के साथ-साथ संस्थान और

विदेशों में रहने वाले संगठन भारत में अनिवासी (बाहरी) खाते खोलने के पात्र नहीं हैं। अनुच्छेद 28. ए 8 (11) में कहा गया है कि सेक के तहत। 29 (1) ((b) विदेशी मुद्रा

कंपनियाँ। इसलिए भारतीय कंपनियों के शेयरों में अनिवासी (बाहरी) खाता निधियों के निवेश की अनुमति इसके बिना नहीं है। रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति।

940

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के अनिवासी व्यक्तियों को निवेश करने के लिए आकर्षित करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से

भारतीय कंपनियों के शेयरों, भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्णय लिया और एक

सरकार को 27 फरवरी, 1982 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 अप्रैल, 1982 को जारी परिपत्र संख्या 9 में शामिल किया गया था। सेक के तहत। 73 (3) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। परिपत्र के पैराग्राफ 2 में बताया गया है कि आगे प्रदान करने के लिए

भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के गैर-निवासियों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश के लिए प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान करने के लिए मौजूदा सुविधाओं को उदार बनाया गया था और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा किया गया था। जैसा कि परिपत्र के बाद के पैराग्राफ में समझाया गया है, इसे सरल बनाया गया है। पैराग्राफ 3 प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश से संबंधित है जबकि पैराग्राफ 4 निवेश से संबंधित है

प्रत्यावर्तन लाभ। पैराग्राफ 4 (ए) में प्रावधान है कि उदारीकृत नीति के तहत, भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के गैर-निवासी को भारत में स्टॉक एक्सचेंजों पर उद्धृत शेयरों में पोर्टफोलियो निवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें लोगों के प्रत्यावर्तन का पूरा लाभ होगा।

निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय बशर्ते कि (ए) शेयर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदे जाते हैं, (बी) किसी एक कंपनी में शेयरों की खरीद प्रत्येक अनिवासी निवेशक रुपये से अधिक न हो। अंकित मूल्य में एक लाख रुपये या कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का एक प्रतिशत, जो भी कम हो, और (ग) ऐसे निवेशों के लिए भुगतान या तो विदेश से नए प्रेषण द्वारा या निवेशक के खाते में रखे गए धन से किया जाता है।

भारत में किसी बैंक में निवासी (बाहरी) खाता/एफ. सी. एन. आर. खाता। यह आगे प्रावधान करता है कि रिजर्व बैंक अनुमति देगा भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अपने अनिवासी ग्राहकों की ओर से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर खरीदने के लिए किसी भी विदेशी मुद्रा के साथ सौदा करने के लिए अधिकृत नामित बैंक, विषय, अन्य बातों के साथ-साथ, उल्लिखित सीमाओं और शर्तों के अनुसार। पैराग्राफ 5 मौजूदा नीति में एक और महत्वपूर्ण छूट प्रदान करता है और "उपरोक्त पैराग्राफ 3 और 4 में उल्लिखित प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश की सुविधाओं के पूरे सरगम को अब विदेशी कंपनियों, साझेदारी फर्मों, ट्रस्टों, समितियों और अन्य कॉर्पोरेट निकायों तक विस्तारित किया जाएगा जो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। इस तरह के प्रमुख स्वामित्व को निर्धारित करने के लिए मानदंड यह है कि इन संस्थाओं का कम से कम 60 प्रतिशत स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के पास होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं के लिए इस संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा

विदेशी लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट/प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार से निर्धारित फॉर्म ओ. ए. सी., उनके आवेदनों के साथशेयरों में निवेश, भारतीय रिजर्व बैंक को या तो विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत नामित बैंकों के माध्यम से या नई निर्गमों की पेशकश करने वाली भारतीय कंपनियों के माध्यम से, जैसा भी मामला हो।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

941

प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश के लिए नामित बैंकों की अनुमति के लिए उन संस्थाओं से आवेदनों को नियंत्रक, विनिमय नियंत्रण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय (विदेशी निवेश) को आर. पी. सी. फॉर्म जमा करना आवश्यक है।

प्रभाग), बॉम्बे। पैराग्राफ 7 में भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों और मुख्य रूप से उनके स्वामित्व वाली विदेशी कंपनियों आदि द्वारा भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया गया है और इसके लिए अधिकृत विक्रेताओं को कुछ क्षेत्रों में अपने काम को केंद्रीकृत करके त्वरित और कुशल सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है।

उन स्थानों पर चयनित शाखाएँ जहाँ स्टॉक एक्सचेंज की सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध हैं। पैराग्राफ 8 गैर-निवासी निवेशकों को शेयरों/प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री की व्यवस्था करने के लिए उचित पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ अपने एजेंट के रूप में भारत में निवासियों (अधिकृत डीलरों के अलावा) को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है। ऐसे एजेंटों में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज दलाल शामिल होंगे। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि 'ऐसे निवेशकों की ओर से शेयरों में निवेश की अनुमति' हालांकि, यह विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत नामित बैंकों को दिया जाएगा क्योंकि ये बैंक प्रासंगिक विनिमय नियंत्रण आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

निर्दिष्ट बैंक और निवेशक एजेंटों के बीच उचित समन्वय और समझ संभालने के लिए आवश्यक होगी।

निवेश प्रक्रियाएँ कुशलता से '। पैराग्राफ 11 निर्धारित करता है

अन्य मामलों के अलावा, नामित बैंकों का कर्तव्य

" अलग से एक उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए

प्रत्येक निवेशक के कारण प्रत्यावर्तन लाभों के साथ और प्रत्यावर्तन लाभों के बिना शेयरों में किए गए निवेश, जिसमें प्रासंगिक विवरण शामिल हैं -

शेयर प्रमाणपत्रों की संख्या और विशिष्ट

शेयरों की संख्या। इसी तरह, नामित शाखाएँ

अधिकृत विक्रेताओं को एक व्यवस्थित और

शेयरों का अद्यतित निवेशक-वार रिकॉर्ड

स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से उनके द्वारा खरीदा गया

उनके विदेशों की ओर से स्वदेश वापसी के आधार पर

भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के ग्राहक ताकि वे यह सुनिश्चित करने में सक्षम हैं कि प्रत्येक अनिवासी निवेशक द्वारा किसी एक कंपनी में शेयरों की खरीद रुपये से अधिक न हो। 1 अंकित मूल्य में एक लाख रुपये या कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी का 1 प्रतिशत, जो भी कम हो।

परिपत्र संख्या 9 के बाद अप्रैल का परिपत्र No.10 आया।

विदेशी मुद्रा। इस परिपत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि विदेशी कंपनियाँ, साझेदारी फर्म, समितियाँ, अन्य 942

कॉरपोरेट निकाय और विदेशी न्यास जिन्हें परिपत्र संख्या 9 द्वारा तैयार की गई निवेश योजना के लाभ दिए गए थे, कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के स्वामित्व में हैं या जिनमें लाभकारी ब्याज का कम से कम 60 प्रतिशत (न्यासों के मामले में) ऐसे व्यक्तियों के पास अपरिवर्तनीय रूप से है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी कंपनी/फर्म/सोसायटी

में स्वामित्व हित या भारतीय व्यक्तियों द्वारा आयोजित न्यास में अपरिवर्तनीय लाभकारी हित राष्ट्रीयता/मूल 60 प्रतिशत से कम नहीं है, अधिकृत डीलरों को खाता खोलने के फॉर्म के साथ, एक विदेशी लेखा परीक्षक/चार्टर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

ए. डी. के साथ संलग्न प्रपत्र ओ. ए. सी. में लेखाकार/प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार। (M.A.Series) 1982 का परिपत्र सं. 9। ' खाताधारक को वार्षिक आधार पर अधिकृत विक्रेता को इस तरह का प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपरोक्त व्यक्तियों का स्वामित्व/लाभकारी ब्याज 60 प्रतिशत के स्तर पर या उससे अधिक बना रहे।

28 अगस्त, 1982 के परिपत्र संख्या 15 द्वारा, रिजर्व बैंक ने 14 अप्रैल, 1982 के परिपत्र संख्या 9 में आंशिक रूप से ढील दी।

रुपये की मौद्रिक सीमा को हटाना। प्रत्यावर्तन आधार पर शेयरों में पोर्टफोलियो निवेश पर एक लाख रुपये। लेकिन कंपनी की चुकता पूंजी के एक प्रतिशत की सीमा को बरकरार रखा गया।

10 दिसंबर, 1982 के परिपत्र संख्या 27-27 के अनुसार, यह था

निर्धारित किया गया,

" जहां भारतीय राष्ट्रीयता के गैर-निवासियों द्वारा भारत में स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों/डिबेंचरों की खरीद/बिक्री के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाती है /

मूल रूप से, लेन-देन सत्तारूढ़ बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए जैसा कि सामान्य बोली और प्रस्ताव विधि द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के तल पर निर्धारित किया जा सकता है। केवल "।

16 मई, 1983 को रिजर्व बैंक ने 'भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासी' पोर्टफोलियो निवेश को स्पष्ट और संशोधित किया।

योजना 'निम्नलिखित तरीके से: परिपत्र संख्या 9 का उल्लेख करते हुए जिसने विदेशी कंपनियों, भागीदार जहाज फर्मों, समितियों और अन्य निगमित निकायों को पोर्टफोलियो योजना का विस्तार किया, जो उनके स्वामित्व में थे।

भारत के गैर-निवासियों द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक

राष्ट्रीयता/मूल और विदेशी न्यासों के लिए जिनमें लाभकारी ब्याज का कम से कम 60 प्रतिशत अपरिवर्तनीय रूप से ऐसे न्यासों के पास था।

व्यक्तियों, परिपत्र संख्या 12 दिनांक 16 मई, 1983 ने एक समग्र अधिरोपित किया

(i) 943 की कुल चुकता पूंजी का 5 प्रतिशत

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

संबंधित कंपनी और (ii) परिवर्तनीय डिबेंचर निर्गम की प्रत्येक श्रृंखला के कुल भुगतान मूल्य का 5 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो। 5 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने और निगरानी करने के उद्देश्य से कटौती की तारीख 2 मई, 1983 निर्धारित की गई थी, जिस तारीख को संसद में नीति की घोषणा की गई थी। यह स्पष्ट किया गया कि 5 प्रतिशत से अधिक के इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए रिजर्व बैंक की पूर्व और विशिष्ट मंजूरी की आवश्यकता होगी। अनुमति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और यह भी प्रावधान किया गया था कि जहां गैर-निवासी निवेशक की ओर से 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश किया जाना है, जिसने निर्धारित प्रपत्र में पहले रिजर्व बैंक को कोई आवेदन जमा नहीं किया है, तो ऐसे निवेश के लिए प्रारंभिक आवेदन उचित प्रपत्र में इक्विटी शेयरों का विवरण देते हुए किया जाना चाहिए।

क्रय किए जाने वाले परिवर्तनीय ऋणपत्र। 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा की निगरानी के लिए परिपत्र संख्या 12 निर्धारित प्रक्रिया का अनुच्छेद 3। अधिकृत डीलरों को अपने लिंक कार्यालयों के माध्यम से रिजर्व बैंक को अपनी नामित शाखाओं द्वारा की गई इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल खरीद और बिक्री (कंपनी वार) का एक समेकित विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। दैनिक विवरणों को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना था और अगले कार्य दिवस पर नियंत्रक को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना था। यह आगे प्रदान किया गया था "सभी खरीद और बिक्री लेनदेन जिनके लिए दलाल के रूप में इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को प्राप्त करने या स्थानांतरित करने के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता की गई है।

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज दलालों द्वारा जारी अनुबंध नोटों को दैनिक विवरण में शामिल किया जाना चाहिए, भले ही वास्तविक डिलीवरी प्रभावित हुई हो या नहीं। यह भी प्रावधान किया गया था कि 5 प्रतिशत की प्रभावी रूप से निगरानी की जाए।सीमा, रिजर्व बैंक, जैसे ही कुल 4 प्रतिशत की सीमा तक पहुंच जाएगा, के लिंक कार्यालयों को इस तथ्य को सूचित करेगा

बम्बई में अधिकृत विक्रेता। इसके बाद लिंक कार्यालयों को अगले 15 दिनों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदे जाने वाले प्रस्तावित इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल संख्या और मूल्य देना आवश्यक था। इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए मंजूरी रिजर्व बैंक द्वारा खरीद को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी।

जिन सभी अधिकृत विक्रेताओं से सूचना प्राप्त हुई है, उनके द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत ऐसा करने का प्रस्ताव है।

19 सितंबर, 1983 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक और परिपत्र (18) जारी किया गया था जिसमें सभी अधिकृत विक्रेताओं को सलाह दी गई थी।

विदेशी मुद्रा कि सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया

14 अप्रैल, 1982 के परिपत्र संख्या 9 द्वारा विदेशी कंपनियां आदि भी उपलब्ध थीं, जहां ऐसे विदेशी निकाय अप्रत्यक्ष रूप से भी कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक ऐसे 944 द्वारा स्वामित्व में थे।

[1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासी। जो आवश्यक था, वह यह था कि लाभकारी हित का अंतिम स्वामित्व

कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक विदेशी निकाय भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के एक या अधिक अनिवासी व्यक्तियों के हाथों में होने चाहिए।

सभी परिपत्रों का शुद्ध परिणाम यह था कि गैर-निवासी

भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के साथ-साथ विदेशों के व्यक्ति

कम्पनियाँ, साझेदारी फर्म, सोसायटी, न्यास और अन्य निगमित निकाय जो लाभकारी हित के स्वामित्व में थे या जिनमें

भारतीय के अनिवासी व्यक्तियों में

निहित

कम से कम 60 प्रतिशत की राष्ट्रीयता/मूल भारतीय कंपनियों के शेयरों में प्रत्यावर्तन के आधार पर ऐसी भारतीय कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के एक प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने के हकदार थे, बशर्ते कि कुल मिलाकर

इस तरह के पोर्टफोलियो निवेश की सीमा प्रति वर्ष 5 की सीमा से अधिक नहीं थी।

प्रतिशत। यह मायने नहीं रखता था कि निवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। जरूरी बात यह थी कि 60 प्रतिशत

भारतीय मूल के गैर-निवासी व्यक्ति। दिलचस्प है। हालांकि अधिग्रहण पर एक प्रतिशत की सीमा लगाई गई थी

प्रत्येक निवेशक द्वारा शेयरों की राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं था

अलग से एक प्रतिशत की सीमा तक शेयरों का अधिग्रहण

एक ही परिवार के प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक व्यक्ति द्वारा

एक ही परिवार (समूह) की कंपनी। इस तरह के किसी भी प्रतिबंध के अभाव में, कोई भी गैर-निवासी निर्धारित करता है कि

एक भारतीय कंपनी को अस्थिर करके ऐसा किया जा सकता है

विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों का संयोजन जिनमें से प्रत्येक एक प्रतिशत की खरीद के लिए अलग से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

एक भारतीय कंपनी के शेयर। प्राधिकृत प्राधिकारी

उदाहरण के लिए, अनुमति देने की अनुमति बी को अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता है जिसने अपने अधिकार में अनुमति के लिए आवेदन किया है।

केवल इस आधार पर कि उसके पिता को अनुमति दी गई है

ए. इसी तरह कंपनी सी को अनुमति देने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

जिसमें डी एक अनिवासी भारतीय के पास 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है और ई एक अन्य अनिवासी भारतीय के पास 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

इस आधार पर कि कंपनी एल जिसमें 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है

पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा?यदि डी के पास सी और एल दोनों कंपनियों के 60 प्रतिशत शेयर हैं?

आधा दर्जन विदेशी कंपनियों की अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है जिनमें

भारतीय मूल के दर्जन भर अनिवासी व्यक्तियों के पास हिस्सेदारी हैअलग-अलग अनुपात लेकिन कुल मिलाकर 60 प्रति से अधिक

आवेदन करने वाली विदेशी कंपनियों के शेयरों का प्रतिशत

भारतीय कंपनी में शेयर खरीदने की अनुमति। कर सकते हैं।उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया जाए? क्या रिजर्व बैंक 945 के बारे में चिंतित है

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

विदेशी कंपनियों के शेयरधारकों की व्यक्तिगत पहचान या शेयरधारकों की राष्ट्रीयता या मूल के साथ? क्या रिजर्व बैंक को केवल त्वचा के रंग के बारे में चिंता करनी चाहिए, न कि विदेशी कंपनी के शेयरधारक के व्यक्तित्व के बारे में? हम बाद में इस सवाल पर वापस लौटेंगे। जाहिर है, एक प्रतिशत नियम गैर-निवासियों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों के बड़े पैमाने पर अधिग्रहण और उनके संभावित अस्थिरता को रोकने के लिए पेश किया गया था। इसके अलावा, स्पष्ट रूप से यह नियम एक व्यर्थ अभ्यास था क्योंकि यह वांछित परिणाम देने में असमर्थ था। स्पष्ट रूप से इसलिए एक बेहतर समाधान खोजना पड़ा और यह '5 प्रतिशत के कुल' नियम द्वारा पाया गया। यह स्वचालित रूप से कुल बाहरी स्वामित्व को सीमित कर देगा और अस्थिरता को प्रभावी ढंग से रोक देगा। बेशक, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करना अभी भी आवश्यक होगा, विशेष रूप से सेक की आवश्यकता। 29 कंपनी के शेयरों को भारत में खरीदने के लिए रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति का प्रावधान करने वाले अधिनियम का। हालांकि इस योजना के तहत अंतिम प्राधिकरण रिजर्व बैंक है, इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रेषण और निवेश की निगरानी नामित बैंक द्वारा की जानी है, जो अधिकृत विक्रेता है।

हमारे समक्ष दो प्रमुख प्रश्नों पर बहस की गई कि क्या अनुभाग द्वारा अनुध्यात अनुमति पर विचार किया गया था। 29 पूर्व अनुमति थी या

इस मामले में राष्ट्रीयता/मूल का कोई भी उल्लंघन शामिल हैएफ. ई. आर. ए. या अनिवासी निवेश योजना। सवाल कैसे उठते हैं, यह समझने के लिए यहां कुछ तथ्यों को बताना आवश्यक है।

अनिवासी पोर्टफोलियो निवेश योजना का लाभ उठाने और एस्कॉर्ट्स के शेयरों में निवेश करने की इच्छा। एक भारतीय कंपनी लिमिटेड, तेरह विदेशी कंपनियां, जिनमें से बारह के शेयर 100 प्रतिशत स्वामित्व में थे और तेरहवें के शेयर कपारो ग्रुप लिमिटेड के 98 प्रतिशत स्वामित्व में थे, ने पंजाब नेशनल बैंक को अपना बैंकर (अधिकृत) नामित किया।

विक्रेता) और मेसर्स। राजा राम भसीन एंड कंपनी इस तरह के निवेश के उद्देश्य से उनके दलालों के रूप में। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि कपारो ग्रुप लिमिटेड के 61.6 प्रतिशत शेयर स्वराज पॉल फैमिली ट्रस्ट के पास हैं, जिसके सौ प्रतिशत लाभार्थी स्वराज पॉल और उनके परिवार के सदस्य हैं।

भारतीय मूल के निवासी व्यक्ति। उनके नामित बैंकर, पंजाब नेशनल बैंक, ई. सी. ई. हाउस ब्रांच ने अपने 4 मार्च, 1983 के पत्र द्वारा, लेकिन 9 मार्च, 1983 को भेजा और 12 मार्च, 83 के एक अन्य पत्र द्वारा नियंत्रक, भारतीय रिजर्व बैंक, विनिमय नियंत्रण विभाग को संबोधित किया और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] SUPP.3 एस. सी. आर. का अनुरोध किया।

रिजर्व बैंक प्रत्येक तेरह के नाम पर अनिवासी बाहरी खाते खोलने के लिए अपनी मंजूरी देगा। राजा राम भसीन एंड कंपनी, स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, दिल्ली स्टॉक एंड शेयर डिपार्टमेंट, दिल्ली के सदस्य की एजेंसी के माध्यम से भारत में निवेश संचालन के उद्देश्य से, पहले पत्र में नामित तीन और दूसरे पत्र में नामित दस कंपनियाँ। ये पत्र प्राप्तकर्ता को 14 और 18 मार्च को प्राप्त हुए थे। पत्रों में यह उल्लेख किया गया था कि प्रस्तावित खाते सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से प्रेषण द्वारा 'प्रभावित' होंगे और डेबिट और क्रेडिट की अनुमति केवल गैर-निवासियों द्वारा निवेश के लिए योजना में निहित योजना के संदर्भ में दी जाएगी। पहला पत्र (1) कपारो टी कंपनी लिमिटेड, यूके, (2) एम्पायर प्लांटेशन एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यूके और (3) असम फ्रंटियर टी होल्डिंग पीएलसी, यूके के संबंध में था, जबकि दूसरा पत्र (1) कपारो इन्वेस्ट मेंट्स लिमिटेड, (2) कपारो प्रॉपर्टीज लिमिटेड, (3) स्टील सेल्स लिमिटेड, (4) अटलांटिक मर्चेंट्स लिमिटेड, (5) बुकानन लिमिटेड, (6) साइमोर शिपिंग लिमिटेड, (7) कपारो ग्रुप लिमिटेड, (8) नेचुरल गैस ट्यूब लिमिटेड, (9) सिंगल होल्डिंग्स लिमिटेड और (10) डीबोर्न होटल टॉर्की लिमिटेड के संबंध में था। प्रत्येक कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित आर. पी. सी. प्रपत्र और कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित ओ. ए. सी. प्रपत्र दोनों पत्रों के साथ थे। आर. पी. सी. के प्रत्येक प्रपत्र में उल्लेख किया गया है कि कंपनी को इंग्लैंड में निगमित किया गया था और कंपनी का 61.6% भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के स्वामित्व में था। प्रत्येक रूप में ओ. ए. सी. में लेखा परीक्षक ने प्रमाणित किया कि भारतीय राष्ट्रीयता/और/या मूल के व्यक्तियों द्वारा कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतिशत 61.6% था और यह कि शेयरधारक का नाम 'स्वामित्व कंपनी में उनके हित के कारण स्वराज पॉल फैमिली ट्रस्ट' था। लेखा परीक्षकों ने प्रमाणित किया कि व्यक्तियों का स्वामित्व हित

कंपनी में भारतीय मूल प्रमाण पत्र की तारीख तक ब्याज के कुल स्वामित्व का 61.6% था और यह कि पारिवारिक न्यास में लाभकारी हित अपरिवर्तनीय रूप से आयोजित किया गया था

भारतीय मूल के व्यक्ति। 23 अप्रैल, 83 को पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के विनिमय नियंत्रण विभाग के नियंत्रक को संबोधित किया और उनके पूर्व पत्रों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

दिनांक 4 और 12 मार्च, 1983, जो 13 कंपनियों से संबंधित आर. पी. सी. और ओ. ए. सी. प्रपत्रों के साथ थे और रिजर्व बैंक ने कहा कि निवेश संचालन कंपनी राजा राम भसीन एंड कंपनी, शेयर एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के सदस्य के माध्यम से किया जा रहा था। रिजर्व बैंक को यह भी सलाह दी गई थी कि कैपारो ग्रुप लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी से 9.3.83,12.4.83,13.4.83 और 23.3.83 पर रुपये 1,35,36,000, रु. 2,36,59,000, Rs.76,35,000 और रु. 1,31,38,681 के बराबर राशि के चार प्रेषण प्राप्त हुए थे। 13 पी। पंजाब नेशनल बैंक ने भी पत्र में उल्लेख किया है कि एल. आई. सी. बनाम.

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

हम इस मोड़ पर यह उल्लेख करना चाहते हैं कि 4 मार्च, 12 मार्च और 23 अप्रैल, 1983 के पत्रों के साथ-साथ पंजाब नेशनल बैंक, ई. सी. ई. हाउस शाखा द्वारा रिजर्व बैंक को लिखे गए अन्य सभी पत्र रुपये के समतुल्य एल. आई. डी. 1 के प्रेषण के बारे में पूरी तरह से चुप हैं। 19,63,000 श्री स्वराज पॉल ने श्री स्वराज पॉल के नाम पर एन. आर. ई. खाता खोलने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग शाखा को 28.1.1983 पर लिखा। कहा जाता है कि प्रेषण श्री स्वराज पॉल के साथ चर्चा के बाद किया गया थापंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे निर्देश क्या थे। हमें बताया गया है कि जब उच्च न्यायालय में रिट याचिका पर बहस की जा रही थी तो केबल और प्रेषण से संबंधित पत्र बार के न्यायाधीशों को सौंप दिए गए थे। हम यहां यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि 26 जनवरी, 83 को तीन कपारो कंपनियों, असम फ्रंटियर टी होल्डिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कपारो टी कंपनी लिमिटेड और एम्पायर प्लांटेशन एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने तीन समान कंपनियों को संबोधित किया।

राजा राम भसीन एंड कंपनी को पत्र जिसमें दलाल को दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों को प्रत्यावर्तन के आधार पर सर्वोत्तम बाजार मूल्य पर खरीदने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक पत्र में उल्लेख किया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग को संबोधित एक पत्र जिसमें Rs.20 लाख के अग्रिम भुगतान को अधिकृत किया गया था, संलग्न किया गया था। शेयरों की डिलीवरी बाजार से प्राप्त होने पर दी जा सकती थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि बैंक वितरित किए गए शेयरों के पूर्ण खरीद मूल्य का भुगतान करेगा और शेयरों की अंतिम डिलीवरी पर Rs.20 लाख के अग्रिम को समायोजित किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इन पत्रों को एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी द्वारा भेजा गया था। पंजाब नेशनल बैंक को लिखे गए पत्रों के साथ पत्र हमारे सामने नहीं रखे गए थे और

पंजाब नेशनल बैंक के वकील ने इस बात से इनकार किया कि पंजाब नेशनल बैंक को कभी भी ऐसा कोई पत्र नहीं मिला था। जो भी हो, हमारे पास ऐसी परिस्थिति है कि एल 1,30,000 का प्रेषण था

निस्संदेह बनाया गया। पंजाब नेशनल बैंक की संसद मार्ग शाखा को, जो पंजाब नेशनल शाखा की ईसीई हाउस शाखा के लिए अज्ञात या किसी भी तरह से अज्ञात है। हमारे समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह संकेत नहीं मिलता है कि एल 1,30,000 की राशि के साथ क्या किया गया था और न ही यह संकेत देता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को पंजाब द्वारा इस प्रेषण के बारे में कभी सूचित किया गया था।

नेशनल बैंक। ऐसा प्रतीत होता है कि पैसा एक वसीयत-ओ-द-विस्प की तरह आया और गायब हो गया।

पंजाब सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1985] SUPP.3 S. C. R. के लिए विद्वान वकील।

948 नेशनल बैंक ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पंजाब नेशनल बैंक की ईसीई हाउस शाखा, जो एनआरई खातों और कपारो समूह की कंपनियों द्वारा शेयरों की खरीद की निगरानी कर रही थी, को संसद मार्ग शाखा द्वारा प्राप्त प्रेषण के बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, दाहिने हाथ को पता नहीं था कि बायां हाथ क्या कर रहा था। यह आश्चर्य की बात है कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा से संबंधित

मामले में पंजाब नेशनल बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत एक अधिकृत डीलर को इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम करना चाहिए था। और जो कुछ भी जांच की आवश्यकता है

भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक की जानकारी के बिना L 1,20,000 की राशि का गायब होना या खर्च करना एक ऐसा मामला है जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है। किसी को भी कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अगर उसने ऐसा किया है, और इस विचित्र तरीके से इससे बच निकलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

राजा राम भसीन एंड कंपनी द्वारा दायर किए गए बयानों से पता चलता है कि 9.3.1983 से पहले, पहले प्रेषण की तारीख का खुलासा किया गया था

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को राजा राम भसीन एंड कंपनी ने मंगला एंड कंपनी से एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयर खरीदे थे, जिनकी कीमत Rs.33,40,865.00 थी। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि पंजाब नेशनल बैंक और रिजर्व बैंक के बीच हुए पत्राचार के अनुसार, प्रेषण 9.3.83,24.3.83,12.4.83,15.4.83,28.4.83 और 28.4.84 पर किया गया था। पत्राचार में, 9.3.83 से पहले किए गए किसी भी प्रेषण का कोई उल्लेख नहीं है। हम यहां यह भी देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से कैपारो समूह की तीन कंपनियों द्वारा शेयरों में निवेश की अनुमति मांगने वाला आईडी3 का पत्र वास्तव में 9 तारीख को भेजा गया था और रिजर्व बैंक को केवल आईडी1 पर प्राप्त हुआ था, जबकि शेष कैपारो समूह की ओर से अनुमति मांगने वाला आईडी4 का पत्र रिजर्व बैंक को आईडी2 पर प्राप्त हुआ था। राजा राम भसीन एंड कंपनी द्वारा की गई शेयरों की खरीद के बयानों से पता चलता है कि 14.3.83 से भी, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों की कीमत रु। 3,85, 920.00 भारत भूषण एंड कंपनी से खरीदे गए थे और Rs.45,81,677.00 मूल्य के शेयर मंगला एंड कंपनी से खरीदे गए थे। इन परिस्थितियों के आधार पर कि प्रेषण प्राप्त होने से पहले ही शेयर खरीदे गए प्रतीत होते हैं, एक गंभीर शिकायत की गई है कि गैर-निवासी निवेश योजना के तहत कपारो समूह के लिए शेयर खरीदने के लिए रुपये के धन का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया होगा। हमें नहीं लगता कि शिकायत का कोई वास्तविक आधार है। स्टॉक एक्सचेंज नियमों के तहत भुगतान अनुबंधित खरीद के दो सप्ताह के भीतर किया जा सकता है। वर्तमान मामले में पहली खरीद के दो सप्ताह से भी कम समय में विदेश से प्रेषण आना शुरू हो गया था और विदेशी प्रेषण से भुगतान करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

949

भारतीय रिजर्व बैंक से 4 और 12 मार्च, 1983 के पत्रों द्वारा तेरह कैपर्क समूह की कंपनियों की ओर से शेयर खरीदने की अनुमति के लिए संपर्क किया गया था, जिसने पंजाब नेशनल बैंक को 29.4.83 पर लिखा था कि "(1) श्री स्वराज पॉल और भारतीय मूल के अन्य अनिवासी व्यक्तियों (ii) पारिवारिक न्यास और (iii) तेरह कंपनियों में से प्रत्येक के संबंध में अलग-अलग अन्य लोगों की हिस्सेदारी का सही

प्रतिशत" के बारे में जानकारी मांगी गई थी। यह भी जानकारी मांगी गई कि क्या भारतीय कंपनियों के कोई शेयर पहले ही उनके भारतीय ग्राहकों द्वारा या उनकी ओर से खरीदे जा चुके हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों

रिजर्व बैंक "हिस्सेदारी के सटीक प्रतिशत" आदि के बारे में जानकारी चाहता था क्योंकि संबंधित जानकारी पहले से ही आर. पी. सी. और ओ. ए. सी. प्रपत्रों में दिनांकित 4.3.83 और 12.3.83 पत्रों के साथ भेजी गई थी। आई. डी. 1 का दिनांकित पत्र इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि रिजर्व बैंक केवल यह जानना चाहता था कि क्या भारतीय कंपनियों के कोई शेयर पहले ही खरीदे जा चुके हैं, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा करना अनुचित होगा। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने रिजर्व बैंक को 6.5.83,19.5.83 और 25.5.83 पर तीन पत्र लिखे, जिसका उद्देश्य यह था कि स्वराज पॉल फैमिली ट्रस्ट के पास कपारो ग्रुप लिमिटेड की शेयर पूंजी का 61.6% था, जिसके पास बदले में ग्यारह कंपनियों की शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत और बारहवीं कंपनी की शेयर पूंजी का 98 प्रतिशत था। ट्रस्ट के लाभार्थियों के नाम श्री स्वराज पॉल, श्रीमती अरुणा पॉल, श्री अंबर पॉल, श्री आकाश पॉल, सुश्री अंजलि पॉल और श्री अंगद पॉल के रूप में दिए गए थे। तीनों पत्रों में यह बताया गया कि आवश्यक आर. पी. सी. और ओ. ए. सी. प्रपत्र पहले ही जमा किए जा चुके हैं। अनुमोदन के अभियान के अनुरोध को दोहराया गया। भारतीय रिजर्व बैंक को यह भी सूचित किया गया कि उनके अनिवासी ग्राहकों ने उन्हें सलाह दी थी कि खरीद पूरी होते ही भारतीय कंपनियों के शेयरों का विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक को दिनांकित आईडी2 के पत्र के जवाब में और बाद के किसी भी पत्र के संदर्भ के बिना स्पष्टीकरण के लिए लिखा कि तेरह विदेशी कंपनियों की ओर से शेयरों की खरीद के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त किए बिना, भारतीय कंपनियों के शेयरों की खरीद का भुगतान विदेशी खरीदारों के अनिवासी बाहरी खाते से भारतीय विक्रेताओं को कैसे किया गया। एक बार फिर (1) श्री स्वराज पॉल (11) भारतीय राष्ट्रीयता/मूल (यदि कोई हो) के अन्य अनिवासी व्यक्तियों और (3) यू. के. में कपारो ग्रुप लिमिटेड में ऐसे व्यक्तियों के पारिवारिक समूह की हिस्सेदारी के सटीक प्रतिशत के बारे में जानकारी मांगी गई। 28.5.83 पर पंजाब नेशनल बैंक ने रिजर्व बैंक को एक तार भेजा और 950

इसके बाद 30.5.83 दिनांकित एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि श्री स्वराज पॉल और उनके परिवार के ट्रस्ट का कपारो ग्रुप लिमिटेड में लाभकारी हित 61.6% था जैसा कि फरवरी में रिजर्व बैंक को दिए गए फॉर्म आर. पी. सी. और प्रमाण पत्र ओ. ए. सी. में पहले ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। 83. भारतीय मूल के अन्य गैर-निवासी जो परिवार न्यास के सदस्य थे, वे थे श्रीमती अरुणा

पॉल, श्री आकाश पॉल, श्री अंबर पॉल, श्री अंगद पॉल और सुश्री अंजलि पॉल, ये सभी श्री स्वराज पॉल के परिवार के सदस्य थे। यह आगे बताया गया था कि

पत्र कि योजना द्वारा आवश्यक के रूप में जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आवेदन करने पर अनुमति देगा निर्धारित तरीके से किए गए, तेरह कंपनियों ने सभी औपचारिकताओं का पालन करते हुए अपने आवेदन जमा किए थे। द.

23.4.83 के पत्र का भी उल्लेख किया गया था और यह उल्लेख किया गया था कि सभी विवरण उसमें दिए गए थे। पंजाब नेशनल बैंक ने आगे अपना विचार व्यक्त किया कि योजना के प्रावधानों के तहत उन्हें भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदने से पहले रिजर्व बैंक की मंजूरी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी, एक बार उचित आवेदन जमा किए जाने के बाद। रिजर्व बैंक को सूचित किया गया कि कपारो ग्रुप लिमिटेड से प्रेषण राजा राम भसीन एंड कंपनी, उनके नामित दलालों और पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के पक्ष में किया गया था। इसलिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एन. आर. ई. खाते के माध्यम से विभिन्न तिथियों पर 23.4.83 तक और उसके बाद संचालन किया गया। भुगतान दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के उप कानूनों और विनियमों के अनुसार किए गए थे। आईडी2 पर, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा रिजर्व बैंक को एक और तार भेजा गया था जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उन्हें एजेंट दलालों द्वारा सलाह दी गई थी कि आईडी1 तक उन्होंने दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल कंपनी लिमिटेड के 80,000 इक्विटी शेयर और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 75,000 इक्विटी शेयर तेरह विदेशी कंपनियों में से प्रत्येक की ओर से खरीदे थे, जो मुख्य रूप से भारतीय मूल के गैर-निवासियों के स्वामित्व में थीं।

1.6.83 पर, भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक नियंत्रक ने भारत सरकार को रसीद के बारे में सूचित करते हुए लिखा

तेरह विदेशी कंपनियों की ओर से पंजाब नेशनल बैंक से आवेदनों की संख्या, जिनमें से ग्यारह पूरी तरह से कपारो ग्रुप लिमिटेड के स्वामित्व में थीं, जो बदले में श्री स्वराज पॉल के फैमिली ट्रस्ट के स्वामित्व में थी। बारहवीं कंपनी, कपारो प्रॉपर्टीज लिमिटेड, कपारो ग्रुप लिमिटेड में 98 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। कापारो ग्रुप लिमिटेड का स्वामित्व 61.6% तक श्री स्वराज पॉल के पारिवारिक न्यास, समूह के अन्य सदस्यों के पास था।

पारिवारिक न्यास में श्रीमती अरुणा पॉल, श्री आकाश पॉल, श्री अंबर पॉल, श्री अंगद पॉल और सुश्री अंजलि पॉल हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कपारो समूह भी प्रत्यक्ष रूप से भारतीय मूल के अनिवासी व्यक्तियों के स्वामित्व में नहीं है, बल्कि केवल अप्रत्यक्ष रूप से एल. आई. सी. v. के माध्यम से 61.6% की सीमा तक है।

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

उन्होंने इस विचार का समर्थन किया कि तेरह विदेशी कंपनियों में से कोई भी भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के योग्य नहीं थी और वर्तमान नीति। . इसलिए उन्होंने सभी तेरह विदेशी कंपनियों के आवेदनों को अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। वे.

भारत सरकार से टेलेक्स द्वारा पुष्टि करने का अनुरोध किया। इस पर भारत सरकार ने 8.6.83 पर टेलेक्स द्वारा इन शब्दों में जवाब दिया:

" संदर्भ D.O.NO. EC.CO. एफ. आई. डी. (II) 294/344-82/83 दिनांक शून्य जून 1983 तीसरी तारीख से आवेदन

पोर्टफोलिओ निवेश योजना (पी. आई. वी. एस.) के तहत अधिकार वापसी के साथ स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भारतीय कंपनियों की खरीद साझेदारी के लिए ओवरसीज कंपनियां। यह बताया गया है कि कुछ सामान पहले ही बनाए जा चुके हैं

पंजाब नेशनल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव की शर्तें

बैंक (.) हालांकि यह पोर्टफोलिओ पोर्टफोलिओ निवेश योजना के तहत मई 1983 में दूसरे स्थान पर आने से पहले लागू होता है।

अधिकृत विक्रेता आर. बी. आई. की पूर्व मंजूरी के बिना कर सकते हैं

अपने आप में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदारी साझा करें उनके गैर-निवासी ग्राहक, जिस स्थिति में हैं

कुछ ऐसे सामान जो हम पहले ही बना चुके थेसम्मिलित कंपनियों को आवश्यक मंजूरी मिल गई

आर. बी. आई. को स्पष्ट नहीं देखा जाता है (।)

आर. बी. आई. को आगे की पूछताछ करने की आवश्यकता हैसरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें और प्रस्तुत करें

विषय के सभी पहलुओं को शामिल करना

इस तरह के खरीद का विवरण, वित्तीय स्थिति और

एप्लिकेंट कंपनियों और उनकी गतिविधियोंनिगम की तिथियाँ और सामान्य कानून भी

स्टॉक 952 पर इस तरह के खरीददारों के लिए मुद्दा

गैर-निवासी भारतीय कंपनियों ई. टी. सी. द्वारा स्थानांतरण। मई 1983 में दूसरे स्थान पर आने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व विशेष मंजूरी (.) के बिना मान्य हैं। आपकी रिपोर्ट

सरकार को निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने के आदेश में जितनी जल्दी हो सके हमें पहुंचना चाहिए।

टेलेक्स संदेश में 2 मई, 1983 का इतना बार उल्लेख किया गया महत्व स्पष्ट रूप से इसलिए है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 मई, 1983 को जारी परिपत्र संख्या 12 द्वारा भारतीय मूल के विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों में 5 प्रतिशत की सीमा लागू करने के लिए 2 मई, 1983 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया था।

इस बीच, 31.5.83 पर, पंजाब नेशनल बैंक ने लिखा

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने उन्हें सूचित किया कि तेरह विदेशी कंपनियां एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों में निवेश कर रही थीं, जो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के स्वामित्व वाले विदेशी कॉर्पोरेट निकायों द्वारा निवेश की योजना के संदर्भ में कम से कम 60 प्रतिशत तक था और तेरह विदेशी कंपनियों ने उन्हें अपने बैंकर के रूप में नामित किया था और मेसर्स राजा राम भसीन एंड कंपनी को निवेश के उद्देश्य से दलाल के रूप में नामित किया गया था। दलालों ने बैंक को सलाह दी थी कि 28 अप्रैल तक एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 83,75,000 इक्विटी शेयरों का भुगतान किया जा चुका है।

तेरह विदेशी कंपनियों में से प्रत्येक के लिए उनके द्वारा खरीदा गया।

इस प्रकार खरीदे गए शेयरों में से प्रत्येक कंपनी द्वारा खरीदे गए 35,560 शेयर दलालों द्वारा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड में दर्ज किए गए थे।

इस उद्देश्य के लिए एच. सी. भसीन और श्री भारत भूषण के नाम

कम्पनीक बहीमे शेयरक अंतरण। 35,667

श्री एच. सी. भसीन और श्री भरत के नाम पर स्थानांतरण का उद्देश्यभूषण। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने 1 जून, 1983 को जवाब दिया और अनुरोध किया

पंजाब नेशनल बैंक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कि क्या

गैर-निवासी कंपनियों ने आवेदनों को निष्पादित और सौंपा था

पूर्व अनुमति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में दाखिल किया जाना

उनके माध्यम से कंपनी के शेयरों को नामित के रूप में खरीदें

बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक को शेयर खरीदने के लिए कहापत्र में उल्लिखित तेरह कंपनियों की ओर से। एस्कॉर्ट्स

लिमिटेड ने इस पत्र में इस परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया कि

एच. सी. भसीन और भारत भूषण ने उनके पास शेयर दर्ज कराए थे।

किसी के नाम के स्थान पर अपने नामों में स्थानांतरण के लिए

विदेशी कंपनियाँ। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था यह अजीब बात है कि दलालों ने अपने नाम पर शेयर दर्ज किए

उनके प्रधानाचार्यों के बजाय, सरल कारण के लिए कि अलविदा-कानून

242 स्टॉक एक्सचेंज विनियम दलालों को ऐसा करने की अनुमति देते हैं

यदि वे समापन जे से पहले औपचारिकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं।]

953

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी,

किताबों से। वे अब इसे एक बिंदु बनाने की कोशिश करते हैं। यह स्पष्ट रूप से सारहीन है। वास्तव में पंजाब नेशनल बैंक को लिखे अपने पत्र में, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने यह उल्लेख करना भी सार्थक नहीं समझा कि जब उन्होंने दलालों को 27.5.83 पर यह जानकारी का अनुरोध करते हुए लिखा कि क्या वे शेयरों के लाभकारी मालिक थे और क्या शेयर भारतीय मूल के गैर-निवासियों की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक अनुमति से खरीदे गए थे। श्री एच. सी. भसीन और श्री भारत भूषण द्वारा जानकारी देने से इनकार कर दिया गया, जिन्होंने ऐसी जानकारी मांगने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाया था, और यहां तक कि हस्तांतरण की कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दर्ज नहीं की गई थी। हम दलालों के रवैये के पीछे के कारण को समझने में असमर्थ हैं। हम केवल एक अनुमान लगा सकते हैं। शायद वे अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। यह कि उन्होंने विदेशी निवेशकों के लिए शेयर खरीदे थे, कोई रहस्य नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले ही पंजाब नेशनल बैंक को सूचित कर दिया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा था कि शेयरों को उनके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए कहने में स्टॉक एक्सचेंज विनियमों के तहत वे अपने अधिकारों के भीतर थे। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के विद्वान वकील ने सुझाव दिया कि दलाल अपने प्राचार्यों के नामों का खुलासा करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि उन्होंने रुपये के धन का उपयोग किया था और इस तथ्य को छिपाना चाहते थे। यह सुझाव दूरगामी प्रतीत होता है क्योंकि तब तक विदेशों से भेजी गई राशि अधिक थी।

तब तक जमा किए गए शेयरों की खरीद को कवर करने के लिए पर्याप्त है। हालाँकि, हमें ध्यान देना चाहिए कि रिकॉर्ड में यह खुलासा नहीं किया गया है कि भारत भूषण तस्वीर में कैसे आए, जिन्होंने उन्हें कपारो समूह की ओर से शेयर खरीदने के लिए अधिकृत किया और जिन्होंने उन्हें अपने नाम पर शेयर जमा करने का निर्देश दिया? वह विदेशी कंपनियों की ओर से शेयर खरीदने के लिए नामित स्टॉक ब्रोकर नहीं थे। यदि

ऐसा है, तो कोई आश्चर्य करता है कि उसकी ओर से लेनदेन करने का उसे क्या अधिकार था। विदेशी कंपनियाँ! यह भी एक ऐसा मामला है जिसकी रिजर्व बैंक द्वारा जांच की आवश्यकता हो सकती है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक ने 13 कंपनियों में से प्रत्येक द्वारा शेयरों की खरीद और एच. सी. भसीन और श्री भारत भूषण के नाम पर कंपनी के साथ शेयरों को दर्ज करने के बारे में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को 31.5.83 पर लिखा था।

कंपनी की बही में शेयरों के हस्तांतरण का उद्देश्य। हमने 1.6.83 पर पंजाब नेशनल बैंक को एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के जवाब का भी उल्लेख किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने तुरंत एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को 2.6.83 पर लिखा कि उन्होंने कंपनी को पहले ही सूचित कर दिया था कि तेरह कंपनियों के लिए शेयरों की खरीद

नामित दलाल मेसर्स द्वारा संभाला गया था। राजा राम भसीन एंड कंपनी और वह जानना चाहता था कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड किस उद्देश्य के लिए था उनसे जानकारी मांगें। हालाँकि, उन्होंने कहा कि वे 954

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

तेरह कंपनियों के बैंकरों के रूप में नामित किए गए थे और उन्होंने योजना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य किया था। बहुत अधिक हलचल के बिना, यानी मैसर्स से कोई और पूछताछ किए बिना। राजा राम भसीन या पंजाब नेशनल बैंक से या भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गदर्शन की कोई जानकारी लिए बिना, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड द्वारा शेयरों के हस्तांतरण की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ कानूनी राय लेने के बाद, समिति ने एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल को शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण के खिलाफ सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जिस प्राथमिक आधार पर सिफारिश की गई थी और जिसके बारे में हम अब चिंतित हैं, वह आधार संख्या 5 है जिसमें कहा गया है,

" कि कंपनी के प्रावधानों द्वारा निषिद्ध है

शेयर हस्तांतरण के पंजीकरण से एफ. ई. आर. ए. की धारा 19

अपनी पुस्तकों में जब उसके पास संदेह करने के कारण हैं कि

धारा 19 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है

फेरा का "।

समिति ने बताया कि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि विचाराधीन शेयरों की खरीद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। समिति की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि उन्होंने 'शेयरों को पंजीकृत करने के लिए कंपनी को डराने और मजबूर करने और कंपनी के संघ के अनुच्छेदों और कानून के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के विवेक के स्वतंत्र और उचित प्रयोग को पूर्व-खाली करने के प्रयासों' का गंभीर संज्ञान लिया। हालाँकि, रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि कंपनी को पंजीकृत करने के लिए डराने और मजबूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए थे

शेयर और मुक्त और उचित अभ्यास को पूर्व-खाली करने के लिए

जिस पर

बोर्ड का विवेकाधिकार। '

9.6.83 पर, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने विचार किया

समिति की रिपोर्ट और एक प्रस्ताव पारित करने से इनकार कर दिया

शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करें। संकल्प में था

निम्नलिखित शर्तें -

और निदेशकों की स्थानांतरण समिति। बोर्ड ने आगे कहा मामले के सभी पहलुओं पर समग्र रूप से विचार किया गया, सभी

सामग्री जो एकत्र की गई थी और पहले रखी गई थी

बोर्ड और कानूनी राय और कानूनी रिकॉर्ड कंपनी द्वारा प्राप्त की गई सलाह

मुद्दे में बिंदु। बोर्ड ने आगे विचार किया कि क्या

एफ. ई. आर. ए और एफ. ई. आर. ए 955 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

कंपनी कानून, स्टाम्प अधिनियम, सार्वजनिक प्रतिभूति अधिनियम और स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित अन्य विनियमों और कानून की आवश्यकता वाले शेयरों के हस्तांतरण सहित विनियमों और अन्य प्रासंगिक कानूनों का पालन किया गया है। बोर्ड ने प्रेस में दिए गए और संबंधित अनिवासी के साथ-साथ दिल्ली में उनके सहयोगियों द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों पर भी विचार किया, जो पात्र निवासियों द्वारा

पोर्टफोलियो निवेश के लिए उदार योजना के तहत सरकार की नीति के विपरीत हैं। बोर्ड ने आगे विचार किया कि क्या विचाराधीन शेयरों की खरीद 'पोर्टफोलियो' के रूप में योग्य होगी।

आर. बी. आई. योजना के तहत परिकल्पित 'निवेश'। बोर्ड ने आगे विचार किया कि क्या प्रस्तावित हस्तांतरण को मंजूरी देना कंपनी और उसके शेयरधारकों के हित में है और क्या प्रस्तावित हस्तांतरणकर्ताओं को शेयरधारकों के रूप में स्वीकार करना उपरोक्त हितों में वांछनीय है। शेयर जांच और स्थानांतरण समिति की रिपोर्ट पर पूरी चर्चा के बाद बोर्ड ने इसे स्वीकार कर लिया। कानूनी और साथ ही मुद्दों की पूरी जांच के बाद

तथ्यात्मक और परिस्थितियां और आगे शेयर जांच और हस्तांतरण समिति की रिपोर्ट में निहित कारणों के कारण और उक्त समिति की सिफारिशों के आलोक में और आगे निदेशक मंडल के इस विचार के कारण कि कंपनी या शेयरधारकों के सामान्य निकाय के हित में नहीं होगा कि वे विचाराधीन शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करें और बोर्ड के इस विचार के कारण कि निदेशक मंडल द्वारा ध्यान में रखे गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए प्रश्नगत हस्तांतरणकर्ताओं को सदस्यों के रूप में स्वीकार करने के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित नहीं किया जा सकता है, बोर्ड ने निम्नलिखित शेयरों के पंजीकरण से इनकार करने का निर्णय लिया।

विचार करें।

यह तय किया गया कि श्री हरीश चंदर भसीन द्वारा दर्ज किए गए प्रत्येक पूर्ण रूप से भुगतान किए गए Rs.10 में 2,88,390 इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण और श्री भारत भूषण द्वारा विशिष्ट संख्या के अनुसार दर्ज किए गए प्रत्येक पूर्ण रूप से भुगतान किए गए Rs.10 के 1,73,947 इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण। चिह्नित सूचियों में दिखाई देता है निदेशकों के समक्ष रखे गए और पहचान के उद्देश्य से अध्यक्ष द्वारा आरंभ किए गए अनुलग्नक ए और बी को क्रमशः अस्वीकार कर दिया जाता है।

इसके अलावा यह संकल्प लिया गया कि श्री चरणजीत सिंह, कंपनी के उपाध्यक्ष और सचिव, धारा 1 के तहत हस्तांतरणकर्ताओं को इनकार करने की सूचना देने और भेजने के लिए अधिकृत हैं और इसके द्वारा अधिकृत हैं। 111 (2) कंपनी अधिनियम, 1956 और ऐसे अन्य कदम उठाना जो कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में आवश्यक और उचित हों।संकल्प के ऊपर।

प्रस्ताव को सभी 13 निदेशकों (कंपनी के कुल 15 निदेशकों में से) के साथ पारित किया गया और श्री डी. एन. डावर को छोड़कर प्रस्ताव के लिए मतदान किया गया।जिन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया और प्रस्ताव पर मतदान किया। कोई असहमत मतदान नहीं हुआ।

तेरह विदेशी अनिवासी कंपनियों के नाम पर पंजीकरण के लिए 19 और 22 अगस्त, 1983 को एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के पास दर्ज शेयरों के एक अन्य ब्लॉक के संबंध में, समिति द्वारा 29.9.83 पर एक समान रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और उसी दिन निदेशक मंडल द्वारा एक समान प्रस्ताव पारित किया गया था।

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, हालांकि उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया था

शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करना, फिर भी, विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी के लिए पंजाब नेशनल बैंक को लिखा गया क्योंकि वे सरकार के निर्देशों के तहत रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही जांच में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। कंपनी जानना चाहती थी कि क्या प्रेषण मेसर्स से प्राप्त हुआ था। केवल कपारो ग्रुप लिमिटेड और अन्य बारह विदेशी कंपनियों में से किसी से भी नहीं। कंपनी यह भी जानना चाहती थी कि क्यों 4,62,337 शेयर केवल हस्तांतरण के लिए उनके पास दर्ज किए गए थे, हालांकि यह कहा गया था कि 9.75 लाख शेयर थे।

तेरह अनिवासी कंपनियों द्वारा खरीदा गया था। कंपनी आगे जानना चाहती थी कि क्या पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दलालों को शेयर खरीदने के निर्देश दिए गए थे और क्या गैर-निवासी कंपनियों ने अधिकतम का संकेत दिया था।वह मूल्य जिस पर शेयर खरीदे जा सकते हैं। कंपनी ने आगे यह जानना चाहा कि शेयर स्क्रिप्ट किसे वापस की जानी चाहिए।

शेयर। हम यहाँ बता सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। शेयर स्क्रिप्ट प्राप्त करें और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को सुझाव दें कि

उन्हें उन लोगों को स्क्रिप्ट वापस करनी चाहिए जिन्होंने उन्हें दर्ज किया था

कंपनी ने।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड,

पहले से ही हस्तांतरण के पंजीकरण को अस्वीकार कर दिया है

शेयर, 14 जून, 1983 को भारतीय रिजर्व बैंक को लिखा गया,20 जून, 1983 और 23 जुलाई, 1983 का उद्देश्य सूचना देना है।

957 के मामले में की गई विभिन्न अवैधताओं के संबंध में

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

तेरह विदेशी कंपनियों, कपारो ग्रुप लिमिटेड आदि द्वारा अपनी कंपनी के शेयरों की खरीद। यह कहा गया था कि यह जानकारी रिजर्व बैंक को दी जा रही थी क्योंकि यह समझा गया था कि रिजर्व बैंक कपारो समूह

की कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों में शेयरों की खरीद के मामले में जांच कर रहा था। इन पत्रों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि किसी कारण से एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने रिजर्व बैंक को इस स्थिति का खुलासा नहीं किया कि उन्होंने पहले ही शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। पहले पत्र में, यह कहा गया था कि उनकी जानकारी से पता चलता है कि कपारो ग्रुप लिमिटेड होल्डिंग कंपनी थी और शेष बारह कंपनियां इसकी सहायक थीं और उनमें से अधिकांश इतनी बड़ी कमाई करने के लिए कोई वित्तीय स्थिति में नहीं थीं।

निवेश करें। रिजर्व बैंक से विशेष रूप से इस बात पर विचार करने का अनुरोध किया गया था कि क्या यह कभी इरादा था कि कोई विदेशी कंपनी एक प्रतिशत की निर्धारित सीमा को दरकिनार कर सकती है। एक दर्जन सहायक कंपनियों के माध्यम से निवेश करना। यह था।

इंगित किया कि उस प्रकृति का एक रंगीन उपकरण छत के उद्देश्य को विफल कर देगा। रिजर्व बैंक से इस तथ्य पर गंभीरता से ध्यान देने का भी अनुरोध किया गया था कि इस योजना में भारतीय कंपनी में अधिकतम एक प्रतिशत तक के निवेश के लिए प्रत्यावर्तन लाभ की अनुमति दी गई थी, जबकि तेरह कंपनियों के नाम पर 7 प्रतिशत से अधिक के शेयरों का अधिग्रहण किया गया था, हालांकि केवल एक कंपनी द्वारा धन प्रेषित किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि शेयर दलालों ने, न कि बैंक ने, शेयर खरीदे और स्टॉक दलालों ने अनधिकृत रूप से अपने नाम, गैर-निवासियों की ओर से खरीदे गए शेयरों को पंजीकृत करने के लिए दर्ज किया। रिजर्व बैंक से शेयरों की खरीद की तारीखों और दरों की जांच करने का अनुरोध किया गया था, क्या

शेयरों की खरीद स्टॉक एक्सचेंज के पटल पर की जाती थी, क्या शेयरों की डिलीवरी ली गई थी, क्या बैंक के पास लेनदेन का दिन-प्रतिदिन का रिकॉर्ड था आदि। रिजर्व बैंक से स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और लेखा पुस्तकों को जब्त करने का भी अनुरोध किया गया था। 20 जून, 1983 के अगले पत्र ने उन परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जो हालांकि

9,75,000 शेयरों को 28 अप्रैल, 1983 से पहले खरीदा गया था, केवल 4,62,337 शेयर 13 मई, 1983 तक दर्ज किए गए थे और इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि आगे का लेन-देन था और खरीद योजना के अनुसार नहीं थी। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने 23 जुलाई, 1983 को अपने तीसरे पत्र में

दावा किया कि लगभग रु. की बड़ी राशि। विदेशों से पंजाब नेशनल बैंक को 2 करोड़ 61 लाख रुपये भेजे गए और इसका उपयोग इसके अलावा शेयर खरीदने के लिए किया गया।

तेरह कंपनियों के नाम से खरीदे गए शेयर। एफ. ई. आर. ए. के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया और प्रति 958 पर एक की सीमा का उल्लंघन किया गया।

योजना के तहत लगाए गए प्रतिशत और 5 प्रतिशत को भी दरकिनार कर दिया गया। रुपये की राशि रु। ऐसा प्रतीत होता है कि 4 करोड़ रुपये की खरीद के लिए अनधिकृत रूप से डायवर्ट किए गए थे।

दो भारतीय कंपनियों, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड में तेरह अनिवासी कंपनियों के लिए और उनकी ओर से शेयर। हालाँकि तेरह अनिवासी कंपनियों की ओर से की गई खरीद 28 अप्रैल, 1983 से पहले की गई थी, लेकिन हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए कंपनी के पास केवल 4,62,337 शेयर दर्ज किए गए थे, जिससे 5,12,663 शेयरों की कमी हो गई। इन शेयरों की गैर-जमाखोरी ने संदेह पैदा किया कि क्या उन शेयरों को योजना के साथ एकोर डांस में खरीदा गया था। यह बताया गया कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के पास दर्ज किए गए शेयर हस्तांतरण विलेखों में 28 अप्रैल, 1983 की तारीख थी और प्रति शेयर Rs.65 के विचार का खुलासा किया गया था, हालांकि

28 अप्रैल, 1983 तक स्टॉक एक्सचेंज में एस्कॉर्ट्स शेयरों की बिक्री की उच्चतम दर Rs.55 केवल प्रति शेयर थी। इस तथ्य से पता चलता है कि एक गलत बयान दिया गया था कि शेयर 28 अप्रैल, 1983 से पहले खरीदे गए थे। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 9,75,000 शेयरों और दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड के 10,30,000 शेयरों के संबंध में कंपनियों के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण विलेखों से पता चलता है कि गैर-निवासी भारतीय कंपनियों की ओर से खरीदे गए शेयरों के लिए कुल रु. 6,33,75,000 की राशि खर्च की गई थी। एस्कॉर्ट्स एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों की खरीद और गैर-निवासी निधियों का 020 रुपये की राशि खरीद पर खर्च की गई।

दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड के शेयर कुल मिलाकर Rs.16,22,44,020 बना रहे हैं। इसके विपरीत, शेयरों की खरीद के लिए विदेशों से केवल Rs.13 करोड़ की राशि भेजी गई थी। Rs.13 करोड़ में से, एक करोड़ रुपये की राशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोक दिया गया था, जिससे शेयरों की खरीद के लिए केवल Rs.12 करोड़ गैर-निवासी निधियों की शेष राशि उपलब्ध थी। इस प्रकार रुपये की एक छोटी सी गिरावट थी। 2. 61 करोड़ जो कि बेनामी था। रिजर्व बैंक के संज्ञान में यह भी लाया गया कि दलालों ने अपने खाते में हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए शेयर दर्ज किए थे।

विदेशी कंपनियों के नाम। जब कंपनी द्वारा प्राचार्यों के नामों का खुलासा करने के लिए कहा गया, तो दलालों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसलिए कंपनी ने विभिन्न कदमों का सुझाव दिया जो रिजर्व बैंक द्वारा की गई कई अवैधताओं का पता लगाने और किसी भी गैर-निवासी व्यक्ति या कंपनी द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के लिए योजना द्वारा लगाई गई एक प्रतिशत सीमा के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाए जाने चाहिए।

इनमें से किसी भी पत्र का भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया या यहां तक कि स्वीकारोक्ति भी नहीं दी। हालांकि रिजर्व बैंक ने एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से कोई और जांच लिखने या करने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिजर्व बैंक ने 959 किया।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

कैप्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ एस्कॉर्ट्स लिमिटेड द्वारा लगाए गए आरोपों की अपने तरीके से जांच करें। ऐसा नहीं था कि रिजर्व बैंक ने केवल कपारो समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों के संबंध में खुद को चिंतित करने से इनकार कर दिया था। पंजाब नेशनल बैंक कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज का नामित बैंक था और यह एफ. ई. आर. ए. के तहत एक अधिकृत विक्रेता था, जो एफ. ई. आर. ए. और पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत रिजर्व बैंक के प्रति गंभीर जिम्मेदारी रखता था। इसलिए रिजर्व बैंक ने इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक का रुख किया।

11 जून, 1983 को भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक को पत्र लिखकर उन्हें सलाह दी कि केवल एक सेक के तहत आवेदन। 29 (1) (ख) एफ. ई. आर. ए. का प्रावधान गैर-निवासी भारतीय कंपनी को रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना शेयर खरीदने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। भारतीय कंपनियों के किसी भी शेयर को खरीदने से पहले रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ती थी। पंजाब नेशनल बैंक का तर्क कि एक आवेदन जमा करना सक्षम करने के लिए पर्याप्त था

गैर-निवासी कंपनी द्वारा शेयर खरीदने को सही नहीं माना गया और बैंक को बताया गया कि उन्होंने शेयर खरीदने में गंभीर अनियमितता की है। पंजाब नेशनल बैंक ने

नियंत्रण नियमावली। पंजाब नेशनल बैंक को सूचित किया गया कि इसे खोलने की मंजूरी के लिए सभी कंपनियों के आवेदन गैर-निवासी खाते उनके पास लंबित थे और जब तक शेयरों की खरीद के लिए विशिष्ट अनुमति नहीं दी जाती, तब तक तेरह कंपनियों में से किसी की ओर से शेयर खरीदने के लिए खातों से कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। उसी तारीख को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को एक और पत्र लिखा गया था जिसमें उनके द्वारा खरीदी गई तेरह कंपनियों और तेरह कंपनियों से अब तक प्राप्त प्रेषण की तारीखों का विवरण मांगा गया था। 17 जून, 1983 और 23 जून, 1983 को पंजाब नेशनल बैंक ने अपना जवाब भेजा।

रिजर्व बैंक टेलेक्स और पत्र द्वारा। उन्होंने टेलेक्स संदेश में कहा कि रिजर्व बैंक के पत्र के परिणामस्वरूप, उन्होंने दलालों के पक्ष में Rs.107,22,610 की राशि का भुगतान रोक दिया था और उन्होंने प्रेषक को इसके बारे में सलाह दी थी। यह कहा गया था कि दलालों ने उन्हें पत्र लिखकर कहा था कि

भुगतान में कहा गया है कि यह डिफ़ॉल्ट राशि होगी यदि भुगतान पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत 2 मई 1983 से पहले शेयरों की खरीद से संबंधित है। 23 जून, 1983 के अपने पत्र द्वारा उन्होंने रिजर्व बैंक को सूचित किया कि दिसंबर 1982 तक और 1 जनवरी, 1983 से 28 फरवरी, 1983 तक 960 की ओर से कोई शेयर नहीं था।

[1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

तेरह में से गैर-निवासी कंपनियों को खरीदा गया था। 1 मार्च, 1983 और 2 मई, 1983 के बीच, तेरह कंपनियों में से प्रत्येक के लिए दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड के 80,000 शेयर और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 75,000 शेयर खरीदे गए। 2 मई, 1983 के बाद कोई शेयर नहीं खरीदा गया। मेसर्स के क्रेडिट के लिए उनकी लंदन शाखा के माध्यम से सभी प्रेषण प्राप्त किए गए थे। राजा राम भसीन एंड कंपनी, की ओर से शेयरों की खरीद के लिए

तेरह कंपनियाँ। 9 मार्च, 1983,24 मार्च, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 28 अप्रैल और 28 अप्रैल, 1983 को

रु. 1,35,36,000 रु. 1,31,38,681, रु. 2,36,59,900 , Rs.76,35,000 रुपये, 1,56,76,000 रुपये और 1,56,80,000 रुपये प्राप्त हुए और कपारो ग्रुप लिमिटेड के खाते से राजा राम भसीन एंड कंपनी के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। कपारो ग्रुप लिमिटेड के एनआरई खाते में Rs.38,682 की शेष राशि को उनके दलाल एम/के पत्र के संदर्भ में 2 जून, 1983 को तेरह खातों में आनुपातिक रूप से आवंटित किया गया था। s.Raja राम भसीन एंड कंपनी। दलाल ने निवेशकों के पत्रों के संदर्भ में अपना अधिकार प्राप्त किया जो इसके साथ संलग्न किए गए थे

बैंक का पत्र। पंजाब नेशनल बैंक ने यह भी कहा कि दलाल ने 22 जून, 1983 के अपने पत्र द्वारा पुष्टि की थी, जिसकी एक प्रति संलग्न की गई थी, कि उल्लिखित शेयरों के अलावा उन्होंने तेरह के लिए कोई अन्य शेयर नहीं खरीदा था। कंपनियाँ। अपने पत्र के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने रिजर्व बैंक को निगमन प्रमाण पत्र की प्रतियां, संघों के लेखों के ज्ञापन और तेरह कंपनियों की बैलेंस शीट भी भेजी। पंजाब नेशनल बैंक के पत्र के साथ संलग्न पत्रों में से एक कपारो ग्रुप लिमिटेड का पंजाब नेशनल बैंक को एक पत्र था जिसमें पुष्टि की गई थी कि उन्होंने मेसर्स की नियुक्ति की है। राजा राम भसीन एंड कंपनी उनके नामित दलालों के रूप में और यह कि बैंक को उपरोक्त दलालों के निर्देशों पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था,

पूरी तरह से कपारो ग्रुप लिमिटेड के जोखिम और जिम्मेदारी पर।

24 जून, 1983 को पंजाब नेशनल बैंक ने 11 जून, 1983 के अपने पत्र के जवाब में रिजर्व बैंक को फिर से लिखा, उन्होंने कहा कि वे इस धारणा में थे कि "..... ..... ए के रूप में

बहुत सावधानी बरतते हुए उन्होंने एन. आर. ई. निवेशकों और उनके दलालों को सूचित किया था कि लेन-देन पूरी तरह से उनके जोखिम और जिम्मेदारी पर किया जा रहा है। प्रेषण का विवरण राजा राम भसीन एंड कंपनी के खाते में प्राप्त और हस्तांतरित नृत्य एक बार फिर दिए गए और अनुमति के लिए अनुरोध दोहराया गया।

6 जुलाई, 1983 को भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रक ने भारत सरकार को पत्र लिखकर उन्हें सूचित किया

कि संबंधित दस्तावेजों को बुलाया गया था और उनकी जांच की गई थी और 961

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे-]

8 जून, 1983 को सरकार के टेलेक्स द्वारा वांछित रिपोर्ट पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही थी। यह कहा गया था कि उन्होंने 'एक प्ररख्यात न्यायविद और वरिष्ठ वकील' श्री एच. एम. सीरवई की कानूनी राय ली थी, जिसका प्रभाव यह था कि परिपत्र ने सामान्य अनुमति नहीं दी थी गैर-निवासी या उनके नामित बैंक और वे विदेशी निकाय जहां वे सीधे गैर-निवासी व्यक्तियों के स्वामित्व में नहीं थे, उदारीकृत योजना के तहत निवेश करने के पात्र नहीं थे। इसलिए यह कहा गया कि तेरह विदेशी कंपनियों में से कोई भी इस योजना के तहत भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के योग्य नहीं थी। संबंधित विनिमय नियंत्रण विनियमों का पालन करने में पंजाब नेशनल बैंक की विफलता के मामले में आगे की कार्रवाई का सवाल आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेने के बाद अलग से लिया जाएगा, यानी शेयर खरीदने की अनुमति के लिए विदेशी कंपनियों के आवेदन। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट जो उनके पत्र के साथ भेजी गई थी, उसे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, न ही इसे हमारे समक्ष रखा गया है। भारत सरकार ने 11 अगस्त, 1983 को रिजर्व बैंक के 6 जुलाई, 1983 के पत्र का जवाब दिया।

महान्यायवादी द्वारा दी गई राय के बारे में महान्यायवादी को सूचित करते हुए रिजर्व बैंक से पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किए गए आवेदनों का महान्यायवादी की राय के आलोक में निपटारा करने के लिए कहा। भारत सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि

वे महान्यायवादी की राय से सहमत थे जिन्होंने

सरकारी नीति के पीछे के इरादे के प्राथमिक महत्व को देखते हुए जो कार्य समूह की रिपोर्ट में बताया गया था। 17 सितंबर, 1983 के एक अन्य पत्र द्वारा, भारत सरकार ने स्थिति को स्पष्ट किया और यह बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के स्वामित्व वाली कंपनियों और विदेशी निकायों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना को प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के उपायों के एक पैकेज के हिस्से के रूप में पेश किया गया था।

भारतीय राष्ट्रीयता के गैर-निवासियों द्वारा नृत्य और निवेश

हमारी कठिनाइयों के समग्र संदर्भ में भारत में उत्पत्ति भुगतान संतुलन। यह बताया गया कि योजना तैयार करने में, तीन सर्वोपरि विचार थे:

(ए) जितना संभव हो उतना लचीलापन होना चाहिएभारत में विदेशी मुद्रा लाने के लिए गैर-निवासियों के लिए उपलब्ध और चिंता का उद्देश्य निवेश होना चाहिए न कि कानूनी इकाई

भारतीय मूल के अनिवासी निवेशक;

(ख) यह सुनिश्चित किया जाना था कि योजना के लाभ गैर-निवासी व्यक्तियों या भारतीय निकायों के अलावा अन्य विदेशी निकायों को उपलब्ध न हों।

राष्ट्रीयता/मूल; और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52

[1985] SUPP.3 एस. सी. आर.

(ग) योजना के तहत धन के निवेश से मौजूदा कंपनियों का अधिग्रहण होना चाहिए।

शेयर बाजार में संचालन।

टी पहले दो विचारों के संदर्भ में था कि यह था इस बात पर जोर दिया कि विदेशी कंपनियाँ आदि के स्वामित्व में होनी चाहिए

पर-भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के निवासियों की सीमा तकपूर्व 60 प्रतिशत और यह तीसरे विचार के संदर्भ में था

प्रत्येक के लिए चुकता पूंजी के एक प्रतिशत की सीमा

निवेशक को लगाया गया था। समान विचारों के अलावा, मई में,

983 , कुल निवेश पर 5 प्रतिशत की सीमा भी निर्धारित की गई थी। भारत सरकार ने बताया कि

अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।इन विचारों को। यह इंगित किया गया था:

" कई देशों में उन कंपनियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो एक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहले से ही स्वामित्व कर सकता है। भारतीय मूल का व्यक्ति

यदि वे चाहें, तो हमारी पोर्टफोलियो निवेश योजना के ढांचे के भीतर सीधे उनके स्वामित्व वाली कई कंपनियों की स्थापना कर सकते हैं और इनमें से प्रत्येक कंपनी के माध्यम से भारत में किसी कंपनी की चुकता पूंजी का एक प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। यह स्थिति अपने आर्थिक प्रभावों में अलग नहीं है यदि

समान राशि का निवेश एक ही व्यक्ति द्वारा भारत में समान कंपनियों में समान संख्या में कंपनियों द्वारा किया गया था, जो अप्रत्यक्ष रूप से (और प्रत्यक्ष रूप से नहीं) उसके स्वामित्व में थीं। योजना के उद्देश्यों और सरकार के इरादे को ध्यान में रखते हुए, यह तथ्य कि क्या कोई कंपनी मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में है या मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में है, एक सामग्री नहीं है।

विचार करें।

उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए और कंपनियों की पात्रता के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी निकाय, चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में हों, इस योजना के तहत निवेश करने के लिए तब तक पात्र हैं जब तक कि यह स्पष्ट है कि कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक अंतिम स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के हाथों में है। ऐसी प्रत्येक आवेदक कंपनी एक प्रतिशत की मौजूदा सीमा के अधीन निवेश करने के लिए पात्र है, भले ही अंतिम स्वामित्व एक या अधिक के हाथों में हो।

व्यक्तियों।

963

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

चूंकि यह स्पष्टीकरण केवल सरकार के मूल इरादे को दर्शाता है, इसलिए आवेदकों द्वारा 2 मई, 1983 से पहले किया गया लेकिन अनुमोदन के लिए लंबित निवेश पांच प्रतिशत के अधीन नहीं होना चाहिए।

छत। लंबित आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया जा सकता है।

यह पत्र स्पष्ट रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. मान मोहन सिंह को व्यक्तिगत रूप से दिया गया था और उन्होंने पत्र पर निम्नलिखित समर्थन किया था:

" मैंने एफ. एस. और एफ. एम. के साथ इस मामले पर चर्चा की है। इस मामले को सी. सी. पी. ए. ने मंजूरी दे दी है। इस प्रकार हमें ईमानदारी से परिणामी कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे है।

एनआरआई योजना के संबंध में सरकार द्वारा स्पष्टीकरण के संबंध में प्रेस नोट जारी करने के संबंध में वित्त मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ चर्चा की गई। इस बात पर सहमति बनी है कि दिल्ली में ही रिजर्व बैंक द्वारा शाम 6:30 बजे प्रेस नोट जारी किया जाएगा।

हमें बताया गया है कि एफ. एस. का अर्थ वित्त सचिव, वित्त मंत्री का अर्थ वित्त मंत्री और राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अर्थ सी. सी. पी. ए. है।

जैसा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नोट में उल्लेख किया गया है, उसी दिन रिजर्व बैंक द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके तहत सरकार ने इसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों द्वारा निवेश के लिए योजना ने स्पष्ट किया था कि उनका मूल इरादा यह था कि भारतीय कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों में प्रत्यक्ष और पोर्टफोलियो निवेश की सुविधाएं और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में जमा विदेशी कंपनियों, साझेदारी फर्मों, ट्रस्टों, समितियों और अन्य निकायों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए जिनमें

स्वामित्व/लाभकारी हित अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन अंततः भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के गैर-निवासी व्यक्तियों द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत की सीमा तक रखा गया था। प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि सरकार ने भी यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक विदेशी निकाय पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत इक्विटी पूंजी का एक प्रतिशत तक निवेश करने का पात्र है, भले ही इस तरह के निकाय में अंतिम स्वामित्व/लाभकारी ब्याज एक या अधिक 964 के हाथों में हो।

यदि निवेश 2 मई, 1983 के बाद किया गया था तो भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासी व्यक्ति कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत की कुल सीमा के अधीन। द.

इस योजना के तहत निवेश करने के इच्छुक विदेशी निकायों को नियंत्रक, रिजर्व को अपने आवेदन जमा करने थे। बैंक ऑफ इंडिया, विनिमय नियंत्रण विभाग, बॉम्बे। विदेशी निकायों को अनिवासी (बाहरी) खाता योजना के तहत भारत में विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए अधिकृत बैंकों के साथ खाते बनाए रखने की आवश्यकता थी।

19.9.1983 पर, रिजर्व बैंक ने अनुभाग के तहत परिपत्र संख्या 18 भी जारी किया। 73 (3) एफ. ई. आर. ए. हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि

पहले वृत्ताकार। उसी दिन (19.9.1983), रिजर्व बैंक ने एक टेलेक्स संदेश के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक को 13 कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से खरीदे गए डीसीएम और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों के बदले भुगतान करने के लिए विदेश से कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा प्रेषित धन जारी करने की अपनी अनुमति से अवगत कराया, बशर्ते कि विचाराधीन शेयरों को 2 मई, 1983 तक खरीदा गया हो। यह भी उल्लेख किया गया था कि शेयरों की खरीद 2 मई, 1983 तक और उसके साथ हुई मानी जाएगी, यदि दलालों के अनुबंध नोटों द्वारा प्रमाणित फर्म खरीद प्रतिबद्धताओं में प्रवेश किया गया था और शेयरों को संबंधित दलालों के अनुबंध नोटों में उल्लिखित मूल्य पर ऐसी फर्म प्रतिबद्धताओं के अनुसार वितरित किया गया था/लिया जाएगा। शेयरों की खरीद के लिए अनुमति देने वाले पत्र का पालन करने के लिए कहा गया था। इसके बाद उसी दिन एक पत्र आया जिसमें 13 कंपनियों के समूह को रिजर्व बैंक से दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों में निवेश करने और अपने पास रखने की मंजूरी दी गई।

कंपनी विषय, जहां खरीद 2 मई, 1983 के बाद की गई थी, प्रत्येक निवेशक कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत की समग्र सीमा के अधीन। 2 मई, 1983 तक की गई खरीद 5 प्रतिशत की सीमा के अधीन नहीं थी। 2 मई, 1983 तक खरीदे गए शेयरों के अंकित मूल्य की संख्या के साथ-साथ 2 मई, 1983 के बाद खरीदे गए शेयरों, यदि कोई हों, के विवरण के बारे में जानकारी का अनुरोध किया गया था।

13 गैर-निवासी कंपनियों की ओर से अन्य भारतीय कंपनियों के शेयरों/डिबेंचरों की खरीद के लिए भी भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से बाजार मूल्य पर अनुमति दी गई थी।

इस शर्त के अधीन कि शेयर/डिबेंचर विदेश से प्राप्त नए प्रेषण और/या आवेदक कंपनियों के अनिवासी (बाहरी) खाते में रखे गए धन से खरीदे जाएंगे जो बैंकर के साथ खोले जाने हैं। 965 में प्रत्यावर्तन लाभों के साथ इक्विटी शेयरों की खरीद की जा सकती है।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी का एक प्रतिशत, 5 प्रतिशत की कुल सीमा के अधीन। एक अन्य शर्त यह थी कि अनुमति के तहत अर्जित शेयरों को अनिवासी निवेशक कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी में उनके पंजीकरण की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए। अनुमति पत्र की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध होनी थी।

इस बीच, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार को 13 गैर-निवासी कंपनियों द्वारा शेयरों की खरीद के संबंध में आरोपों को दोहराते हुए 23.7.83,5.9.1983,16.9.1983 और 17.9.1983 पर कई उग्र पत्र लिखे। हालांकि रिजर्व बैंक ने गैर-निवासी कंपनियों को 19.9.83 पर आवश्यक अनुमति प्रदान की, भारतीय रिजर्व बैंक ने 22.10.1983 पर, शायद उस दृढ़ता को देखते हुए जिसके साथ एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने काम करना जारी रखा

गैर-निवासी कंपनियों के खिलाफ आरोप और शायद खुद को और संतुष्ट करने के लिए, पंजाब नेशनल बैंक को पत्र लिखकर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के दिनांक 5 और 17 सितंबर 83 के पत्रों, डीसीएम के दिनांक 11 और 24 अगस्त 83 के पत्रों और उनके अधिवक्ताओं के पत्रों में उठाए गए मुद्दों पर एक रिपोर्ट मांगी। पत्रों की प्रतियां पंजाब नेशनल बैंक को भेज दी गईं, जिन्होंने बदले में दलालों राजा राम भसीन एंड कंपनी से पूछा। रिजर्व बैंक के पत्र में उठाए गए विभिन्न मुद्दों के बारे में उन्हें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। राजा राम भसीन एंड कंपनी ने जवाब दिया

12.12.1983 और इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि ये सवाल रिजर्व बैंक द्वारा 19.9.1983 पर अपनी अनुमति देने के बाद उठाए जा रहे हैं। हालाँकि, उन्होंने समझाया कि 2.5.1983 से पहले शेयरों की खरीद के संबंध में उनके या उनके ग्राहकों कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई थी। द.

कंपनियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों में उनके द्वारा 28.4.1983 तक की गई खरीद की तारीख पर कोई विवाद नहीं था। प्रश्न भ्रामक थे और केवल भ्रम पैदा करने का प्रयास थे। रिजर्व बैंक ने खुद को संतुष्ट किया था और निवेश करने के लिए कंपनियों की पात्रता की घोषणा की थी। शेयरों की बिक्री या खरीद के लिए सभी अनुबंध स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, उप-कानूनों और विनियमों के अधीन किए गए थे और वितरण

पहले किए गए अनुबंधों के अनुसार किया और स्वीकार किया जा सकता था। यह आवश्यक नहीं था कि हस्तांतरण विलेखों पर अनुबंध की तारीख के रूप में कंपनी पंजीयक की मुहर की तारीख होनी चाहिए।

28.4.1983 के बाद भी डिलीवरी ली जा सकती है। हस्तांतरण विलेखों में बताई गई तारीखें हस्तांतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरण विलेखों के निष्पादन की तारीखें थीं और उनकी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. पी. की तारीख से कोई प्रासंगिकता नहीं थी।

3 एस सी आर।

966

डिलीवरी की तारीख की खरीद। हस्तांतरण विलेख में दिखाया गया बिक्री प्रतिफल स्टाम्प शुल्क की गणना के उद्देश्य से हस्तांतरण विलेख पर बताई गई तारीखों पर प्रचलित दर पर भुगतान किया जाना था, न कि वास्तविक तिथि या खरीद पर। बेनामी नामों पर कोई शेयर नहीं खरीदे गए। जिन प्रश्नों के उत्तर अब मांगे गए थे, वे पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष थे और अनुमति देने से पहले उनके द्वारा विचार किया गया था।

राजा राम भसीन एंड कंपनी ने 27.12.1983 पर एक और पत्र लिखा।

इस प्रश्न के संबंध में कि क्या शेयर भारतीय रिजर्व बैंक से भारत में जुटाए गए रुपये के ऋण से खरीदे गए थे। यह था।

उन्होंने कहा कि बिना किसी कारण का खुलासा किए पंजाब नेशनल बैंक के पास लगभग Rs.107 करोड़ का प्रेषण था। शेयर पहले ही खरीदे जा चुके थे और परिणामस्वरूप, दलालों को विक्रेता दलाल से डिलीवरी लेनी पड़ती थी और उन्हें पैसे का भुगतान करना पड़ता था। अन्यथा दलालों को भुगतान न करने पर चूककर्ता घोषित किया जाएगा। परिसर में, दलालों को डिलीवरी लेनी पड़ती थी और भुगतान की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसके लिए रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।

इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने रिजर्व बैंक को पत्र लिखा।

उनके द्वारा उठाया गया और

बैंक ऑफ इंडिया ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए दोहराया कि उन्होंने रिजर्व बैंक के दिनांकित 19.9.1983 पत्र में निहित निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य किया था। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और डी. सी. एम. लिमिटेड द्वारा उठाए गए अन्य सभी बिंदुओं के लिए आवश्यक उत्तर

दलाल। इसलिए उन्होंने दलालों को लिखा और दलालों ने जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि कोई अवैधता नहीं की गई थी। द.

दलालों की टिप्पणियों का सारांश दिया गया और फिर यह जोड़ा गया कि दलालों को उनके टेलेक्स संदेश और दिनांकित 19.9.1983 पत्र द्वारा बताए गए RBI के निर्देशों के अनुसार ₹2,000 की राशि जारी की गई थी।

रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति देने के बाद

भारत सरकार ने शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने का एक और प्रयास किया। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने एक बार फिर अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने अपने पत्र 13.10.83 में कहा कि इसके अलावा

भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न निदेशक मंडल का शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने का निर्णय अन्य आधारों पर भी आधारित था जो वैध बने रहे। हम यहां उल्लेख कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय के समक्ष, निदेशक मंडल द्वारा उल्लिखित अन्य सभी आधारों को छोड़ दिया गया था, सिवाय इसके कि निदेशक मंडल की अनुमति की कमी से संबंधित आधार को छोड़कर। भारतीय रिजर्व बैंक। उच्च न्यायालय के समक्ष, निदेशकों द्वारा संचरण द्वारा पारित एक प्रस्ताव दायर किया गया था और यह था

प्रभाव:

967

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

" यह समाधान किया गया कि 8 जून, 1983 की निदेशक जांच और स्थानांतरण समिति की रिपोर्ट के पैरा 7 में या 29 अगस्त, 1983 की रिपोर्ट के पैरा 6,7 और 8 में निहित अस्वीकृति के आधार पर किसी अन्य कार्यवाही में निर्णय लेने का बोर्ड का इरादा नहीं है और बोर्ड एतद्द्वारा यह संकल्प करता है कि -

किसी भी कार्यवाही में उक्त आधारों पर भरोसा करें।

उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में भी रियायत दर्ज की:

" पैरा 214: याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि याचिकाकर्ता शेयरों के पंजीकरण से इनकार करने के अन्य आधारों पर निर्णय नहीं चाहते हैं, और इस तरह एफ. के. आर. ए. की धारा 29 के तहत पूर्व अनुमति प्राप्त करने में विफलता अस्वीकृति का एकमात्र आधार बनी रही। उत्तरदाताओं ने आग्रह किया कि चूंकि शेयरों को पंजीकृत करने से इनकार करने के अन्य आधारों पर अब दबाव नहीं डाला गया है और इस रिट में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है

याचिका, न्यायालय को इस पर जाने से इनकार कर देना चाहिए सवाल करते हैं। यह खरीद की वैधता और खरीद से इनकार करने पर टुकड़ों में निर्णय लेने के बराबर होगा।

रजिस्टर, जो किसी वाद के मामले में भी अनुज्ञेय नहीं है, जो सिद्धांत, विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, रिट याचिका उत्परिवर्तन पर भी लागू होता है।पैरा 215: क्या न्यायनिर्णयन के लिए कोई सजीव मुद्दा है और क्या याचिकाकर्ताओं का अधिकार क्षेत्र है, इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अलग या अमूर्त रूप से नहीं देखा जा सकता है।

पैरा 216: हमारे विचार में, इस विवाद को उठाने में कुछ प्रासंगिक कारकों की अनदेखी की जा रही है। भारत संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और पी. एन. बी. और अन्य प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं द्वारा खरीदे गए शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत नहीं करने के लिए लिए गए निर्णय की शुद्धता पर विवाद करते हैं। 4 17 तक। प्रतिवादी No.19 ने धारा सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. पी. के तहत अपील को प्राथमिकता दी है।

3 एस सी आर।

111 कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष कंपनी अधिनियम और वह अभी भी लंबित है। उत्तरदाता सं। 20 और 21, स्टॉक-ब्रोकर, इस पर जोर देना जारी रखते हैं

शेयरों के पंजीकरण के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार। डी. एन. डावर ने वित्तीय संस्थानों की ओर से अपने द्वारा हस्ताक्षरित 6.1.1984 पर लिखित नोट लिखा और निदेशक मंडल से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की।

निर्णय लें। इसके अलावा याचिकाकर्ता-कंपनी को समय-समय पर इन शेयरों के धारकों को इन शेयरों पर लाभांश का भुगतान करना पड़ता है। इन शेयरों पर प्रति वर्ष रु. 7,50,000 की राशि का लाभांश स्पष्ट रूप से उन लोगों को देय है जिनके नाम पर शेयर कंपनी की पुस्तकों में पंजीकृत हैं। यदि देय राशि का भुगतान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता-कंपनी और उसके निदेशकों को कंपनी अधिनियम के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा। लाभांश के भुगतान का सवाल साल दर साल दोहराया जाएगा। वास्तव में, अंतरिम लाभांश के भुगतान के सवाल पर, जबकि प्रतिवादी-कंपनियां लाभांश के भुगतान के हकदार होने का दावा करती हैं क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदे हैं, याचिकाकर्ता भुगतान पर आपत्ति जताते हैं क्योंकि पूर्व अनुमति के बिना खरीदे गए शेयरों के हस्तांतरण का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है।

प्रभावित और लाभांश का भुगतान उन व्यक्तियों को नहीं किया जा सकता जिनके शेयर पंजीकृत नहीं हैं। जब याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 2 दिसंबर 1983 को आई. एफ. सी. आई. के कार्यकारी निदेशक डी. एन. डावर को एक पत्र संबोधित किया, जिसमें प्रतिवादी-कंपनी द्वारा खरीदे गए शेयरों के संबंध में अंतरिम लाभांश को रोकने के निर्णय पर उनकी टिप्पणियां आमंत्रित की गईं, तो उन्होंने 17 दिसंबर, 1983 को अपने पत्र के माध्यम से निम्नलिखित जवाब दिया:

" चूंकि लाभांश का भुगतान, जैसा कि आपके पत्र में उत्तर के तहत संदर्भित किया गया है, से संबंधित है -

20 जुलाई 1983 को निदेशक मंडल द्वारा हल किए गए अंतरिम लाभांश में दूसरी राय के अनुसार इसे रोकने में कानूनी बाधा प्रतीत नहीं होती है। हालांकि इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी कानूनी राय को देखते हुए, हम इस मामले को उनके स्पष्टीकरण के लिए कानून मंत्रालय, कंपनी मामलों के विभाग को भेज रहे हैं। उनसे सुनने के बाद हम इस विषय पर आपसे बात करेंगे।

969

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

इस प्रकार यह मामला भारत सरकार के संदर्भ में था और सवाल यह था कि क्याशेयरों का हस्तांतरण प्रभावी होना चाहिए या नहीं और इन शेयरों पर कौन लाभांश प्राप्त करने का हकदार होगा, यह 17 दिसंबर 1983 को भी एक लाइव इश्यू था और रिट याचिका दायर होने तक भी इसका फैसला नहीं किया गया था। प्रत्यर्थियों में से किसी ने भी हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए याचिकाकर्ता-कंपनी के पास दर्ज किए गए शेयरों को वापस नहीं लिया है। शेयरों की बिक्री और याचिकाकर्ता-कंपनी के साथ उनके हस्तांतरण के लिए आवेदन दर्ज करने पर, उसे निर्णय लेना पड़ा। कंपनी ने पंजीकरण के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि उनके कानूनी सलाहकारों की सुविचारित राय के अनुसार, यह वैध और उचित है। आर. बी. आई. के साथ-साथ अन्य उत्तरदाता

अलग-अलग

और उनके कानूनी सलाहकार एक विचार रखते प्रतीत होते हैं। बेशक, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उस कानूनी राय को अदालत के समक्ष नहीं रखा गया है और न ही अदालत को इसका खुलासा करने के लिए उनसे अनुरोध करने का अधिकार है। यह दर्ज किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, श्री नरीमन ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि यह याचिकाकर्ताओं की ओर से एक त्रुटि थी जिसका उल्लेख किया गया था

रिट याचिका की सुनवाई। जो भी हो, तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं ने एक अलग मत व्यक्त किया

इस कानूनी मुद्दे पर विचार करें और उसी पर जोर दिया है

इस अदालत के सामने। सवाल यह है कि क्या पूर्व अनुमति है

सायन आवश्यक है या नहीं इस प्रकार से निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है

द्वारा खरीदे गए शेयरों के हस्तांतरण की अस्वीकृति

उत्तरदाता Nos.4 से 16 तक। यह समय से उत्पन्न होता है

भविष्य में इस तरह की खरीदारी कब और कब की जाती है।

याचिकाकर्ता-कंपनी को स्वयं विचार करना होगा

जब भी ऐसे शेयर प्रस्तुत किए जाते हैं

पंजीकरण। यहाँ तक कि प्रतिवादी No.18 के सॉलिसिटर भी

27 फरवरी 1984 के अपने पत्र में उन्हें संबोधित किया गया

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा:

शेयरों के हस्तांतरण के बारे में विवाद सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. के पूरे विस्तार में बढ़ रहा है।

देश और शेयरधारक संघों, वाणिज्य मंडलों और अन्य सार्वजनिक निकायों सहित विभिन्न मंच ऐसे मुद्दों पर टिप्पणियां और सुझाव देते रहे हैं।

उन्होंने उस पत्र में विशेष रूप से यह भी कहा कि वे रिट याचिका की सुनवाई में उस पत्र का उल्लेख करेंगे। यह कानूनी मुद्दा निर्णय के लिए तब उत्पन्न होगा जब भी याचिकाकर्ताओं द्वारा शेयरों को पंजीकृत नहीं करने की कार्रवाई पर किसी भी हस्तांतरणकर्ता या शेयरों के हस्तांतरणकर्ता द्वारा सवाल उठाया जाता है। यदि प्रत्यर्थी अभी भी शेयरों के पंजीकरण पर जोर दे सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा शेयरों की खरीद के बाद प्रत्यर्थी कंपनियों को दी गई अनुमति वैध है, जो दावा प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 द्वारा लिए गए रुख द्वारा दृढ़ता से समर्थित है, तो याचिकाकर्ता निश्चित रूप से एक अनुरोध करने के हकदार हैं।

इस संबंध में घोषणा। इस ओर से ऐसी घोषणात्मक राहत दी जा सकती है या नहीं, इस पर नियत समय में विचार किया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के पास घोषणा की मांग करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। फैसले के बावजूद

निदेशक मंडल द्वारा लिया गया, कंपनी पर शेयरों के हस्तांतरण का दबाव बना हुआ है। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा लिया गया रुख गलत है, तो वे क़ानून के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के तहत हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए बाध्य होंगे।

याचिकाकर्ता-कंपनी और पंजीकृत डाक ए. डी. द्वारा भेजे गए, ने अनुरोध किया था कि बोर्ड का निर्णय 29 अगस्त 1983 के निदेशकों द्वारा शेयरों को पंजीकृत करने से इनकार करने की समीक्षा की जानी चाहिए। जवाब में याचिकाकर्ता

कंपनी ने 13 अक्टूबर 1983 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि विवादित परिपत्र और भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र के बावजूद, पंजीकरण करने से इनकार कर दिया गया है।विभिन्न अन्य कारणों से अच्छा बना रहा। उस पत्र में याचिकाकर्ताओं-कंपनी ने भी विवाद किया

कंपनियों ने किया था

दावा करें कि तेरह गैर-निवासी 2 मई 1984 से पहले शेयर खरीदे गए। याचिकाकर्ता-कंपनी ने इस प्रकार कहा कि

बाद में दी गई अनुमति वैध नहीं है और अन्य कारणों से शेयरों को पंजीकृत करने से इनकार करना एल. आई. सी. v.

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

971

अभी भी अच्छा है। बेशक, रिट याचिका की सुनवाई में, बजाज ऑटो लिमिटेड बनाम में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए। एन. के. फिरोदिया

ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 321 विद्वान वकील श्री नरीमन ने स्वीकार किया कि शेयरों को पंजीकृत नहीं करने के लिए अन्य आधारों को पंजीकरण से इनकार करने के समर्थन में नहीं दबाया जा रहा था। इसलिए, उत्तरदाताओं के लिए यह तर्क दिया गया कि यह पत्र इंगित करेगा कि उस स्तर पर याचिकाकर्ताओं ने भी स्वीकार किया कि

अनुमति, एक्सएच के तहत दी गई "। बी "और एक्सट"। सी "ने खरीद को मान्य किया और अब रास्ते में नहीं खड़ा रहा

शेयरों का पंजीकरण। हम इस विवाद से सहमत होने में असमर्थ हैं; सबसे पहले क्योंकि यदि खंड के तहत: 29 वैध खरीद के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता थी, पत्र में इस तरह का कोई भी बयान

याचिकाकर्ता-कंपनी इस तरह के हस्तांतरण को मान्य नहीं कर सकती है ताकि शेयरों के पंजीकरण का दावा करने के लिए खरीद का हकदार हो। द्वारा हस्तांतरण का कोई भी पंजीकरण

याचिकाकर्ता-कंपनी एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 के साथ पठित धारा 19 का उल्लंघन करेगी; दूसरा, पत्र की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि -

कंपनी और उसके निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया रुख कि खरीद अमान्य है

पूर्व अनुमति प्राप्त करना छोड़ दिया गया था। आगे भले ही एक्सएच '। बी 'और एक्सएच'। सी 'को अनुमति के अनुदान के रूप में माना जाता है, यह अनुमति देने के बराबर होगा।

याचिकाकर्ता-कंपनी स्पष्ट रूप से कहती है कि "नहीं संदर्भ के रूप में आर. बी. आई. द्वारा अनुमति का स्थायी अनुदान

आप द्वारा ", इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि खरीद के बाद अनुमति का अनुदान अच्छा नहीं हो सकता है और

उस अनुमति का आधार। तथ्य यह है कि वे वास्तव में अनुमति को चुनौती देने के लिए आगे बढ़े

रिट याचिका के माध्यम से प्रदान किया गया यह पूरी तरह से स्थापित करता है कि कंपनी ने हस्तांतरण के लिए अपने दायित्व को अस्वीकार कर दिया

विवादित परिपत्र के बल पर शेयर और

पत्र। जबकि, यह याचिकाकर्ताओं का मामला है

कि डी. एन. डावर निदेशकों में से एक, के साथ सशस्त्र

सभी वित्तीय संस्थानों के लिए बोलने का अधिकार

एल. आई. सी. सहित इस बात पर जोर देना जारी रखा कि रिट

याचिका वापस ली जाए। अन्य दबावों के अलावा

याचिकाकर्ता पर लगाया गया-कंपनी और उसका प्रबंधन

निदेशक, जिसकी पहले ही चर्चा की जा चुकी है, की बैठक में

6 जनवरी 1984 को आयोजित याचिकाकर्ता-कंपनी के निदेशक मंडल, डी. एन. डावर ने सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. पी. के चार पृष्ठ प्रस्तुत किए।

3 एस सी आर।

बोर्ड पर जोर देते हुए हस्ताक्षरित नोट

निदेशक संस्थान के पास जमा किए गए चेकों को वापस बुलाएंगे

ऋणों के पुनर्भुगतान और निकासी की दिशा में उपाय

अदालत में दायर रिट याचिका और ध्यान न देने के लिए

वित्तीय के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार का

संस्थान और प्रबंधन। बोर्ड ऑफ

हालांकि, निर्देशक उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं थे।

इसके विपरीत, इसने रिट दाखिल करने की पुष्टि की

नौ निदेशकों ने इस अदालत में एक हलफनामा दायर कियारिट याचिका दायर करने का समर्थन करना। यह भी है

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वित्तीय संस्थान, यह पाते हुए कि यूनानी के बावजूद

डी. एन. डावर द्वारा उनकी ओर से किया गया अनुरोध

निदेशक मंडल की बैठक, कंपनी और इसके प्रबंध निदेशक रिट को वापस लेने से इनकार कर रहे थे

याचिका और शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावित करना,

शेयरों का पंजीकरण प्राप्त करने का पिछला उद्देश्य,

याचिकाकर्ता के ई. जी. एम. की मांग की-कंपनी तो

ताकि वे एक नियंत्रित बहुमत हासिल कर सकें

एल. आई. सी. की कार्रवाई (प्रतिवादी सं. 18) जो खुद से उनके पास 30 प्रतिशत शेयर हैं और इसके साथ ही अन्य

वित्तीय संस्थान, जो सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं

डावर के पास 52 प्रतिशत शेयर हैं और यह दुर्भावनापूर्ण है और इसकी गणना की जाती है।

उन शेयरों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए जो थे

एफ. ई. आर. ए. के उल्लंघन में खरीदा गया। परिधि में

बाद में दिया जाना वैध नहीं है और इनकार करना अन्य कारणों से शेयर पंजीकृत करें जो अभी भी अच्छे हैं।

बेशक, रिट याचिका की सुनवाई में,

बजाज में

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करें

ऑटो लिमिटेड v. एन. के. फिरोदिया, विद्वान वकील श्री

नरीमन ने स्वीकार किया कि नहीं के लिए अन्य आधार

शेयरों को पंजीकृत करने के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा था पंजीकरण से इनकार का समर्थन।

प्रत्युत्तर का दृश्य और इससे पहले दी गई रियायत

, कंपनी द्वारा पंजीकरण करने से इनकार करने के संबंध में

973 शेयरों के लिए एकमात्र आधार जो आवश्यक है

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

हम इस बात पर विचार करें कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति क्रम में थी।

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है

शेयरों का हस्तांतरण, किसी ने सोचा होगा कि यह बाद में खरीदारों या शेयरों के विक्रेताओं पर निर्भर है, अगर वे इस मामले में आगे की उचित कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने के लिए इतने इच्छुक थे।

शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने का मामला। हालाँकि यह वे नहीं थे जो आगे बढ़े लेकिन यह एस्कॉर्ट्स लिमिटेड था जिसने रिट याचिका दायर की थी जिसमें से वर्तमान अपीलें उत्पन्न होती हैं। वे.

समझाएँ कि परिस्थितियों का दबाव ऐसा था कि उनके पास संविधान के Art.226 के तहत अदालत जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि 18.10.83 पर, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की,

आई. सी. आई. सी. आई., आई. एफ. सी., आई. डी. बी. आई. और यू. टी. आई. यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 30 प्रतिशत शेयर जीवन बीमा निगम के पास हैं, 16 प्रतिशत यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास हैं और 6 प्रतिशत सामान्य बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों के पास हैं। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के अनुसार, इस बैठक में

उनके प्रतिनिधियों ने विभिन्न का पूरा विवरण दिया

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों की खरीद में कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा की गई अवैधताएँ लेकिन वे बार-बार थीं

संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा दबाव डाला गया कि वे अपने निदेशक मंडल को अपने पहले के इनकार पर पुनर्विचार करने के लिए कहें

शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करें। यह कहा गया था कि श्री पटेल यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वित्तीय

जिन संस्थानों के पास 52 प्रतिशत शेयर थे, वेप्रबंधन को अपनी इच्छानुसार हटाने की स्थिति। वहाँ अन्य थे

वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें। श्री नंदा, एस्कॉर्ट्स के अध्यक्ष

सीमित था

श्री पुंजा, आई. डी. बी. आई. के अध्यक्ष से मिलने का अनुरोध किया और

जीवन बीमा निगम के निदेशक जो अभी-अभी लौटे थे

विदेशों में। श्री पुंजा ने जोर देकर कहा कि इस बैठक में भी यह कहा गया था

कि तेरह कपारो द्वारा खरीदे गए शेयरों का हस्तांतरणकंपनियों को पंजीकृत किया जाना चाहिए। फिर से 1.11.83 पर एक था

एस्कॉर्ट्स के वकीलों और के कानूनी सलाहकारों के बीच बैठक

वित्तीय संस्थान। इनके बीच एक और बैठक हुई

श्री नंदा और श्री पुंजा 9.11.83 पर जब एस्कॉर्ट्स के श्री नंदालिमिटेड ने श्री पुंजा से विलय के प्रस्ताव में तेजी लाने का अनुरोध किया

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के साथ गोएट्ज़ इंडिया लिमिटेड और इसके लिए प्रस्ताव

अंतर-संस्थागत बैठक में वित्तीय संस्थान 9 तारीख की दोपहर को आयोजित किया गया। श्री नंदा को बाद में श्री नंदा ने सूचित किया।

डावर ने कहा कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी 974

और स्वीकार कर लिया लेकिन औपचारिक मंजूरी के लिए श्री नंदा के साथ श्री पुंजा की चर्चा का इंतजार करना होगा। इसके बाद, यह कहा गया कि श्री नंदा को श्री पुंजा ने सूचित किया कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को कपारो समूह की कंपनियों द्वारा खरीदे गए कुछ शेयरों को पंजीकृत करना होगा। जवाब में श्री नंदा ने श्री पुंजा को सूचित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं कपारो समूह द्वारा शेयरों की खरीद की जांच कर रहा है।

कंपनियों और इसलिए श्री पुंजा को जाँच के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 10.11.83 पर श्री सेन गुप्ता, के नियंत्रक

श्री नंदा को पूंजी निर्गम के बारे में फोन किया गया और जोर देकर कहा कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को कम से कम कपारो समूह द्वारा खरीदे गए कुछ शेयरों को तुरंत पंजीकृत करना चाहिए। 12.11.83 पर श्री पुंजा ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि कुछ शेयरों को कम से कम तुरंत पंजीकृत किया जाना चाहिए

1y. आई. डी. 1 पर श्री नंदा ने आई. सी. आई. सी. आई. के अध्यक्ष श्री नाडकर्णी से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि श्री पुंजा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड द्वारा शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने पर सबसे अधिक परेशान थे। इसके बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने लिखा कि

नए सिरे से जोर दिया गया कि शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत किया जाना चाहिए। आई. डी. 1 पर श्री नंदा ने श्री पुंजा के साथ टेलीफोन पर चर्चा की, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी देने का सवालऋणों के पूर्व भुगतान और डिबेंचर जारी करने के लिए विलय, कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा खरीदे गए शेयरों के हस्तांतरण के रजिस्टर के सवाल के साथ जुड़ा हुआ था। श्री नंदा के अनुसार यह बातचीत उनके द्वारा उसी दिन श्री पुंजा को संबोधित एक पत्र में समकालीन रूप से दर्ज की गई थी।

जबकि 'टेलीग्राफ' और 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' ने श्री स्वराज पॉल का एक बयान प्रकाशित किया कि लड़ाई अब थी सरकार और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के प्रबंधन के बीच और यह कि वह खुद को पराजित समझेंगे यदि सरकार पहले के बिना डिबेंचर जारी करने के लिए एस्कॉर्ट्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है।

उसे खरीद लिया। श्री स्वराज पॉल ने यह भी कहा था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर (डॉ. मान मोहन सिंह, हमारे देश के एक अत्यंत सम्मानित सिविल सेवक) आवेदन कर रहे थे।दोहरा मापदंड और केंद्रीय वित्त मंत्री को गलत जानकारी दे रहा था। (यदि रिपोर्ट किया गया कथन सही है, तो हम इसे केवल चिकना, अशिष्ट और उद्दंड होने के रूप में वर्णित कर सकते हैं।

किसी विदेशी नागरिक से अनुमति मांगता है

रिजर्व बैंक भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करेगा। शायद

ये उन बाजारों के तरीके हैं जिनमें वे काम करते हैं। लोग 975

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

दोहरी दृष्टि से पीड़ित लोग दूसरों में दोहरे मानदंड देखने के लिए तैयार होते हैं। हम न तो उनके आचरण और न ही उनके बयानों की सराहना करते हैं। हम मानते हैं कि डॉ. मान मोहन सिंह का श्री स्वराज पॉल की तरह प्रेस में जाना और खुद को एक अप्रिय विवाद में शामिल करना उचित नहीं था)। 24.12.83 पर, केंद्रीय वित्त मंत्री (श्री.

प्रणब मुखर्जी), कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटिनम जुबली समारोह में, जिसमें उन्होंने कुछ बड़ी निजी कंपनियों के इक्विटी शेयरों में वित्तीय संस्थानों की प्रमुख स्थिति का उल्लेख किया और कहा, "अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही प्रभावी साधन है।" एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के अनुसार यह तथ्यात्मक पृष्ठभूमि थी कि वे बॉम्बे के उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर हुए। एस्कॉर्ट्स के श्री नंदा की एक उल्लेखनीय रणनीति यहाँ विशेष उल्लेख के योग्य है। रिट याचिका 29.12.83 पर दायर की गई थी और उसी दिन कुछ अंतरिम निर्देश भी मांगे गए थे। उसी दिन श्री नंदा ने श्री पुंजा के कार्यालय में वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की थी, जिसमें श्री नंदा को बोर्ड ऑफ एस्कॉर्ट्स में यू. टी. आई. के एक प्रतिनिधि को शामिल करने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था और उन्हें आगे बताया गया था कि गोएट्ज़ लिमिटेड के विलय का प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो सकता है क्योंकि इससे वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत हो जाएगी।

प्रतिशत लेकिन यह मामला अभी भी विचाराधीन था। श्री नंदा की ओर से जो उल्लेखनीय और संदिग्ध आचरण माना जा सकता है, वह है उन्हें सूचित करने में उनकी विफलता।

उसी दिन रिट याचिका दायर करने के बारे में वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि।

इस प्रकार बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर 83 की रिट याचिका (आईडी1) शायद सुरक्षात्मक और खाली करने से पहले की हड़ताल दोनों थी। रिट याचिका अपनी लंबाई और प्रार्थनाओं की संख्या के लिए उल्लेखनीय है। रिट याचिका 172 पृष्ठों की है और कई खंडों में आने वाले असंख्य दस्तावेज अब हमारे सामने रखे गए हैं। मूल रूप से तेरह प्रार्थनाएँ (ए) से (एम) थीं। इन प्रार्थनाओं में बाद में चार और प्रार्थनाएँ जोड़ी गईं। प्रार्थना

(क), (ख) और (ग) यह घोषणा करने की मांग करते हैं कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत परिपत्र अवैध और अमान्य है और इसे मनमाना और संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए जारी किया गया है, क्योंकि यह वैधानिक नियमों का दुरुपयोग है।

प्राधिकरण के रूप में और संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (सी) और 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है। प्रार्थना (घ) एक घोषणा के लिए है कि

कपारो समूह 976 द्वारा और/या उसकी ओर से की गई शेयरों की खरीद

लिमिटेड अवैध हैं और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम और स्टॉक एक्सचेंज के उप-कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। प्रार्थना (ई), (एफ), (जी), (एच), (आई) फिर से परिपत्र संख्या 18 दिनांकित

19.9.83 और दिनांकित 19.9.83 पत्र से संबंधित हैं। प्रार्थना (जे) की ओर निर्देशित है संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित करना। प्रार्थना (के) पहली प्रतिवादी (भारत संघ) को शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए कंपनी पर दबाव डालने से रोकने के लिए है। प्रार्थना (1) प्रार्थना (जे) और (के) के संदर्भ में अंतरिम राहत के लिए है। प्रार्थना (एम) याचिका के खर्च के लिए है। इस पर ध्यान देना दिलचस्प होगा।

इस स्थिति में कि विद्वान एकल न्यायाधीश, जिनके समक्ष प्रारंभिक सुनवाई के लिए रिट याचिका आई थी, ने प्रार्थना (घ) के संबंध में नियम निसी जारी नहीं करना उचित समझा। विद्वान न्यायाधीश ने प्रार्थना (घ) के संबंध में एक नियम निसी जारी करने से इनकार करते हुए एक बोलने का आदेश दिया। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड द्वारा उस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी और जहां तक प्रार्थना (घ) का संबंध है, आदेश अंतिम हो गया। याचिकाकर्ता की कार्रवाई का पूरा कारण चारों ओर केंद्रित हैकापारो ग्रुप लिमिटेड द्वारा और उसकी ओर से किए गए शेयरों की खरीद और यदि उन खरीद को निर्विवाद छोड़ दिया जाता है, तो एक छोड़ दिया जाता है।

आश्चर्य है कि रिट याचिका में क्या बचा है, विशेष रूप से इस तथ्य का विचार कि कंपनी के निदेशक मंडल ने पहले ही हस्तांतरण को पंजीकृत करने की उनकी अनुमति से इनकार कर दिया था

शेयर। परिपत्र संख्या 18 दिनांक 19.9.83 और दिनांकित 19.9.83 से संबंधित प्रार्थनाएँ केवल प्रार्थना (घ) की सहायता के लिए थीं, जो, जैसा कि हम देखते हैं, रिट याचिका में मुख्य प्रार्थना थी। लेकिन हम ऐसे किसी भी प्रारंभिक आधार पर मामले का निपटारा करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। जाहिरा तौर पर, जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रार्थना के संबंध में एक नियम निसी जारी करने से इनकार कर दिया (घ) उनका मतलब यह था कि शेयरों की खरीद के लेनदेन को अलग से और व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इसमें शामिल होगा

प्रत्येक लेन-देन के संबंध में साक्षय का संयोजन और सामान्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के प्रांत के बाहर होगा। विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं जो कहा है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने प्रार्थना (घ) पर आपत्ति का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है:

" यह भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थना (घ) पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और यदि याचिकाकर्ता 'बी' और 'सी' को प्रदर्शित करने तक सीमित से परे की दलीलों का आग्रह करना चाहते हैं तो उन्हें एक सामान्य कार्रवाई के लिए या कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष लंबित अपील में इन दलीलों का आग्रह करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए।

उन्होंने आपत्ति का निपटारा किया और निष्कर्ष निकाला:

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

" जैसा कि पहले कहा गया है, मेरा मानना है कि प्रार्थना (घ) में जो मांगा गया है, उसे सामान्य रूप से रिट कोर्ट के कार्य से परे माना जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं होना चाहिए

यह इंगित करने के लिए लिया गया है कि मामले के इस पहलू के संबंध में एस्कॉर्ट्स और याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा की गई विभिन्न शिकायतों में कोई वारंट नहीं है। वास्तव में यह स्पष्ट होगा कि याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा 19 सितंबर 1983 के अपने पत्र में जो कहा गया था वह पर्याप्त और गंभीर था, लेकिन इन आरोपों को भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं लिया गया है।

Ex. B हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति में दिनांकित 19.9.83 और Ex-C परिपत्र में उल्लेख कर सकते हैं।

रिट याचिका दायर करने के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे बाद में रिट याचिका में 18वें प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था), जिसके पास अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ कंपनी में कुल शेयरों की संख्या का 52 प्रतिशत हिस्सा था, ने कंपनी के नौ अंशकालिक निदेशकों को हटाने और उनके स्थान पर नौ अन्य लोगों को नामित करने के उद्देश्य से एक असाधारण आम बैठक आयोजित करने के लिए कंपनी को दिनांक 1 पर एक अनुरोध जारी किया। यह आरोप लगाते हुए कि भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी और भारत संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और कपारो ग्रुप लिमिटेड द्वारा कंपनी को शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए मजबूर करने और

रिट याचिका को वापस लेते हुए, रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में उपयुक्त संशोधन करने और बैठक को मनमाना, अवैध, अधिकार से परे आदि घोषित करने के लिए प्रार्थना (आई. ए.), (आई. बी.), (आई. सी.) और (आई. डी.) जोड़ने की मांग की। रिट याचिका थी

संशोधित किया गया। पैराग्राफ 149ए (1) से (44) को जोड़ा गया और साथ ही प्रार्थना (आई. ए.), (आई. बी.), (आई. सी.) और (आई. डी.) को भी जोड़ा गया।

उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत जांच के बाद उनका सारांश दिया

निष्कर्ष निकालना और निम्नलिखित तरीके से राहत प्रदान करना:

" नियम निसी को निम्नानुसार निरपेक्ष बनाया गया है:

एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (बी) अनिवार्य है। कोई भी एनआरआई निवेशक किसी भारतीय कंपनी में शेयर खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है।

धारा के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना

29 (1) (ख) एफ. ई. आर. ए. की; ऐसी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के बिना शेयरों की कोई भी खरीद।

पूर्व अनुमति अवैध है। न तो भारत संघ और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक को धारा 75 के तहत या उसके तहत निर्देश जारी करके अन्यथा आदेश देने का अधिकार है।

एफ. ई. आर. ए. की धारा 73 (3); और न ही उन्हें शेयरों की खरीद के बाद अनुमति देने का अधिकार है ताकि ऐसी खरीद को मान्य किया जा सके या बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए खरीदे गए शेयरों को रखने की अनुमति दी जा सके। 17 सितंबर, 1983 की प्रेस विज्ञप्ति। ए), 19 सितंबर, 1983 का परिपत्र (एक्सएच। (ख) और 19 सितंबर, 1983 का पत्र। ग) पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं कर सकते हैं ताकि एनआरआई कंपनियों द्वारा किए गए शेयरों की खरीद को मान्य किया जा सके जो खरीद की तारीख पर अयोग्य थे और न ही वे पूर्व प्राप्त किए बिना शेयरों की खरीद को अधिकृत कर सकते हैं।

एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (बी) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति। जहाँ तक विवादित प्रेस विज्ञप्ति की बात है,

परिपत्र और पत्र उत्तरदाता को अनुमति देता है

आर. बी. आई. की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना शेयरों की खरीद करने वाली कंपनियां, वे एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (बी) के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं और धारा 75 और आर. बी. आई. के तहत भारत संघ में निहित शक्तियां हैं।

सेक के तहत। 73 (3) FERA से। इस हद तक, वे संभावित और पूर्वव्यापी दोनों रूप से शून्य और निष्क्रिय हैं।

सक्रिय रूप से। हालाँकि, विवादित प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र पोर्टफोलियो निवेश में संशोधन के बराबर है। पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों वाली योजना शुरू की गई परिपत्र संख्या 9 दिनांक 14 अप्रैल, 1982 (एक्स. 'जी') के तहत और ऐसा संशोधन केवल संभावित रूप से संचालित होता है। परमादेश की एक रिट प्रत्यर्थियों को प्रतिबंधित करने वाली संख्या जारी करेगी। 1 और 2 कोई भी निर्देश जारी करने से -

(क) 19 तारीख के पत्र के अनुसार प्रत्यर्थी-कंपनियों (जो इस रिट याचिका की विषय वस्तु हैं) द्वारा खरीदे गए शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करना।

सितंबर, 1983 (एक्स. 'सी'); और ((ख) 19 सितंबर, 1983 के उक्त परिपत्र को लागू करने से रोकने के लिए। बी) और प्रतिवादी कंपनियों द्वारा खरीदे गए शेयरों के संबंध में 19 सितंबर 1983 (एक्स. 'सी') का उक्त पत्र जो इस रिट याचिका का विषय है।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

एक घोषणा होगी कि प्रतिवादी No.18 की विवादित मांग सूचना जारी करने की कार्रवाई धारा के प्रावधानों के विपरीत है। 284 एल. आई. सी. अधिनियम की धारा 6 के तहत एल. आई. सी. में निहित शक्तियों और एल. आई. सी. अधिनियम के प्रावधानों के इरादे के विपरीत। विवादित माँग सूचना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। विवादित मांग नोटिस जारी करने में एल. आई. सी. की कार्रवाई संपार्श्विक उद्देश्य के लिए की गई एक मनमानी और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है।

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। भारत संघ और भारतीय रिज़र्व बैंक, उत्तरदाता Nos.1 और 2, इस संबंध में एल. आई. सी. की कार्रवाई के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। उनके और केंद्रीय वित्त मंत्री के खिलाफ लगाए गए इस दुर्भावनापूर्ण आरोप हैं -

अप्रमाणित। उक्त सूचना के अनुसरण में आयोजित बैठक में पारित अनुरोध सूचना और समाधान रद्द कर दिए जाते हैं। एक अनिवार्य रिट उत्तरदाताओं को उस सूचना के अनुसरण में आयोजित किसी भी बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में कोई भी कदम या कार्रवाई करने से रोकने के लिए जारी करेगी, जिसमें विवादित मांग सूचना पर या उसके तहत या आगे कोई कदम या कार्रवाई की जाएगी।

ऊपर जो बताया गया है, उससे यह देखा जाता है कि विचार किए जाने वाले मुख्य प्रश्नों में से एक यह है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पास पूर्व-कार्योत्तर देने की शक्ति या अधिकार था। सेक के तहत अनुमति। 29 (1) (ख) भारत में किसी कंपनी द्वारा शेयरों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम

भारत में निगमित या क्या ऐसी अनुमति आवश्यक रूप से "पूर्व" अनुमति होनी चाहिए थी।

हम यह पता लगाने के लिए किसी भी शब्दकोश का उल्लेख करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि 'अनुमति' शब्द का अर्थ क्या है या नहीं।

बाद की अनुमति को शामिल करने के लिए पर्याप्त कठोर। हम केवल सर शाह सुलेमान, सी. जे. का उल्लेख करेंगे। शाकिर हुसैन बनाम में कहा गया है। चंदू लाल और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1931 अल्लाह, 567।

" आम तौर पर अनुमोदन और अनुमति के बीच का अंतर यह है कि पहले में अधिनियम अस्वीकृत होने तक अच्छा रहता है, जबकि दूसरे मामले में, यह अनुमति प्राप्त होने तक प्रभावी नहीं होता है। लेकिन बाद में प्राप्त अनुमति पिछले अधिनियम को मान्य कर सकती है।

हम पहले ही सेक निकाल चुके हैं। 29 (1) और हम देखते हैं कि उपयोग की गई अभिव्यक्ति "रिजर्व की सामान्य या विशेष अनुमति" है।

बैंक ऑफ इंडिया "और यह कि अभिव्यक्ति" पूर्व "या" पूर्व "शब्द द्वारा योग्य नहीं है। हालांकि हम इस बात से अवगत हैं कि "पूर्व" आर "" पूर्व "शब्द निहित हो सकता है यदि प्रासंगिक स्थिति या कानून का उद्देश्य और डिजाइन इसकी मांग करता है, तो हम ऐसी कोई मजबूर करने वाली परिस्थितियां नहीं पाते हैं जो इस तरह के किसी भी शब्द को पढ़ने को उचित ठहराती हैं।

सेक में निहितार्थ। 29 (1) . दूसरी ओर, सभी संकेत इसके विपरीत हैं। हम अधिनियम की कई अलग-अलग धाराओं के अवलोकन पर पाते हैं कि जब भी यह सोचा गया कि "पूर्व अनुमति" आवश्यक थी, संसद "पूर्व अनुमति" अभिव्यक्ति का उपयोग करके अपने इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता से बेखबर नहीं रही है। सेक में। 27 (1) और 30, हम पाते हैं कि अभिव्यक्ति 'अनुमति' शब्द 'पूर्ववर्ती' शब्द द्वारा योग्य है और धारा 8 (1), 8 (2) और 31 में, अभिव्यक्ति सामान्य या विशेष अनुमति 'द्वारा योग्य है शब्द "पिछला", जबकि धारा 13 (2), 19 (1), 19 (4), 20,21 (3), 24,25,28 (1) और 29 में, 'अनुमति' और 'सामान्य' या 'विशेष अनुमति' पद अयोग्य रहते हैं। द.

संसद द्वारा एक ही अधिनियम के कई प्रावधानों में सरल अनुमति और पूर्व अनुमति के बीच किए गए अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या हम इसे स्पष्ट करने के लिए दबाव नहीं डाल सकते हैं। विधियों की व्याख्या करने का यह तरीका नहीं है। उचित तरीका यह है कि उपयोग को उचित महत्व दिया जाए और साथ ही अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में योग्य शब्दों का उपयोग करने में चूक की जाए। एक प्रावधान में योग्यता के उपयोग और दूसरे प्रावधान में इसके गैर-उपयोग के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हमारे विचार में, संसद ने जानबूझकर सेक में योग्यता शब्द 'पूर्ववर्ती' से परहेज किया। 29 (1) ताकि भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमति देने के मामले में कुछ हद तक लोच के साथ निवेश किया जा सके

भारतीय कंपनियों में शेयर खरीदने के लिए अनिवासी कंपनियाँ। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, निस्संदेह विदेशी मुद्रा अर्जित करना, संरक्षित करना, विनियमित करना और संग्रहीत करना है। अधिनियम की पूरी योजना और रूप-रेखा उसी दिशा में निर्देशित है। मूल रूप से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 को एक अस्थायी उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसे 1957 के संशोधन अधिनियम द्वारा स्थायी रूप से क़ानून पुस्तिका में रखा गया था। 1957 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "भारत में विदेशी मुद्रा की कमी बनी हुई है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारे विदेशी मुद्रा संसाधनों का राष्ट्रीय हित में संरक्षण किया जाए।" 1973 में, पुराने अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसका लंबा शीर्षक है: कुछ भुगतानों, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों में लेनदेन को विनियमित करने वाले कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम, ट्रांस 981

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा और मुद्रा और सर्राफा के आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाली कटौती।

देश "। हम पहले ही सेक का उल्लेख कर चुके हैं। 76 जो इस बात पर जोर देता है कि केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई प्रत्येक अनुमति या लाइसेंस

या भारतीय रिजर्व बैंक को देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण की इच्छा से प्रेरित किया जाना चाहिए। इसलिए, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय आर्थिक हित में अधिनियमित एक क़ानून है। निर्माण करते समयराष्ट्रीय हित में अधिनियमित कानूनों में, हमें आवश्यक रूप से अधिनियम द्वारा विचार की गई व्यापक तथ्यात्मक स्थितियों को लेना होगा और इसके प्रावधानों की व्याख्या करनी होगी ताकि आगे बढ़ सकें और उस विशेष राष्ट्रीय हित को विफल न किया जा सके जिसकी प्रगति कानून द्वारा प्रस्तावित है। वैधानिक व्याख्या के पारंपरिक मानदंडों को राष्ट्रीय हित की व्यापक धारणाओं के अनुरूप होना चाहिए। यदि कानून को उस दृष्टिकोण से देखा और समझा जाता है, जैसा कि वास्तव में यह अनिवार्य है कि हम ऐसा करते हैं, तो हमें व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं मिलती है।

'अनुमति' का अर्थ 'अनुमति' है, पिछली या बाद की, और हम 'अनुमति' को केवल 'पिछली अनुमति' तक सीमित करने के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं। हमारे विचार में जो आवश्यक है वह यह है कि अनिवासी कंपनियों द्वारा शेयरों की खरीद के लिए किसी स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। कंपनी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एफ. एस. नरीमन द्वारा हमारे समक्ष एक तर्क को जोरदार ढंग से दबाया गया था कि अधिनियम की योजना से पता चलता है कि अनुभाग द्वारा अनुध्यात अनुमति। 29 (1) केवल पूर्व अनुमति हो सकती है, इस परिस्थिति के बावजूद कि 'पिछला' शब्द योग्य नहीं है

सेक में अभिव्यक्ति 'सामान्य या विशेष अनुमति'। 29 (1) हालाँकि यह कई अन्य प्रावधानों में है। श्री नरीमन के अनुसार, इस अधिनियम को न केवल आकर्षित करने के लिए बनाया गया था, बल्कि विदेशी मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने के लिए भी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि प्रावधान बहुत सख्त थे। हमें श्री नरीमन से सहमत होने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विदेशी मुद्रा के प्रवाह का अधिनियम द्वारा स्वागत किया जाता है, लेकिन प्रवाह भी निम्न के अधीन है -

सख्त नियंत्रण अन्यथा कुछ ही समय में देश की अर्थव्यवस्था विदेशी धन से भर जाएगी और विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन यह वास्तव में प्रभावित नहीं करता है Sec.29 (1) में 'अनुमति' अभिव्यक्ति की व्याख्या। भारतीय रिजर्व बैंक पूर्व-कार्योत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है।

अनुमति जब भी यह पाया जाता है कि व्यवसाय शुरू किया गया है या [1985] एसयूपीपी।

शेयर उसकी पूर्व अनुमति के बिना खरीदे गए हैं। ऐसे मामलों में, जहां भी भारतीय रिजर्व बैंक को किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य का संदेह होता है, हम मानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक न केवल अनुमति देने से इनकार करेगा, बल्कि आगे भी कार्रवाई करेगा

हम तक कि सेकंड के दौरान। 29 (2) और 29 (4) ने किसी भी गतिविधि को जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए उचित प्रावधान किया एस में उल्लिखित प्रकृति। 29 (1) (क) और एस में उल्लिखित चरित्र की कंपनी के शेयर रखना जारी रखें। 29 (1) (ख) यदि ऐसा कार्य किया गया था और ऐसे शेयर अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को रखे गए थे, तो ऐसी गतिविधि को जारी रखने या ऐसे शेयरों को रखने की अनुमति के लिए आवेदन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया गया था यदि ऐसी गतिविधि शुरू की गई थी या यदि ऐसे शेयर अधिनियम के प्रारंभ के बाद प्राप्त किए गए थे, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना। यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अधिनियम के प्रारंभ के बाद अधिग्रहित किसी गतिविधि या शेयरों के लिए अनुमति देने के लिए किसी निर्धारित प्रपत्र का अभाव, स्पष्ट रूप से पूर्व अनुमति की आवश्यकता की अनिवार्य प्रकृति का संकेत था। यह प्रस्तुत किया गया था कि शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में जो भी तर्क संभव था, यह स्पष्ट था कि धारा में उल्लिखित प्रकृति की कोई गतिविधि नहीं थी। 29 (1) (क) रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना शुरू किया जा सकता है। चूंकि रिजर्व बैंक का 'सामान्य या विशेष अनुमति' शब्द सेक में आता है। 29 (1) दोनों एल. आई. सी. बनाम।

खंड (ए) और (बी) अभिव्यक्ति को खंड (बी) के संदर्भ में वही अर्थ दिया जाना था जो इसे खंड (ए) के संदर्भ में दिया जाना था और वह यह था कि पूर्व अनुमति आवश्यक थी। तर्क आकर्षक है और पूरी तरह से सारहीन नहीं है, लेकिन यह इस धारणा पर आगे बढ़ता है, जिसके लिए कोई आधार नहीं है, कि इसके तहत व्यवसाय करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है।

सेक. 29 (1) (क) अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमति होनी चाहिए। हम यह नहीं सोचते हैं कि संसद का उद्देश्य पूर्ण रूप से निर्धारित करना था कि अनु. द्वारा अनुध्यात अनुमति। 29 (1) पूर्व अनुमति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सेक का प्रमुख उद्देश्य। 29 खंड (क) द्वारा अनुध्यात गतिविधि के भारत में संचालन

और खंड (ख) में उल्लिखित चरित्र के भारत में किसी उपक्रम या शेयरों के अधिग्रहण को विनियमित करना और पूरी तरह से प्रतिबंधित करना नहीं है। अंतिम उद्देश्य भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह को आकर्षित करना और नियंत्रित करना है। यदि यह बहुत कुछ स्पष्ट है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संसद का इस मामले में बहुत कठोर रवैया अपनाने का इरादा नहीं था और इसलिए इसे छोड़ दिया गया था

कोई सुरक्षित नहीं

भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके पास पूर्व या पूर्व-कार्योत्तर, सशर्त या बिना शर्त अनुमति देने का अधिकार हो सकता है। रिजर्व बैंक से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह विवेकपूर्ण तरीके से और देश के सर्वोत्तम हित में विवेक का उपयोग करेगा।

विदेशी मुद्रा के मामले में घोषित सरकारी राजकोषीय नीति।

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की ओर से यह तर्क दिया गया था कि सेक। 13 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जो केंद्रीय को सक्षम बनाता है सरकार, राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, यह आदेश देने के लिए कि कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के अलावा भारत में कोई सोना या चांदी नहीं लाएगा या नहीं भेजेगा।

विदेशी मुद्रा या भारतीय मुद्रा, अप्रभावी हो जाएगी यदि अभिव्यक्ति 'सामान्य या विशेष अनुमति' सेक में होती है। 13 निम्नलिखित को शामिल करने के लिए समझा जा सकता है

अनुमति ली। तो, यह आग्रह किया गया था, दोनों एस में। 13 और सेक. 19 और 29 अभिव्यक्ति को बाद में बहिष्कृत करने के लिए समझा जाना चाहिए।अनुमति ली। इस समर्पण में कोई बल नहीं है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 67 में प्रावधान है कि प्रतिबंध

सेक द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित। 13 यह माना जाना चाहिए कि धारा के तहत लगाया गया है। 11 सीमा शुल्क अधिनियम, और, आगे, बनाता हैतदनुसार लागू सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधान। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 केंद्र सरकार को किसी भी निर्दिष्ट विवरण के माल के आयात या निर्यात को पूरी तरह से या शर्तों के अधीन प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। धारा 13 और 67 [1985] एस. यू. पी. पी. को एक साथ पढ़ें।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के तहत, यह देखा जाता है कि धारा. 13 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम एक निषेध के रूप में कार्य करता है और इसलिए, रिजर्व बैंक द्वारा निषिद्ध वस्तुओं के आयात को मान्य करने और सीमा शुल्क अधिनियम द्वारा निर्धारित परिणामों

से बचने के लिए बाद में अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। इसलिए, धारा 19 और 29 की व्याख्या करने के लिए धारा 13 के सादृश्य को स्वीकार करना संभव नहीं है।

अनुमति प्राप्त करने में विफलता के बाद होने वाले परिणामों की बहुत गंभीर प्रकृति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

रिजर्व बैंक और यह परिस्थिति कि इस बात के प्रमाण का भार भी कि अपेक्षित अनुमति प्राप्त की गई थी, उस व्यक्ति पर था जिस पर अधिनियम या नियम या अधिनियम के तहत बनाए गए निर्देश या आदेश के प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया था या उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, इस प्रकार मेन्स्रिया को अपराध के एक आवश्यक घटक के रूप में खारिज कर दिया गया था। यह सच है कि जहां अनुमति निर्धारित की गई है, वहां आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं करने के परिणाम गंभीर और गंभीर भी हैं। यह भी सच है कि सबूत का बोझ है

व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई और इसके परिणामस्वरूप पुरुषत्व की व्याख्या खारिज के रूप में की जा सकती है। लेकिन इससे यह अपरिहार्य निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि धारा 29 द्वारा अनुध्यात अनुमति अनिवार्य रूप से पूर्व अनुमति है। धारा 50 के तहत या धारा 56 के तहत कार्रवाई अनिवार्य नहीं है और धारा 56 के तहत अभियोजन के मामले में, अपराधी को इस आवश्यकता से और अधिक संरक्षित किया जाता है कि शिकायत धारा 61 (2) (ii) द्वारा निर्दिष्ट अधिकारियों में से एक या अन्य द्वारा की जानी चाहिए और तब भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को यह दिखाने का अवसर देने के बाद कि उसके पास आवश्यक अनुमति थी। हम. मान लीजिए कि जब यह दिखाने के लिए बुलाया जाता है कि उसके पास आवश्यक अनुमति थी, तो अपराध का आरोपी व्यक्ति संबंधित अधिकारी को संतुष्ट कर सकता है कि उसने अनुमति के लिए आवेदन किया था क्योंकि उसे अनुमति प्राप्त करने की उचित संभावना थी। हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि सामान्य विवेक एक विदेशी नागरिक, जो दुनिया का आदमी है, विशेष रूप से वाणिज्यिक दुनिया का है, को भारतीय कंपनियों के शेयरों में अपना पैसा निवेश करने से पहले अनुमति लेने और प्राप्त करने के लिए चेतावनी देगा। यदि नहीं, तो वह अनुमति से इनकार करने का मौका देगा और अन्य आकस्मिक प्रश्नों का जोखिम उठाएगा। मौका और जोखिम, निश्चित रूप से, वहाँ नहीं होता अगर सब कुछ साफ होता। यहां तक कि अगर अनुमति दी जाती है, तो यह प्रत्यावर्तन को रोकने जैसी शर्तों के अधीन हो सकती है।

लाभ, जो उसके लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। यह एक और मौका है जब वह पूर्व-पोस्ट-फैक्टो अनुमति मांगता है।

सी. ई. 985

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

श्री नरीमन की दलीलों में यह था कि संसद ने 'अनुमति' शब्द से अलग 'पुष्टि' शब्द का उपयोग करने का ध्यान रखा, जहां उसे लगा कि इस तरह की पुष्टि पर्याप्त है, जैसा कि अनुभाग में है। 19 (5) . श्री

नरीमन के अनुसार, संसद अधिनियम के प्रारंभ के बाद अस्तित्व में आने वाले लेन-देन की पुष्टि करने के लिए एक प्रावधान कर सकती थी, यदि वह इस तरह से सोचती थी, लेकिन चूंकि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन 'अनुमति' शब्द को चुना, इसलिए उसे उस धारा का पालन करना चाहिए। 29 केवल पूर्व अनुमति पर विचार करता है। हम इस समर्पण के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं देखते हैं। किसी भी शब्दकोश या समानार्थक शब्दों की किसी भी पुस्तक के संदर्भ से पता चलेगा कि प्रत्येक शब्द के अर्थ के अलग-अलग रंग होते हैं और अलग-अलग शब्दों का एक ही अर्थ हो सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है। यदि संसद का इरादा पिछली और बाद की अनुमति दोनों को समझना था, तो 'पुष्टि' शब्द बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हालांकि 'अनुमति' शब्द का व्यापक रूप से अर्थ निकालने की अनुमति हो सकती है, लेकिन 'पुष्टि' शब्द का उपयोग कभी भी 'पिछली अनुमति' के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। पुष्टि शब्द सेकंड में पूरी तरह से गलत होगा। 29 .

कंपनी की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यदि 'अनुमति' शब्द का अर्थ पूर्व-पोस्ट-फैक्टो को शामिल करना था

अनुमति, यह वास्तव में पूर्वव्यापी देने के बराबर होगा अनुमति के लिए संचालन। रिजर्व बैंक, यह कहा गया था कि पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं था। हमारे विचार में, पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम को यहां प्रस्तुत स्थिति में आयात नहीं किया जा सकता है। पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम व्याख्या का एक नियम है जिसका उद्देश्य निहित अधिकारों में हस्तक्षेप को रोकना है जब तक कि स्पष्ट रूप से प्रदान या आवश्यक रूप से निहित न हो। ऐसी स्थिति में जहां कोई निहित अधिकार शामिल नहीं हैं, पूर्वव्यापीता के खिलाफ नियम का आह्वान करना एक नियम के कारण को भूलकर व्याख्या के नियम को वैधानिक दर्जा देना है।

हमारे सामने बहुत सख्ती से आग्रह किए गए समर्पणों में से एक यह था कि वही अधिकार जो मुख्य रूप से सौंपा गया थाविदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक को प्रशासित करने का कार्य स्वयं इस विचार का था कि अनु. 29 (1) (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की पूर्व अनुमति थी। हमारा ध्यान विनिमय नियंत्रण नियमावली के अनुच्छेद 24-ए. 1 की ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें पहले तीन वाक्य इस प्रकार हैं:

" सेक के संदर्भ में। 29 (1) (ख) विदेशी मुद्रा 986

विनियमन अधिनियम 1973, भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारत के बाहर निगमित कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी (न ही बैंकिंग कंपनी) हो, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना भारत में व्यापार, वाणिज्य या औद्योगिक गतिविधि करने वाली किसी भी कंपनी के शेयर प्राप्त नहीं कर सकता

है। सेक के तहत भी। 19 (1) (बी) और अधिनियम के 19 (1) (डी), किसी भी प्रतिभूति (जिसमें शेयर शामिल हैं) का हस्तांतरण और जारी करना

भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब शेयर हस्तांतरण या जारी करने की अनुमति दी गई हो।

सेक. के तहत अनिवासी निवेशक। 19 (1) (बी) या 19 (1) (डी) इसे स्वतः ही धारा के तहत अनुमति माना जाता है।

29 (1) (ख) उसके द्वारा शेयरों की खरीद के लिए।

श्री नरीमन का समर्पण दो गुना था। उन्होंने आग्रह किया कि अनुच्छेद 24-ए. 1 धारा के तहत जारी किया गया एक वैधानिक निर्देश था। 73 (3) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और, इसलिए, कानून का बल था और इसका पालन करना आवश्यक था। वैकल्पिक रूप से उन्होंने आग्रह किया कि यह अधिनियम के प्रावधान की आधिकारिक और समकालीन व्याख्या है और इसलिए, हमारी स्वीकृति का हकदार है। प्रस्तुतिकरण के पहले भाग का आधार विनिमय नियंत्रण नियमावली की प्रस्तावना में इस आशय का कथन था:

" इस नियमावली के वर्तमान संस्करण में 31 मई, 1978 तक परिपत्रों के रूप में अधिकृत विक्रेताओं को जारी किए गए स्थायी प्रकृति के सभी निर्देशों को शामिल किया गया है। एस. के. के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। 73 (3) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जो भारतीय रिजर्व बैंक को प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन निर्देश जारी करने का अधिकार देता है

विनिमय नियंत्रण। इसके बाद अधिकृत विक्रेताओं को इस नियमावली में निहित प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

समर्पण के इस हिस्से में कोई बल नहीं है। नियमावली के अवलोकन से पता चलता है कि यह अधिकृत विक्रेताओं, धन परिवर्तकों आदि के लिए एक प्रकार की मार्गदर्शक पुस्तक है और विभिन्न वैधानिक निर्देशों, निर्देशों, प्रशासनिक निर्देशों, सलाहकार राय, टिप्पणियों, टिप्पणियों, स्पष्टीकरण सुझावों आदि का एक संग्रह या संग्रह है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 24-ए. 1 को भारत में विदेशी निवेश के परिचय के रूप में शैलीबद्ध किया गया है। एल. आई. सी. वी. में कुछ भी नहीं है।

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

987

पूरा पैराग्राफ जो दूर से भी सेक के तहत एक निर्देश का सुझाव देता है। 73 (3) . पैराग्राफ 24-ए. 1 स्वयं सेक पर टिप्पणी की प्रकृति में प्रतीत होता है। 29 (1) (ख), सेक के तहत एक दिशा के बजाय। 73 (3) . सेक के तहत निर्देश। 73 (3) , हम देखते हैं, अलग-अलग तिथियों पर परिपत्र के रूप में

अलग से जारी किए जाते हैं। हमारे सामने ऐसा कोई परिपत्र नहीं रखा गया है जो पैराग्राफ 24-ए. 1 के किसी भी हिस्से से मेल खाता हो। हमें इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 24-ए. 1 अधिकृत विक्रेताओं के लाभ के लिए दिशानिर्देश का एक व्याख्यात्मक विवरण है। यह न तो वैधानिक है

निर्देश और न ही यह एक अनिवार्य निर्देश है। यह इस तरह पढ़ा जाता है जैसे कि यह प्रकृति में है और वास्तव में यह अधिकृत डीलरों को दी गई सलाह है कि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, ताकि बाद में ऐसा न हो। पैराग्राफ 24-ए. 1 में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति 'पूर्व अनुमति' का मतलब यह नहीं है कि

धारा 29 (1) (बी) और 19 (1) (बी) में पाई जाने वाली 'सामान्य और विशेष अनुमति' अभिव्यक्ति की सीमा को प्रतिबंधित करना। यह सामान्य प्रक्रिया को इंगित करने के लिए है जिसका पालन किया जा सकता है। श्री.

नरीमन ने तर्क दिया कि आवेदन और बाद की अनुमति देने के लिए निर्धारित प्रपत्रों में से कोई भी प्रदान नहीं किया गया था। यह इस स्पष्ट कारण से हो सकता है कि आम तौर पर कोई उम्मीद करेगा

अधिनियम से पहले अनुमति मांगी जाए और दी जाए। निश्चित रूप से, प्रपत्र अधिनियम, नियमों या निर्देशों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। एक के रूप में

मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश को यह कहने का शौक था कि 'यह है कुत्ता जो पूंछ को हिलाता है, न कि पूंछ जो कुत्ते को हिलाती है।

हम यह जोड़ सकते हैं कि इस न्यायालय को वासुदेव रामचंद्र शेलट बनाम में क्या कहने का अवसर मिला था। प्राणलाल जयानंद ठक्कर, [1975] 1 एस. सी. आर.

534 :

" किसी संचरण के पदार्थ की किसी कठोर रूप से निर्धारित रूप में अधीनता को सावधानीपूर्वक करना आवश्यक है।

प्राचीन और अप्रचलित न्यायशास्त्र का अवलोकन, स्वाद

डेंस "।

श्री नरीमन के अनुसार, भले ही हमें पता चला हो,

भारतीय कंपनी के शेयर खरीदने की अनुमतिभारतीय मूल या राष्ट्रीयता के गैर-निवासी निवेशक

एफ. ई. आर. ए. की धारा 29 (1) (बी) के बाद प्राप्त किया जा सकता है

क्रय के बाद, रिजर्व बैंक के पास ऐसी शक्ति समाप्त हो गई

पोर्टफोलियो निवेश योजना का निर्माण क्योंकि यह नहीं था

पोर्टफोलियो निवेश के तहत ऐसी कोई भी शक्ति अपने पास सुरक्षित रखें।

एस. के. के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषित योजना। 73 (3) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। हम कोई आधार नहीं देखते हैं।

योजना में ही इस तर्क के लिए। योजना बात नहीं करती है

किसी भी पूर्व या पूर्व अनुमति के लिए, और न ही हम 988 तक पहुँच सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. 3 एस सी आर।

यह समझें कि संसदीय विधान के तहत रिजर्व बैंक के पास मौजूद शक्ति को इस तरह से कम किया जा सकता है कि इसका उपयोग पूरी तरह से रोका जा सके। यह एक अधीनस्थ विधायी निकाय के लिए खुला हो सकता है कि वह संसद द्वारा निहित शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने के लिए उचित नियम और विनियम बनाए, ताकि कानून के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, लेकिन यह नहीं कर सकता है

खुद को सत्ता से अलग कर लें। इसलिए, हम यह बताने में असमर्थ हैं कि कैसे रिजर्व बैंक, यदि उसके पास एफ. ई. आर. ए. के तहत पूर्व-कार्योत्तर अनुमति देने की शक्ति है, तो वह योजना के तहत उस शक्ति से खुद को अलग कर सकता है। योजना के तहत निर्धारित प्रपत्रों के विशेष संदर्भ में तर्क दिया गया था। हम पहले ही बता चुके हैं कि योजना के तहत फॉर्म कानून को कम नहीं कर सकते हैं।

आगे बढ़ने से पहले, शेयरों में संपत्ति की प्रकृति, कानून के तहत शेयरों में संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कानून और एफ. ई. आर. ए. के प्रावधानों के प्रभाव की स्पष्ट तस्वीर होना उचित है। उस उद्देश्य के लिए, यह वांछनीय है कि हम शेयरों के अधिग्रहण, हस्तांतरण और पंजीकरण से संबंधित सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों को एक साथ पढ़ें। प्रासंगिक वैधानिक का उल्लेख करने के अलावा

प्रावधानों के अनुसार, हम इस विषय पर प्रमुख मामलों का भी उल्लेख करेंगे।

कंपनी अधिनियम की धारा 2 (46) "शेयरों" को "कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सेदारी" के रूप में परिभाषित करती है, और इसमें स्टॉक शामिल है।

सिवाय इसके कि जहां शेयरों और शेयरों के बीच अंतर व्यक्त या निहित हो। कंपनी अधिनियम की धारा 82 में कहा गया है कि "कंपनी में किसी भी सदस्य के शेयर या अन्य हित कंपनी की वस्तुओं द्वारा निर्धारित तरीके से हस्तांतरणीय चल संपत्ति होंगे।" धारा 84 कंपनी की आम मुहर के तहत एक प्रमाण पत्र बनाती है, जिसमें किसी भी सदस्य द्वारा रखे गए किसी भी शेयर को ऐसे शेयरों के लिए सदस्य के स्वामित्व के प्रथम दृष्टया साक्षय के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। धारा 87 कंपनी के प्रत्येक सदस्य को वहां कोई भी इक्विटी शेयर पूंजी रखने का अधिकार देती है-यानी ऐसे मामलों के संबंध में मतदान का अधिकार। पूँजी, कंपनी के समक्ष रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर, कंपनी की चुकता इक्विटी पूँजी के अपने हिस्से के

अनुपात में होने का उसका मतदान अधिकार। धारा 106 कुछ परिस्थितियों में 'शेयरों के विशेष वर्गों के धारकों के अधिकारों में परिवर्तन' का प्रावधान करती है। धारा 108 (1) किसी कंपनी को किसी कंपनी में शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से रोकती है जब तक कि

हस्तांतरण का उचित साधन हस्तांतरण द्वारा या उसकी ओर से या हस्तांतरणकर्ता एल. आई. सी. द्वारा या उसकी ओर से विधिवत मुहर लगाई गई और निष्पादित किया गया।

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

989

शेयरों से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ कंपनी को वितरित किया गया है। धारा 108 (ला) (ए) में हस्तांतरण के साधन को निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य विधिवत होना है। उस पर इस तरह की प्रस्तुति की तारीख की मुहर लगा दी गई। धारा 108 (1 ए) (बी) में विधिवत मुहर लगे उपकरण को वितरित करने का प्रावधान है।

इस मामले के उद्देश्य के लिए चिंतित। धारा 110 में शेयरों के हस्तांतरण के लिए आवेदन का प्रावधान है। धारा 111 (1) कंपनी के किसी भी शेयर के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने के लिए अपने लेखों के तहत कंपनी की शक्ति को संरक्षित करती है, और एस। 111 (3) इस तरह के इनकार के खिलाफ केंद्र सरकार को अपील करने का प्रावधान हैपंजीकरण करने के लिए। धारा 206 एक कंपनी को बाध्य करती है कि वह ऐसे शेयर के पंजीकृत धारक या उसके आदेश या उसके बैंकरों को छोड़कर किसी भी शेयर के संबंध में लाभांश का भुगतान न करे या जहां ऐसे वारंट के वाहक को या उसके बैंकर को शेयर के संबंध में शेयर वारंट जारी किया गया है। लाभांश के भुगतान में चूक को भी धारा के तहत दंडनीय बनाया गया है। 207. कंपनी के कम से कम एक सौ सदस्य या कुल सदस्यों की संख्या का दसवां हिस्सा बनाने वाले अन्य लोगों के साथ एक शेयरधारक को धारा के तहत अदालत में आवेदन करने का अधिकार है। 397 अप्रेस सायन के मामले में और सेक के तहत राहत के लिए। 398 कुप्रबंधन के मामले में राहत के लिए। धारा 428 'अंशदायी' को परिभाषित करती है और इसमें ऐसे किसी भी शेयर का धारक शामिल है जो पूरी तरह से भुगतान किए गए हैं। अंशधारक को, अंशदाता के रूप में, परिसमापन के लिए आवेदन करने का भी अधिकार है।

सेक के तहत कंपनी। 439. समापन पर, सेक। 475 न्यायालय को अपने बीच अंशदाताओं के अधिकारों को समायोजित करने में सक्षम बनाता है और

अधिशेष को उसके हकदार व्यक्तियों के बीच वितरित करना।

हमारे पास यहाँ भी कोई सूचना नहीं है सेक। 27 प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, जो यह उपबंध करता है कि किसी भी प्रतिभूति के धारक के लिए, जिसका नाम उक्त प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी की पुस्तकों पर दिखाई देता है, किसी भी वर्ष के लिए कंपनी द्वारा घोषित किसी भी लाभांश को

प्राप्त करना और बनाए रखना विधिसम्मत होगा, इसके बावजूद कि उक्त प्रतिभूति पहले ही उसके द्वारा विचार के लिए स्थानांतरित कर दी गई है, जब तक कि हस्तांतरणकर्ता, जो हस्तांतरणकर्ता से लाभांश का दावा करता है, ने प्रतिभूति और हस्तांतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज दर्ज नहीं किए हैं, जो कंपनी के साथ कंपनी द्वारा लाभांश देय होने की तारीख के पंद्रह दिनों के भीतर अपने नाम पर पंजीकृत होने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

हमें यहां आगे ध्यान देना होगा कि माल की बिक्री अधिनियम स्टॉक और शेयरों पर भी लागू होता है। माल की बिक्री अधिनियम की धारा 2 (7) 'माल' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है "कार्रवाई योग्य दावों और धन के अलावा हर प्रकार की चल संपत्ति; और इसमें स्टॉक और शेयर, उगाने वाली फसलें, घास और भूमि से जुड़ी या उससे जुड़ी चीजें शामिल हैं जो बिक्री से पहले या बिक्री के अनुबंध के तहत बेचे जाने के लिए सहमत हैं।

खरीदार को ऐसे समय पर हस्तांतरित किया जाता है जब अनुबंध के पक्ष इसे स्थानांतरित करने का इरादा रखते हैं। अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखते हुए इरादे का पता लगाया जा सकता है - पक्षों का आचरण और मामले की परिस्थितियाँ। जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक धारा 20 से 24 में निहित नियम उस समय के इरादे को निर्धारित करने के लिए हैं जब माल में संपत्ति खरीदार को दी जानी है। धारा 20 एक सुपुर्दगी योग्य स्थिति में विशिष्ट वस्तुओं से संबंधित है। धारा 21 विशिष्ट वस्तुओं को सुपुर्दगी योग्य स्थिति में रखने से संबंधित है। धारा 22 एक वितरण योग्य स्थिति में विशिष्ट वस्तुओं से संबंधित है जब विक्रेता को कीमत का पता लगाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। धारा 23 अप्रमाणित वस्तुओं की बिक्री और विनियोग से संबंधित है और धारा 24 अनुमोदन या "बिक्री या वापसी पर" भेजे गए सामान से संबंधित है।

हमने शुरुआत में उल्लेख किया है और वास्तव में हमने विदेशी मुद्रा विनियमन के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को निकाला है।

अधिनियम जो हमारे समक्ष मामले के लिए प्रासंगिक है। हमने देखा है कि सेकंड के दौरान। 19 (1) (ख) यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति, रिजर्व बैंक के सामान्य या विशेष प्रावधान के अलावा, हस्तांतरण नहीं करेगा। किसी प्रतिभूति को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को या उसके पक्ष में, किसी प्रतिभूति में कोई ब्याज बनाना या हस्तांतरित करना।

29 (1) (ख) यह प्रावधान करता है कि भारत के बाहर रहने वाला कोई भी व्यक्ति (चाहे वह भारत का नागरिक हो या न हो) या कोई कंपनी भारत में लागू किसी कानून के तहत निगमित नहीं है या जिसमें गैर-निवासी ब्याज 40 प्रतिशत से अधिक है, रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के अलावा इसमें शेयर नहीं खरीदेगा।

भारत या कोई भी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग करने वाली कंपनी। सेक के प्रावधान। 29 धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कहा गया है। 47 जो किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अनुबंध या समझौते में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम या निर्देश या आदेश के किसी भी प्रावधान के संचालन से बचता है या बचाता है।

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

991

यह भी प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों में यह आवश्यकता है कि कोई भी चीज जिसके लिए केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक की अनुमति आवश्यक है, किसी भी राशि की वसूली के लिए भारत में लाई जाने वाली कानूनी कार्यवाही को नहीं रोकेगी, जो उक्त प्रावधानों के अलावा ऋण, हर्जाने या अन्यथा के रूप में देय होगी, इस शर्त के तहत कि किसी भी राशि के भुगतान के लिए किसी भी निर्णय या आदेश को लागू करने के उद्देश्य से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जब तक कि केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, राशि का भुगतान करने की अनुमति न दे। हम पहले भी सेक का उल्लेख कर चुके हैं। 19 (4) जो यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति, रिजर्व बैंक की अनुमति के अलावा, किसी भी रजिस्टर में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में प्रवेश नहीं करेगा, यदि उसके पास यह संदेह करने का कोई आधार है कि हस्तांतरण में धारा के प्रावधानों का कोई उल्लंघन शामिल है। 19 . धारा 48,50,56 और 63 अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम के तहत जारी नियमों, आदेशों और निर्देशों का पालन न करने के परिणामों को निर्धारित करती है और दंडात्मक संबंध और अभियोजन का प्रावधान करती है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधान, जिनका हमने अभी उल्लेख किया है, यह निर्धारित करते प्रतीत नहीं होते हैं कि बिना प्राप्त किए शेयरों की खरीद

रिजर्व बैंक की अनुमति अमान्य होगी। दूसरी ओर, ऐसे लेन-देन से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

के रूप में वापस लिया जा सकता है

इस शर्त के अधीन कि कोई राशि ऋण, हर्जाना या अन्यथा, जब तक और जब तक आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है। हम पहले ही मान चुके हैं कि अनुमति पूर्व-कार्योत्तर हो सकती है। यदि पूर्व-कार्योत्तर अनुमति दी जा सकती है, तो स्पष्ट रूप से लेन-देन एक मूर्खतापूर्ण और बिना किसी हस्तक्षेप के नहीं हो सकता है।

प्रभाव जो भी हो।

प्रस्तुतियों के दौरान हमें मानेकजी के पास भेजा गया

पेस्टनजी भरुचा और अन्र। वी. वाडीलाल साराभाई एंड कंपनी, 52 I.A.92, बैंक ऑफ इंडिया बनाम। जमशेदजी ए. एच. चिनॉय, ए. आई. आर. 1950

वी. लॉडिस बैंक लिमिटेड 1982 ए. सी. 584, चरणजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 41, माथलोन और अन्य। वी. बॉम्बे

लाइफ एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 385 और वासुदेव रामचंद्र शेलट बनाम। प्राणलाल जयानंद ठक्कर, (ऊपर) ए. के.

रमैया वी. रिजर्व बैंक 1970 (1) एम. एल. जे. 1 और बालिव चोपड़ा आई. ए. आर.

1971 (2) दिल्ली 637। हमने उन सभी को पढ़ा है और हमें लगता है कि यह है

पर्याप्त है अगर हम उनमें से कुछ का उल्लेख करते हैं।

चरणजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ (ऊपर),

मुखर्जी, जे. ने एक कंपनी में एक शेयरधारक के अधिकारों का सारांश दिया।

निम्नलिखित तरीके से:

" एक शेयरधारक के रूप में याचिकाकर्ता के पास निस्संदेह एक

कंपनी में रुचि। उनकी रुचि का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

उसके हिस्से से और हिस्सा चल 992 है।

भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार संपत्ति, उससे जुड़ी ऐसी संपत्ति की सभी घटनाओं के साथ। आम तौर पर, वह लाभांश के रूप में शेयरों से उत्पन्न आय का आनंद लेने का हकदार है; किसी भी अन्य विपणन योग्य वस्तु की तरह शेयर को बंधक या गिरवी के माध्यम से बेचा या स्थानांतरित किया जा सकता है। उनके नाम पर हिस्सेदारी रखने से उन्हें निदेशकों के चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिलता है और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के मामलों के प्रबंधन में भाग लेते हैं। यदि अधिकांश शेयरधारक उसका पक्ष लेते हैं, तो वह एक प्रस्ताव पारित करा सकता है जो कंपनी के लिए बाध्यकारी होगा और अंत में, वह कंपनी को बंद करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध परिसंपत्तियों का वितरण हो सकता है।

शेयरधारक "।

यह देखना दिलचस्प है कि न्यायमूर्ति मुखर्जी ने अपनी राय के दौरान यह विचार व्यक्त किया कि एक निगम, जो समुदाय के लिए आवश्यक रूप से आवश्यक वस्तु के उत्पादन में लगा हुआ है, उसका अपना एक सामाजिक चरित्र है और इसे मुख्य रूप से या केवल उन्हीं लोगों की चिंता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो इसमें अपना पैसा निवेश करते हैं।

माथेलोन और ओआरएस में। वी. बॉम्बे लाइफ एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर), हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता के बीच संबंधों का प्रश्न।

कंपनी की बही में हस्तांतरण के पंजीकरण से पहले शेयरों के हस्तांतरणकर्ता पर हस्तांतरणकर्ता के अधिकार के संबंध में विचार किया जाने लगा।

कंपनी। शेयरों के हस्तांतरण पर हस्तांतरणकर्ता लाभकारी ब्याज का मालिक बन गया, हालांकि कानूनी अधिकार के साथ था

हस्तांतरणकर्ता न्यासी और 'सेस्टूई क्यू ट्रस्ट' का संबंध स्थापित किया गया था और हस्तांतरणकर्ता उन सभी उचित निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य था जो हस्तांतरणकर्ता दे सकता था और वह लाभांश का न्यासी बन गया और साथ ही वोट देने के अधिकार का न्यासी भी बन गया। न्यासी और न्यासी का संबंध इस परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुआ कि जब तक हस्तांतरणकर्ता का नाम हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता इक्विटी के बीच एक उचित लेनदेन लाने के लिए शेयरधारकों के रजिस्टर पर नहीं लाया गया था, तब तक हस्तांतरणकर्ता को एक रचनात्मक न्यासी का दर्जा दिया गया था और यह उसे न्यास के बेचे गए शेयरों से जुड़े संपत्ति अधिकारों के सभी लाभों को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य करता था। इक्विटी के सिद्धांत को उन मामलों में विस्तारित नहीं किया जा सकता था जहां हस्तांतरणकर्ता ने उचित परिश्रम के साथ कंपनी के रजिस्टर में एक सदस्य के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाए थे और इस बीच, कुछ अन्य विशेषाधिकार या

993 के परिणामस्वरूप नए शेयरों की खरीद के अवसर पैदा हुए।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

पहले से अर्जित शेयरों का स्वामित्व। हस्तांतरणकर्ता द्वारा उसके द्वारा बेचे गए हिस्से के संबंध में एक रचनात्मक न्यासी के रूप में प्राप्त लाभ को उसके पास नहीं रखा जा सकता है और उसे लाभार्थी के पास जाना चाहिए, लेकिन यह मजबूर नहीं कर सकता है। वह शेयरों के नए निर्गमों से जुड़े दायित्वों के लिए खुद को उत्तरदायी बनाएगा और आवश्यक भुगतान करके नए निर्गम के लिए आवेदन करेगा, जब तक कि लाभार्थी द्वारा विशेष रूप से ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए।

वासुदेव रामचंद्र शेलत बनाम। प्राणलाल जयानंद ठक्कर (ऊपर), सवाल इस तरह उठा, दाता ने कुछ उपहार दिए एक पंजीकृत विलेख द्वारा अपीलार्थी को कंपनियों में हिस्सेदारी। उन्होंने कई खाली हस्तांतरण

प्रपत्रों पर भी हस्ताक्षर किए ताकि प्राप्तकर्ता कंपनियों के रजिस्टर में शेयरों का हस्तांतरण प्राप्त कर सके। हालाँकि, कंपनियों के बही में अपीलार्थी को शेयर हस्तांतरित किए जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। दानदाता के भतीजे, प्रतिवादी ने इस आधार पर शेयरों का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया कि दान के हस्तांतरण के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करने में विफलता के लिए उपहार अधूरा था।

शेयर। यह देखते हुए कि 53 भारतीय अपीलों में, 92 में "रजिस्टर पर जाने के लिए शीर्षक" और "एक कंपनी में शेयरों में पूरी संपत्ति" के बीच अंतर किया गया था, अदालत ने यह विचार व्यक्त किया कि सेक। 6 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम ने भी इस प्रकार को उचित ठहराया

शेयरों पर "संपत्ति" का गठन करने वाले अधिकार का विभाजन ठीक उसी तरह जैसे यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त थी कि संपत्ति के स्वामित्व के अधिकारों को "कोष" के अधिकार में विभाजित किया जा सकता है और दूसरे को संपत्ति के "उपभोग" के अधिकार में विभाजित किया जा सकता है और फिर अलग से निपटा जा सकता है। उपहार के पंजीकृत विलेख की डिलीवरी के साथ-साथ

दाता को शेयर प्रमाण पत्र, दाता के नाम पर शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकार का दान पंजीकरण के साथ-साथ वितरण द्वारा भी अपरिवर्तनीय हो गया। या तो पर्याप्त था। कंपनियों के रजिस्टरों में वास्तविक हस्तांतरण इस अधिकार के अधिक प्रवर्तन का गठन करता है ताकि दाता शेयरधारक के अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हो सके। जितना अधिक तथ्य यह था कि इस तरह के हस्तांतरण को कंपनी कानून के अनुसार दर्ज किया जाना था, दान की गई चीज़ों की पूर्णता को कम नहीं करता था। 1913 के कंपनी अधिनियम की पहली अनुसूची के विनियमन 18 का उल्लेख करते हुए, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण के तरीके को निर्धारित किया गया था, अदालत ने कहा कि विनियमन में या कहीं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह संकेत दे कि बिना सख्त नियमों के।

कुछ कठोर रूप से निर्धारित प्रपत्र का अनुपालन, लेन-देन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल होना चाहिए। यह कहा गया था, "एक लेन-देन के पदार्थों का कुछ कठोर रूप से निर्धारित करने के लिए अधीनता का सावधानीपूर्वक पालन करने की आवश्यकता है, अरोहैक और पुराने न्यायशास्त्र का स्वाद"। अदालत ने कंपनी अधिनियम XXXI एडन पर बकले में परिच्छेद का उल्लेख किया। पृष्ठ 813:

" दानदाता द्वारा किए गए शेयरों के हस्तांतरण का गैर-पंजीकरण उपहार को अपूर्ण नहीं बनाता है, और पाल्मर के सामान्य कानून में मार्ग: 21 सेंट एडन। पृष्ठ 334: पंजीकृत होने तक स्थानांतरण अधूरा रहता है। पंजीकरण का इंतजार करते हुए, हस्तांतरणकर्ता के पास केवल एक

उसे हस्तांतरित शेयरों का न्यायसंगत अधिकार। जब तक इन शेयरों के संबंध में रजिस्टर में उसका नाम दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वह कानूनी मालिक नहीं बन जाता। कानून के दो बयानों को अदालत द्वारा सुलझा लिया गया था और यह कहा गया था कि "शेयरों के उपहार के तहत हस्तांतरणकर्ता, कंपनी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त शेयरधारक के रूप में तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसका नाम औपचारिक रूप से किसी कंपनी के रजिस्टर पर नहीं लाया जाता है और वह एक शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है जैसा कि पहले से ही ऊपर बताया गया है। वास्तव में, संघ के लेखों में उपहार या बिक्री द्वारा शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हो सकते हैं। यह इंगित किया गया था कि, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त शेयरों में "संपत्ति" अधिकारों का हस्तांतरण, सभी के वास्तविक निहित होने या सभी के पूर्ण अधिकारों के पूर्ववर्ती हो सकता है।

कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार शेयरों का स्वामित्व और शेयरधारकों के अधिकारों का प्रयोग, और यह कि सामान्य रूप से संपत्ति का हस्तांतरण कंपनी अधिनियम का विषय नहीं था, यह केवल इसलिए शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित है क्योंकि वे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त शेयरधारकों को कुछ अधिकार देते हैं और उन कंपनियों के संबंध में उन पर कुछ दायित्व लगाते हैं जिनमें वे शेयर रखते हैं। शेयर प्रमाणपत्र नहीं

केवल उस शेयरधारक को, जिसका नाम उस पर पाया जाता है, शेयर धारण पर ब्याज का अधिकार देता है, बल्कि संबंधित कंपनी से संबंधित कुछ कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार देता है।के फ्राय, (ऊपर), एफ में, संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी अपने बेटे को कुछ शेयरों का उपहार देना चाहता है।

एक अंग्रेजी कंपनी ने हस्तांतरण के एक विलेख को निष्पादित किया और इसे कंपनी को पंजीकरण के लिए भेजा। जैसा कि लेफ्टेंस लेफ्टेंस (वित्त) विनियम किसी भी प्रतिभूति या किसी भी प्रतिभूति के किसी भी हस्तांतरण को प्रतिबंधित करते हैं।

कोषागार से अनुमति के बिना एक अनिवासी द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों में ब्याज, कंपनी ने एफ को लिखा कि कुछ प्रपत्र उसके और हस्तांतरणकर्ता द्वारा पूरे किए जाने थे और कोषागार से एक लाइसेंस प्राप्त करना था। इससे पहले कि एफ आवेदन कर सके और कोषागार की अनुमति प्राप्त कर सके, उनकी मृत्यु हो गई। सवाल यह उठा कि क्या एफ का बेटा एफ की व्यक्तिगत आवश्यकता का हकदार था।

उसके लिए शेयरों की कानूनी और लाभकारी स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कोषागार की अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण, कंपनी हस्तांतरण को पंजीकृत नहीं कर सकी और इसलिए, बेटे ने विचाराधीन शेयरों के लिए कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं किया। न ही बेटे को शेयरों में समान ब्याज का पूरा उपहार था क्योंकि एफ के पास 995 नहीं था।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्फा रेली, जे.]

कोषागार की सहमति को कम किया और इसलिए, नहीं किया था

1 जो अपने न्यायसंगत अधिकार से खुद को अलग करने के लिए आवश्यक था

अपने बेटे के पक्ष में। इसलिए बेटा नहीं था।

मुकदमा करने के लिए शीर्षक। पिता के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों को प्राप्त करने के लिए

उसे शेयरों की कानूनी और लाभकारी स्थिति।

स्विस बैंक निगम बनाम। लॉयड्स बैंक लिमिटेड और अन्य।,

ऊपर), प्रश्न एस के तहत एक अधिकृत सकारात्मक के परिणाम के बारे में था। 16 (2) विनिमय नियंत्रण अधिनियम, विभाजन

विदेशी मुद्रा प्रतिभूति से संबंधित प्रमाण पत्र

बैंक ऑफ इंडिया के विपरीत कोषागार की अनुमति

ग्रंथि विनिमय नियंत्रण सूचना ई. सी. 7. अपील की अदालत में,ckley L. J. ने देखाः

..... बैंक ऑफ इंग्लैंड, हमें यह मान लेना चाहिए कि

पर्याप्त कारण, हस्तांतरण को मान्य करने से इनकार कर दिया

अभिरक्षा में। परिणामस्वरूप इसे धारा 16 (2) के उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए, जिसे, जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, स्वीकार किया गया है; लेकिन एक कार्य किया गया है।

एक क़ानून के उल्लंघन में आवश्यक नहीं है

शून्यता। ऐसा है या नहीं, यह क़ानून के नियमों और प्रभाव पर निर्भर करना चाहिए, और इस पर निर्भर हो सकता है -

कानून की नीति और अधिनियम की प्रकृति

स्वयं। अधिनियम की धारा 34 द्वारा प्रभाव दिया गया है

अधिनियम की अनुसूची 5 के प्रावधान

अधिनियम के प्रवर्तन के उद्देश्य। अनुच्छेद 1 (1)

उस अनुसूची के भाग II में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति

यूनाइटेड किंगडम में या निवासी जो अधिनियम द्वारा या उसके तहत लगाए गए किसी भी प्रतिबंध या आवश्यकता का उल्लंघन करता है, के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होगा

उस अनुसूची का हिस्सा। के बाद के प्रावधान अनुसूची का वह भाग ऐसे अपराध के लिए कारावास या खोज के रूप में अधिकतम दंड अधिरोपित करता है।

" मेरे निर्णय में, अधिनियम के तहत अपराध स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हैं, दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं; वे कृत्य नहीं हैं

कोई भी उद्देश्य। इस तरह वे किसी से वंचित नहीं हैं। प्रभाव; वे केवल दोषियों को अधिनियम द्वारा निर्धारित दंड के लिए उजागर करते हैं, जिनमें से कोई भी, अब तक नहीं

जैसा कि मुझे पता है, ठीक किया गया है या होने की कोशिश की गई हैइस मामले में कार्रवाई की गई।

. यदि विधायिका का इरादा था कि

प्रतिभूति, यदि किसी की अभिरक्षा से हस्तांतरित की जाती है

अन्य 996 की अभिरक्षा के लिए अधिकृत जमाकर्ता

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. एफ. 3 एस सी आर।

किसी भी प्रासंगिक अनुमति की सभी शर्तों के अनुपालन के बिना, बाद वाले जमाकर्ता की अभिरक्षा में होने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। मुझे लगता है, उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट प्रावधान खोजने की उम्मीद है, अन्यथा एक अनियमित के परिणामों के लिए

हिरासत के हस्तांतरण को संदेह में छोड़ दिया गया है।

इससे पहले हमने उल्लेख किया था कि कंपनी अधिनियम का S.111

निदेशक कंपनी और प्रत्येक शेयरधारक दोनों के प्रति एक प्रत्ययी स्थिति में होते हैं। इसलिए, निदेशकों को ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता होती है न कि मनमाने ढंग से और किसी भी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए "जहां लेखों ने निदेशकों को बिना सौंपे शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने की अनुमति दी थी। इन कारणों से, अदालत अनिवार्य रूप से निदेशकों के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालेगी, लेकिन यह मान लेगी कि उन्होंने उचित और प्रामाणिक रूप से काम किया है। जहां निदेशकों ने कारण दिए, अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या कारण वैध थे और क्या निदेशक सही या गलत सिद्धांत पर आगे बढ़े। यदि लेख निदेशकों को कारणों का खुलासा नहीं करने की अनुमति देते हैं, तो उनसे पूछताछ की जा सकती है और कारणों का खुलासा करने के लिए कहा जा सकता है। यदि वे उस कारण का खुलासा करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है।

कई वैधानिक प्रावधानों के समग्र दृष्टिकोण पर और

न्यायिक उदाहरण जिनका हमने उल्लेख किया है, हम पाते हैं कि एक शेयरधारक का किसी कंपनी में निस्संदेह हित होता है, एक ऐसा हित जो उसकी हिस्सेदारी द्वारा दर्शाया जाता है। शेयर चल है। ऐसी संपत्ति की सभी विशेषताओं के साथ। शेयरधारकों के अधिकार हैं (i) निदेशकों का चुनाव करना और इस प्रकार उनके माध्यम से प्रबंधन में भाग लेना; (ii) कंपनी की बैठकों में प्रस्तावों पर मतदान करना; (iii) कंपनी के लाभ का आनंद लेना।

लाभांश के रूप में कंपनी; (iv) एल. आई. सी. बनाम के लिए न्यायालय में आवेदन करना।

एस्कॉर्ट्स [चिनाफ्फा केली, जे।]

997

दमन के मामले में राहत; (v) कुप्रबंधन के मामले में राहत के लिए न्यायालय में आवेदन करना; (vi) कंपनी को बंद करने के लिए न्यायालय में आवेदन करना; (vii) बंद होने पर अधिशेष में हिस्सेदारी करना। एक शेयर हस्तांतरणीय होता है लेकिन जबकि हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता के बीच हस्तांतरण हस्तांतरण की तारीख से प्रभावी हो सकता है, हस्तांतरण वास्तव में पूर्ण होता है और हस्तांतरणकर्ता एक शेयरधारक के सभी अधिकारों के साथ, अवधि के सही और पूर्ण अर्थों में एक शेयरधारक बन जाता है, केवल तभी जब हस्तांतरण कंपनी के रजिस्टर में पंजीकृत होता है। हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरणकर्ता के बीच प्रभावी हस्तांतरण कंपनी और व्यक्तियों के खिलाफ हस्तांतरण की सूचना के बिना तब तक प्रभावी नहीं है जब तक कि हस्तांतरण कंपनी के रजिस्टर में पंजीकृत नहीं हो जाता है।

वास्तव में जब तक हस्तांतरण कंपनी की पुस्तकों में पंजीकृत नहीं हो जाता है, तब तक वह व्यक्ति जिसका नाम केवल रजिस्टर में पाया जाता है, वह लाभांश प्राप्त करने का हकदार है, भले ही वह पहले ही शेयरों में अपने हित के साथ भाग ले चुका हो। हालांकि, शेयरों के हस्तांतरण पर, हस्तांतरणकर्ता लाभकारी ब्याज का मालिक बन जाता है, हालांकि कानूनी स्वामित्व हस्तांतरणकर्ता के पास जारी रहता है। न्यासी और 'सेस्टूई क्यू ट्रस्ट' का संबंध स्थापित हो जाता है और हस्तांतरणकर्ता उन सभी उचित निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है जो हस्तांतरणकर्ता दे सकता है। वह लाभांश के साथ-साथ मतदान के अधिकार का भी न्यासी बन जाता है। हस्तांतरणकर्ता के 'रजिस्टर में शामिल होने' के अधिकार का उपयोग उचित परिश्रम के साथ किया जाना चाहिए और समानता का सिद्धांत जो हस्तांतरणकर्ता को एक रचनात्मक न्यासी बनाता है, उस मामले तक विस्तारित नहीं होता है जहां हस्तांतरणकर्ता रजिस्टर में शामिल होने के लिए कोई सक्रिय रुचि नहीं लेता है। जहां हस्तांतरण एक कानून द्वारा विनियमित किया जाता है, जैसा कि एक अनिवासी को हस्तांतरण के मामले में, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा विनियमित है, कानून द्वारा निर्धारित अनुमति, यदि कोई हो, प्राप्त की जानी चाहिए। अनुमति के अभाव में, हस्तांतरण हस्तांतरणकर्ता को अधिकार के साथ नहीं पहनेगा

' जब तक आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक रजिस्टर 1 पर जाएं। एक अंतरिती जिसे पाने का अधिकार है

रजिस्टर, जहाँ किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है या जहाँ अनुमति प्राप्त की गई है, कंपनी को हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए कह सकती है और जिस कंपनी को शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए कहा जाता है, वह हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकती है, सिवाय किसी प्रामाणिक कारण के, न तो मनमाने ढंग से और न ही किसी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए। सर्वोपरि विचार कंपनी का हित और शेयरधारक का सामान्य हित है। दूसरी ओर, उदाहरण के लिए, जहां एफ. ई. आर. ए. के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है, यह कंपनी के लिए खुला है और वास्तव में, यह एक अनिवासी के पक्ष में एक भारतीय कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार करने के लिए बाध्य है। लेकिन एक बार अनुमति प्राप्त करने के बाद, चाहे वह शेयरों की खरीद से पहले हो या बाद में, कंपनी इसके बाद शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से इनकार नहीं कर सकती है।

न ही यह कंपनी या किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्तिगत रूप से खुद को संभालने के लिए खुला है, इसके बाद, यह तय करने का कार्य कि क्या अनुमति सही तरीके से दी गई थी।

क्या विदेशी व्यवस्था के प्रावधानों की आवश्यकताएँविनिमय विनियमन अधिनियम और विभिन्न नियमों, निर्देशों और आदेशों को समय-समय पर पूरा किया गया है और क्या अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम के तहत जारी नियमों, आदेशों और निर्देशों का पालन न करने के परिणामों का उल्लेख अनुभागों में किया गया है। 48 , 50 , 56 और अधिनियम की धारा 63। अधिनियम का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अधिनियम के बाहर काम करने वाले किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि क्या रिजर्व बैंक धारा के तहत अनुमति देने में सही था या गलत। 29 (1) अधिनियम से। जैसा कि हमने पहले कहा, अधिनियम की योजना के तहत, यह भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे विदेशी मुद्रा को विनियमित करने और संरक्षित करने का कार्य सौंपा गया है। यदि कोई इस तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता है, तो यह विदेशी मुद्रा का 'संरक्षक-सामान्य' है। प्रवर्तन का कार्य प्रवर्तन निदेशालय पर छोड़ दिया गया है, लेकिन यह भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक को ही तय करना है कि अनुमति दी जाए या नहीं।

सेक के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। 29 (1) अधिनियम से। यह अधिनियम इसे अपना अनन्य विशेषाधिकार और कार्य बनाता है। कोई अन्य प्राधिकरण नहीं है

यह किसी भी शक्ति के साथ निहित है और न ही यह इस प्रश्न को तय करने की शक्ति ग्रहण कर सकता है कि क्या अनुमति दी जा सकती है या नहीं या क्या इसे दी जानी चाहिए थी या नहीं। सवाल को सीधे या सीधे उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

संपार्श्विक रूप से। हालाँकि, हम उन सीमित वर्ग के मामलों को खारिज नहीं करते हैं जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति के अनुदान पर एक इच्छुक पक्ष द्वारा अनुच्छेद के तहत कार्यवाही में सवाल उठाया जा

सकता है। 226 संविधान का, इस आधार पर कि यह दुर्भावनापूर्ण था या कि मन का कोई अनुप्रयोग नहीं था या यह था

अधिनियम द्वारा विचार किए गए राष्ट्रीय हित के विपरीत, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना और अधिनियम के तहत जारी किए गए नियम, आदेश और निर्देश। एक बार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद, आम तौर पर यह किसी के लिए भी अनुमति के पीछे जाने और उस पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है। यह निश्चित रूप से उस कंपनी के लिए खुला नहीं है जिसके शेयर एक अनिवासी कंपनी द्वारा खरीदे गए हैं, वह अनुमति प्राप्त करने के बाद भी शेयरों को पंजीकृत करने से इनकार कर सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक को इस आधार पर कि एफ. ई. आर. ए. के तहत अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। स्वयं को यह याद दिलाना आवश्यक है कि अनुभाग द्वारा अनुध्यात अनुमति। 29 (1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का न तो इरादा है और न ही एल. आई. सी. बनाम।

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा केली, जे।]

999

भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की दुर्भावनाओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मन को लागू न करने के बारे में हमारे सामने बहुत कुछ कहा गया था।यह कानूनी दुर्भावना के बराबर है। हालांकि कंपनी के विद्वान वकील श्री नरीमन ने समय-समय पर अपने तर्क के दौरान उल्लेख किया कि श्री स्वराज पॉल प्रेस बयान जारी कर रहे थे, जिनका आम तौर पर सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा कोई न कोई कार्रवाई करके पालन किया जाता था, लेकिन उन्होंने श्री स्वराज पॉल द्वारा दिए गए प्रेस बयानों को हमें पढ़ने से उचित रूप से परहेज किया। हालाँकि, श्री स्वराज पॉल के कुछ प्रेस बयानों और रिलीज़ का सार उन दलीलों में शामिल किया गया है जिन्हें हमें पढ़ा गया था। ऐसा हो सकता है कि श्री स्वराज पॉल अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए हमेशा तैयार और उत्सुक थे, या तो उन्हें इस बात का आभास था या उन्होंने अनुमान लगाया था कि सरकार या रिजर्व बैंक किस तरह की कार्रवाई करने की संभावना है या क्योंकि वे, हर इच्छुक पक्ष की तरह, ऐसे बयान देने में रुचि रखते थे जो कहीं न कहीं किसी के कान लग सकते हैं। इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि श्री स्वराज पॉल की किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच थी जो इस मामले में निर्णय लेने या किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की स्थिति में था।

मामले में निर्णय। हमें नहीं लगता कि हम श्री स्वराज पॉल द्वारा दिए गए भद्दे और भव्य प्रेस बयानों और विज्ञप्ति को कोई महत्व दे सकते हैं। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के अति-मूल्यांकन वाले बयानों के रूप में नजरअंदाज किया जाना चाहिए, जिसने खुद को बहुत उच्च दर्जा दिया। सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति जिस पर निर्भरता थी

कंपनी की ओर से दुर्भावना से संबंधित तर्क के समर्थन में रखा गया, इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के रवैये की बारी थी। यह कहा गया था कि शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक को इस सवाल पर गंभीर आपत्ति

थी कि क्या भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों द्वारा शेयरों की अप्रत्यक्ष खरीद मूल योजना के तहत अनुमत थी। बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्त सचिव, वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की।

प्रधानमंत्री के निजी सचिव भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना रवैया बदल दिया और विवादित परिपत्र और अनुमति जारी कर दी। हमारा ध्यान विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था: (i) भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भारत सरकार को 1 जून, 1983 को लिखा गया पत्र जिसमें रिजर्व बैंक का यह विचार प्रतीत होता है कि इस योजना में अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1985] का उल्लेख नहीं किया गया है।

3 एस सी आर।

1000 भारतीय मूल के अनिवासी व्यक्तियों द्वारा निवेश और सभी 13 समुद्री कंपनियों के आवेदन को अस्वीकार करने का प्रस्ताव, लेकिन भारत सरकार से पुष्टि की मांग की, (ii) भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार का 17 सितंबर, 1983 का जवाब और (iii) गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांकित 17.9.83 पत्र पर किया गया समर्थन। हम पहले ही कार्यवाही पैराग्राफ में दो अक्षरों (1) और (11) की सामग्री का उल्लेख कर चुके हैं। हमने डॉ. मान मोहन सिंह का पूरा समर्थन भी प्राप्त कर लिया है। (i), (ii) और (iii) से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने (1) में खुद को दृढ़ता से व्यक्त किया था, लेकिन यह वित्त सचिव, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के निजी सचिव के दबाव में था कि

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अंततः सरकार द्वारा अपने दिनांकित 17.9.83 पत्र में सुझाए गए मार्ग को अपनाने के लिए सहमत हो गए और यह कि भारतीय रिजर्व बैंक का निर्णय एक मुक्त एजेंट का नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र और उसके द्वारा दी गई अनुमति, यह सुझाव दिया गया था, भारत सरकार के दबाव में जारी और प्रदान की गई थी। हम नहीं सोचते कि हम इस तरह के किसी भी चित्र को बनाने में उचित होंगे।

अनुमान। यह डॉ. मान मोहन सिंह के लिए पूरी तरह से अनुचित और अनुचित होगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की एक बड़ी मात्रा शामिल थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरुआत में एक निश्चित

मामले में स्थिति, इसने परामर्श करना आवश्यक समझा और

इस मामले में भारत सरकार की सलाह लें। स्पष्ट रूप से उच्च स्तरीय चर्चाएँ हुईं क्योंकि

विदेशी मुद्रा और इसमें शामिल नीति का प्रश्न और इस मामले ने जनता के रूप में प्रेस का भी काफी ध्यान आकर्षित किया था। यदि उच्च स्तरीय चर्चाओं के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विचार बदल दिए, तो यह अनुचित और अनुचित होगा।

यह मानने की अनुमति नहीं है कि यह दबाव के दबाव में किया गया था। . इस प्रकृति के प्रत्येक प्रश्न के अलग-अलग पहलू होने चाहिए जो

अलग-अलग कोणों से देखने पर वे अलग-अलग रोशनी में खुद को प्रस्तुत करते हैं। यदि सरकार के उच्च स्तर के उन लोगों के साथ पूर्ण चर्चा के बाद जो नीति-निर्माण से संबंधित हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलकर

अर्थव्यवस्था के हितों में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण

देश, यह देखने में विफल रहता है कि इसके निर्णय को कैसे कहा जा सकता है

किसी भी दबाव का परिणाम।

यह तर्क दिया गया था कि समय-समय पर कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक को कई पत्र भेजे थे

बाद वाले का ध्यान कई अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना और

अवैध कार्य, जिनका उसने दावा किया था, श्री स्वराज एल. आई. सी. बनाम द्वारा किए गए थे।

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

1001

पॉल और कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि रिजर्व बैंक जवाब देने और मामले में कोई जांच करने में विफल रहा। यह कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक दिमाग के पूर्ण गैर-अनुप्रयोग का दोषी था और इसलिए, कानूनी रूप से इसे दोषी ठहराया जा सकता है। हम इस निवेदन से सहमत नहीं हो सकते। केवल इसलिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी से प्राप्त संचार का जवाब भेजने का विकल्प नहीं चुना, इसका मतलब यह नहीं था कि भारतीय रिजर्व बैंक ईमानदारी से काम नहीं कर रहा था। हालांकि हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ने कंपनी से प्राप्त संचार को स्वीकार करने और उन्हें जवाब देने के लिए अच्छा काम किया होगा, हम ऐसा करने में उनकी विफलता से दुर्भावनापूर्ण अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। ऐसा नहीं था कि रिजर्व बैंक ने कंपनी की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने तरीके से मामले की जांच की। जैसा कि हमने घटनाओं के वर्णन के दौरान पहले ही उल्लेख किया है, रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक से जानकारी मांगकर अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियुक्त एक अधिकृत डीलर था और जिससे रिजर्व बैंक को पूरी और सटीक आपूर्ति करने की उम्मीद की जा सकती थी।

जानकारी दी। उस समय पंजाब नेशनल बैंक की ईमानदारी और अयोग्यता पर संदेह करने की कोई बात नहीं थी। कंपनी ने रिजर्व बैंक को भेजे कई पत्रों में भी पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। उन परिस्थितियों में, यदि रिजर्व बैंक पंजाब नेशनल बैंक से जानकारी लेना उचित समझता है और पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त जानकारी पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ता है, तो रिजर्व बैंक पर दिमाग

का उपयोग न करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। रिजर्व बैंक पंजाब नेशनल बैंक और उस बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा करने का हकदार था क्योंकि बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत एक वैधानिक स्थिति में था। यह हो सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक ने उस स्तर की क्षमता और परिश्रम के साथ काम नहीं किया जैसा कि उससे उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन उस स्तर पर, रिजर्व बैंक के मन में कोई संदेह पैदा करने के लिए कुछ भी नहीं था। हम वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निभाई गई भूमिका की ओर लौटेंगे, लेकिन रिजर्व बैंक को केवल पंजाब नेशनल बैंक और उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा रखने के कारण ईमानदारी और गैर-व्यवहार के अभाव में बदलने का कोई कारण नहीं है, हालांकि सुनवाई के दौरान अब सामने लाई गई कुछ सामग्री की सहायता से, हम समझते हैं कि रिजर्व बैंक कार्रवाई कर सकता था

पंजाब नेशनल बैंक पर भरोसा करने की तुलना में अधिक ज्ञान। लेकिन यह वास्तव में 'हिंद-दृष्टि' के साथ बात करना होगा।

इससे पहले हमने पंजाब नेशनल की विफलता का उल्लेख किया था।

बैंक अपने [1985] एस. यू. पी. पी. द्वारा श्री स्वराज पॉल से प्राप्त एल. 1,30,000 के प्रेषण के बारे में रिजर्व बैंक को सूचित करेगा, जैसा कि वह करने के लिए बाध्य था।

संसद मार्ग शाखा। पंजाब नेशनल लैंक से यह सुनकर खेद हुआ कि उनकी ईसीई हाउस शाखा, जो एनआरई खातों और कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा शेयरों की खरीद की निगरानी कर रही थी, को पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा द्वारा प्राप्त प्रेषण के बारे में जानकारी नहीं थी। अब हमें बताया गया है कि एल 1,30,000 की इस राशि का उपयोग कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए शेयर खरीदने के लिए भी किया गया था। यदि ऐसा था, तो ईसीई हाउस शाखा को इसके बारे में पता होना चाहिए था। अन्यथा, कोई आश्चर्य करता है कि ईसीई हाउस शाखा द्वारा की गई निगरानी क्या थी, अगर उसे यह भी पता नहीं था कि उनकी संसद भवन शाखा द्वारा प्राप्त एल 1,30,000 के एक बड़े प्रेषण का उपयोग कपारो समूह की कंपनियों के लिए शेयरों की खरीद के लिए किया गया था। यदि राशि का उपयोग कपारो समूह की कंपनियों के लिए शेयरों की खरीद के लिए नहीं किया गया था, तो यह अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करना चाहिए कि कुछ शेयरों की खरीद के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध धन का उपयोग किया गया होगा, न कि विदेशी प्रेषण का। यह तथ्य कि यह बड़ी राशि श्री स्वराज पॉल द्वारा भेजी गई थी और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में कभी नहीं लाया गया, जिसे स्पष्ट रूप से इसके बारे में अंधेरे में रखा गया था। हम.

इसे एक गंभीर मामला मानते हुए आगे की जांच की आवश्यकता है।

रिजर्व बैंक। हम पाते हैं कि इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक का पूरा आचरण सबसे अधिक गैर-जिम्मेदाराना रहा है। उन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत अधिकृत विक्रेताओं के रूप में नियुक्त किया गया था और इस तरह की नियुक्ति के आधार पर प्रवाह को विनियमित करने और विदेशी मुद्रा के संरक्षण और राष्ट्रीय हित की रक्षा के उद्देश्य से उन पर बहुत विश्वास किया गया था। पोर्टफोलियो निवेश योजना में प्रावधान किया गया था कि जिन बैंकों को अधिकृत विक्रेताओं के रूप में नामित किया गया था, वे भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अपने अनिवासी ग्राहकों की ओर से स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर खरीद सकते थे। भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने की अनुमति के लिए विदेशी निवेशकों के आवेदन वास्तव में नामित बैंकों के माध्यम से किए जाने थे। 14 अप्रैल, 1982 के परिपत्र संख्या 9 के पैराग्राफ 11 द्वारा नामित बैंकों को निवेशक के लिए प्रत्यावर्तन लाभों के साथ और बिना शेयरों में किए गए निवेश का एक उचित रिकॉर्ड अलग से बनाए रखने की आवश्यकता थी, जिसमें शेयर प्रमाणपत्रों की संख्या और शेयरों की विशिष्ट संख्या सहित सभी प्रासंगिक विवरण शामिल थे। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रत्येक निवेशक के लिए उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों का एक व्यवस्थित और अद्यतित रिकॉर्ड रखना आवश्यक था ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि किसी एक निवेशक द्वारा किसी एक कंपनी में शेयरों की खरीद रुपये से अधिक न हो। कंपनी के अंकित मूल्य में एक लाख। 22 अप्रैल, 1982 के परिपत्र संख्या 10 द्वारा फिर से, अधिकृत विक्रेता (नामित बैंक) को निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों से एक

लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट/प्रमाणित सार्वजनिक 1003 से प्रमाण पत्र

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

सीएसी के रूप में लेखाकार। यह प्रमाण पत्र हर साल अधिकृत विक्रेता द्वारा प्राप्त किया जाना था। जब 16 मई, 1983 के परिपत्र संख्या 12 द्वारा कंपनी की कुल चुकता इक्विटी पूंजी के 5 प्रतिशत की कुल सीमा लागू की गई थी, तो 5 प्रतिशत की सीमा की निगरानी के उद्देश्य से यह निर्धारित किया गया था कि जिन अधिकृत विक्रेताओं को पात्र गैर-निवासी निवेशकों की ओर से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत शेयर खरीदने की अनुमति दी गई थी, उन्हें दैनिक आधार पर अपनी नामित शाखाओं द्वारा किए गए इक्विटी शेयरों की खरीद और बिक्री के समन्वय के उद्देश्य से बॉम्बे में एक लिंक कार्यालय नामित करना चाहिए और इसे नियंत्रक, नियंत्रण विनिमय विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना चाहिए। लिंक अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में नामित शाखाओं द्वारा की गई इक्विटी शेयरों की कुल खरीद और बिक्री का एक समेकित विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था। दैनिक बयानों को अगले दिन नियंत्रक को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना था। हम सीधे कह सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक, प्रेषण प्राप्त करने के अलावा। कापारो ग्रुप लिमिटेड से और स्टॉक ब्रोकरों को राशि हस्तांतरित करते हुए, राजा काम भसीन एंड कंपनी ने अधिकृत डीलरों के रूप में अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कुछ भी

नहीं किया। अब यह स्वीकार किया जाता है कि उन्होंने राजाराम भसीन एंड कंपनी को शेयरों की खरीद के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया, कि उन्होंने कभी भी शेयरों में किए गए निवेश का कोई व्यवस्थित, अद्यतन और उचित रिकॉर्ड नहीं रखा और उन्होंने नियंत्रक को शेयरों की खरीद और बिक्री के दैनिक विवरण जमा नहीं किए। बेशक, शुरुआत में, उन्होंने भारतीय कंपनियों में शेयर खरीदने की अनुमति के लिए रिजर्व बैंक को कपारो समूह की कंपनियों के आवेदन प्रस्तुत किए। वह 4 और 12 मार्च, 1983 को था। इसके बाद, उन्होंने 23 अप्रैल, 1983 को रिजर्व बैंक को अनुमति के लिए अपने ग्राहकों के आवेदनों के बारे में याद दिलाते हुए लिखा और उन्हें 9.3.1983,12.4.1983,13.4.1983 और 23.3.1983 पर चार प्रेषणों की प्राप्ति के बारे में सूचित किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राजा राम भसीन एंड कंपनी के माध्यम से निवेश संचालन किए जा रहे थे। किन शेयरों, कितने और किस राशि के लिए, इन विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया था, यहां तक कि खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या और तब तक खर्च की गई राशि का भी उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए, रिजर्व से एक पत्र के जवाब में

बैंक, उन्होंने 6 मई, 1983 को लिखा कि उन्हें सलाह दी गई थी कि श्री स्वराज पॉल और परिवार के सदस्यों के पास कपारो ग्रुप लिमिटेड की 61.6 प्रतिशत शेयर पूंजी है और कपारो ग्रुप के पास कपारो प्रॉपर्टीज को छोड़कर शेष कंपनियों की 100 प्रतिशत शेयर पूंजी है, जिसमें हिस्सेदारी 98 प्रतिशत थी। इस पत्र में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "उक्त अनिवासी ग्राहकों द्वारा या उनकी ओर से खरीदे गए भारतीय कंपनियों के शेयरों के विवरण के संबंध में, उन्होंने हमें सलाह दी है कि उनकी आपूर्ति की जाएगी।

जब खरीदारी पूरी हो गई थी। यह कथन हमें दिखाई देता है।

:

1004

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. 3 एस सी आर।

पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत अधिकृत विक्रेता के कर्तव्यों का पूरी तरह से उल्लंघन करना। पत्र से पता चलता है कि न केवल अधिकृत डीलरों द्वारा बिक्री नहीं की गई थी, बल्कि अधिकृत डीलरों को तब तक हुए लेन-देन के बारे में भी पता नहीं था, हालांकि अब हमें बताया गया है कि सभी शेयर 28 अप्रैल, 1983 तक खरीद लिए गए थे। केवल आईडी2 पर ही पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को एक तार भेजा कि उन्हें दलालों द्वारा सलाह दी गई थी कि आईडी1 तक, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 75,000 इक्विटी शेयर तेरह विदेशी कंपनियों में से प्रत्येक की ओर से और उनके लाभ के लिए खरीदे गए थे। रिजर्व बैंक ने अपने पत्र द्वारा विदेशी कंपनियों के लाभ के लिए की गई शेयरों की खरीद की जानकारी मांगी, (i) दिसंबर, 1982 तक; (ii) 1.1.83 से 28.2.83 तक; (iii) 1.3.83 से 2.5.83 तक; और (iv) 2.5.83 के बाद। शेयरों की कुल संख्या और अंकित मूल्य सहित खरीद के विवरण दिए जाने की आवश्यकता थी। पंजाब नेशनल बैंक ने 23.6.83 पर इस आशय का जवाब दिया कि उनके दलालों ने उन्हें

अपने पत्र दिनांक 22.6.83 द्वारा सूचित किया था कि 1.3.83 से लेकर अब तक की अवधि के दौरान तेरह कंपनियों में से प्रत्येक के लिए एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 75,000 शेयर खरीदे गए थे।

2.5.83 , लेकिन किसी को भी पहले या बाद में नहीं खरीदा गया था। यह भी कहा गया कि दलालों ने पुष्टि की थी कि इन शेयरों के अलावा कोई अन्य खरीद नहीं की गई थी। यह पत्र फिर से बताता है कि वे अधिकृत विक्रेताओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कितने लापरवाह थे। न केवल उन्होंने प्रत्येक कंपनी की ओर से की गई खरीद का अद्यतन और उचित रिकॉर्ड नहीं रखा, न केवल उन्होंने नियंत्रक को दैनिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया, उन्हें हुए लेनदेन के बारे में भी जानकारी नहीं थी, बल्कि वे पूरी तरह से काजाराम भसीन एंड कंपनी द्वारा उन्हें एक बार प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर थे। हालांकि रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक से कुछ पूछताछ की, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं उठाया जितना उन्होंने किया होगा, लेकिन जाहिर तौर पर, पंजाब नेशनल बैंक पर भरोसा करना पसंद किया क्योंकि वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत अधिकृत विक्रेता थे और उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वे सब कुछ ठीक से और अधिनियम और योजना द्वारा अधिकृत और विचार किए गए तरीके से कर रहे थे। यह याद रखना होगा कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने भी पंजाब नेशनल बैंक के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी। अब यह पता चला है कि पंजाब नेशनल बैंक ने केवल एक बेवकूफ, नकली से बेहतर काम नहीं किया और अधिनियम और योजना के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करने में विफल रहा।

1005

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

कर्तव्य की अवहेलना का परिणाम

पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि इसकी उचित निगरानी नहीं की गई थी। तेरह कपारो समूह द्वारा शेयरों की खरीद

कंपनियाँ। जबकि हम यह मानने में असमर्थ हैं कि रिजर्व बैंक

भारत ने ईमानदारी से काम नहीं किया और न ही प्रासंगिक मुद्दों पर अपना दिमाग लगाया। जिन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता थी

अनुमति देने से पहले, क्योंकि, यह प्रामाणिक रूप से लागू होता था

उसके दिमाग में जो भी सामग्री तब उसके लिए उपलब्ध थी और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इसे आपूर्ति की गई, हमें इसे रखना चाहिए

जिस पर

अब हमारे पास ऐसी सामग्री उपलब्ध है कि पंजाब नेशनल बैंक पर उनकी अंतर्निहित निर्भरता पूरी तरह से गलत थी। उस निष्कर्ष पर आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, यह एक सवाल है जो हमें करना है।

विचार करें। हम दूसरे पर विचार करने के बाद ऐसा करेंगे।

हमारे सामने प्रश्न बहस करते थे।

श्री नरीमन ने तर्क दिया कि कई परिक्षेत्र थे

अभिलेख में स्थिति जिसने स्थापित किया कि बड़ी संख्या में

उपलब्ध कराई गई निधियों से शेयर खरीदे गए थे।

स्थानीय रूप से और विदेश से प्रेषित धन नहीं और यह भी कि शेयर 2.5.83 के बाद खरीदे गए थे। परिस्थितियाँ

ये थे: (1) प्रेषण शुरू होने से पहले शेयरों की खरीद शुरू हो गई; (ii) जिस कीमत पर शेयर बाजार में उपलब्ध थे, उससे पता चलता है कि जो राशि प्रेषित की गई थी, उससे अधिक राशि होनी चाहिए। शेयरों की खरीद के लिए उपयोग किया गया है और यह केवल रुपये के कोष के साथ हो सकता था; (iii) कंपनी विक्रेताओं के दो दलालों से दो दलालों के नोट प्राप्त करने में सक्षम थी, जिससे पता चलता है कि बिक्री 2.5.83 के काफी बाद की गई थी और (iv) तेरह कंपनियों की ओर से खरीदे गए कुल शेयरों में से, 4,62,000 शेयर केवल हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए 14.5.83 पर कंपनी के पास दर्ज किए गए थे। 3,68,463 शेयर थे

19.8.83 पर दर्ज किया गया, अर्थात 2.5.83 के 3-1/2 महीने बाद, जो कि 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा लागू करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि थी। 1,44,200 कंपनी के पास शेयर बिल्कुल भी जमा नहीं किए गए थे। एक उचित अवधि के भीतर शेयरों को दर्ज करने में विफलता

28.4.83 जिसे वह तारीख माना जाता था जिसके द्वारा सभी पुर का पीछा किया गया था, यह इंगित करता था कि खरीदारी बहुत बाद में की गई होगी। इन परिस्थितियों में से हर कोई कुछ स्पष्टीकरण देने में सक्षम है, पर्याप्त या नहीं, हमारे पास अब हमारे सामने रिकॉर्ड पर कहने के लिए आवश्यक सामग्री नहीं है। इस प्रश्न में व्यक्तिगत खरीद की जांच और साक्षय को जोड़ना शामिल होगा। यह उच्च न्यायालय में रिट याचिका के दायरे से बाहर होगा। यह याद रखा जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने प्रार्थना (घ) के संबंध में एक नियम निसी जारी करने से इनकार कर दिया, जाहिर है क्योंकि यह सोचा गया था कि न्यायालय के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 226 को साक्षय 1006 का अन्वेषण नहीं करना चाहिए।

शेयरों की खरीद के विभिन्न लेन-देन की तिथियों का निर्धारण करना और क्या उन्हें विदेशी मुद्रा या स्थानीय रूप से उपलब्ध निधियों से खरीदा गया था। हम मानते हैं कि यह वास्तव में अंतिम निगरानी

प्राधिकरण, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक के विचार का विषय है। हम बाद में बताएँगे कि हम मामले के इस पहलू के बारे में क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं।

यह प्रस्तुत किया गया था कि तेरह कपारो कंपनियाँ केवल नाम की तेरह कंपनियाँ थीं; वे केवल एक थीं और वे एक व्यक्ति थे, श्री स्वराज पॉल। श्री स्वराज पॉल को पीछे छिपे हुए देखने के लिए केवल कॉर्पोरेट घूंघट को छेदना पड़ता था। यह प्रस्तुत किया गया था कि तेरह कंपनियों की ओर से उस योजना को दरकिनार करने के लिए तेरह आवेदन किए गए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता या प्रत्येक कंपनी के मूल के प्रत्येक गैर-निवासी की ओर से एक प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके 60 प्रतिशत शेयरों का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के गैर-निवासियों के पास था। हमारा ध्यान वालरस्टीनर बनाम में लॉर्ड डेनिंग एम. आर. की सुरम्य घोषणा की ओर आकर्षित किया गया था। मोइर 1974 3 सभी ई. आर. 217, और टाटा इंजीनियर में इस अदालत के फैसले

आई. एन. जी. एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 1964 6 एस. सी. आर. 885, आयकर आयुक्त बनाम। मीनाक्षी मिल्स ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 819 और वर्कमेन बनाम। एसोसिएटेड रबर लिमिटेड 1985 2 स्केल 321। जबकि यह सालोमोन बनाम के बाद से दृढ़ता से स्थापित है। ए.

सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 ए. सी. 22 में यह निर्णय लिया गया कि एक कंपनी का एक स्वतंत्र और कानूनी व्यक्तित्व होता है जो कंपनी से अलग होता है।

कॉर्पोरेट पर्दा उठाया जा सकता है, कॉर्पोरेट व्यक्तित्व हो सकता है नजरअंदाज किया जाता है और अलग-अलग सदस्यों को पहचाना जाता है कि वे किसमें हैं

कुछ असाधारण परिस्थितियाँ। पेनिंगटन अपने कंपनी कानून में

(चौथा संस्करण) कहता है:

" कंपनियों के अलग कानूनी व्यक्तित्व के सिद्धांत पर कानून द्वारा चार रास्ते बनाए गए हैं। इनमें से अब तक सबसे व्यापक कर लगाने वाले कानून द्वारा बनाया गया है। स्वाभाविक रूप से सरकार को योजनाओं का नुकसान स्वेच्छा से नहीं उठाना पड़ता है

कराधान से बचने के लिए जो उनकी सफलता के लिए अलग कानूनी व्यक्तित्व के सिद्धांत के उपयोग पर निर्भर करता है, और वास्तव में कानून इस हद तक चला गया है कि कुछ परिस्थितियों में कर लगाया जा सकता है

यदि करदाता अपनी कर देनदारी को कम करने के प्रयास में कंपनियों को नियुक्त करता है तो यह उसकी तुलना में अधिक भारी होगा यदि वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करता है। कंपनियों का कराधान एक जटिल विषय है और यह इस पुस्तक के दायरे से बाहर है। वह पाठक जो 1007 की कामना करता है

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे.]।

इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए निगम कर, आयकर, पूंजीगत लाभ कर और पूंजीगत हस्तांतरण कर पर कई मानक पाठ्य पुस्तकों को संदर्भित किया जाता है।

" अलग निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत पर अन्य प्रयास कंपनी अधिनियम, 1948 की दो धाराओं द्वारा किए गए हैं, जिसमें उस सिद्धांत की न्यायिक अवहेलना की गई है जिसमें सार्वजनिक हितों का संरक्षण किया जाता है।

जहाँ कंपनी का गठन कानून और अदालतों द्वारा लगाए गए दायित्वों से बचने के लिए किया गया है। कुछ मामलों में यह दर्शाता है कि एक कंपनी अपने सदस्यों के लिए एक एजेंट या ट्रस्टी है।

पाल्मर्स कंपनी लॉ (तेइसवां संस्करण) में, वर्तमान

इंग्लैंड में स्थिति बताई गई है और वे अवसर जब

निगमित पर्दा उठाया जा सकता है गणना की गई है और वर्गीकृत किया गया है

. चौदह श्रेणियों में। इसी तरह गोवर के कंपनी कानून में

(चौथा संस्करण), एक अध्याय 'पर्दा उठाने' के लिए समर्पित है और

विभिन्न अवसरों पर चर्चा की जाती है जब ऐसा किया जा सकता है। में।

टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स Co.Ltd। (ऊपर), कंपनी चाहते थे कि कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया जाए ताकि इसे बनाए रखा जा सके

कंपनी द्वारा दायर याचिका की रखरखाव क्षमतासंविधान का Art.32, इसे संविधान द्वारा दायर एक के रूप में मानते हुए

कंपनी के शेयरधारक। कंपनी का अनुरोध थाइस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इलाज करना संभव नहीं था

Art.19 के उद्देश्यों के लिए एक नागरिक के रूप में कंपनी। आयुक्त में

आय कर v. मीनाक्षी मिल्स (ऊपर), कॉर्पोरेट घूंघट था

के संबंध में भुगतान करके आयकर को हटाया और रोका गया

कानूनी पहलू के पीछे की आर्थिक वास्तविकताएँ। वर्कमेन वी।

एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री (सुप्रा), रिसॉर्ट को जाना पड़ा

कल्याण से बचने के लिए उपकरणों को रोकने के लिए घूंघट उठाने का सिद्धांतकानून। इस बात पर जोर दिया गया कि ध्यान दिया जाना चाहिए

पदार्थ और लेन-देन का रूप नहीं। आम तौर पर और मोटे तौर पर, हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट घूंघट हो सकता है

उठा लिया गया जहाँ एक क़ानून स्वयं घूंघट उठाने पर विचार करता है, या

धोखाधड़ी या अनुचित आचरण को रोकने का इरादा है, या

कर कानून या एक लाभकारी कानून से बचने की कोशिश की जाती है या

जहाँ संबद्ध कंपनियाँ अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं,

वास्तव में, एक चिंता का हिस्सा है। यह न तो आवश्यक है और न ही

प्रासंगिक वैधानिक या अन्य प्रावधान, जिसका उद्देश्य होना चाहिए प्राप्त, आक्षेपित आचरण, तत्व की भागीदारी

लोक हित, प्रभावित होने वाले पक्षों पर प्रभाव

आदि।

1008

[1985] एसयूपीपी। 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान मामले में, हमें नहीं लगता कि 'घूंघट उठाना' है

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और पोर्टफोलियो निवेश योजना की आवश्यक आवश्यकता से परे आवश्यक या अनुमेय। हमने देखा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य विदेशी मुद्रा के प्रवाह का संरक्षण और विनियमन करना है और इस योजना का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के अनिवासी निवेशकों को भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। व्यक्तियों के मामले में, उनकी पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है

राष्ट्रीयता या मूल। कंपनियों और अन्य कानूनी व्यक्तियों के मामले में, राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता का कोई सवाल नहीं हो सकता है।

इस तरह

ऐसी कंपनी या कानूनी व्यक्तित्व की जातीयता। किसकी?

तब गैर-निवासी कंपनियों या कानूनी हस्तियों को भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका उत्तर उस योजना द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है जिसमें यह पता लगाने के लिए 'निगमित पर्दा उठाने' का प्रावधान है कि क्या कम से कम 60 प्रतिशत शेयर भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के गैर-निवासियों के पास हैं। शेयरधारकों की राष्ट्रीयता या मूल का पता लगाने के लिए पर्दा उठाना आवश्यक है न कि व्यक्ति का पता लगाने के लिए।

प्रत्येक शेयरधारक की पहचान। कॉर्पोरेट पर्दा को केवल उस हद तक उठाया जा सकता है और उससे अधिक नहीं।

योजना के विवरण पहले ही निकाले जा चुके हैं

हमें। सबसे पहले, भारतीय कंपनी की इक्विटी पूंजी के एक प्रतिशत की सीमा किसी भी एकल विदेशी निवेशक द्वारा उसके शेयरों की खरीद पर लगाई गई थी। सीमा लागू करने का स्पष्ट उद्देश्य विदेशी निवेशकों द्वारा शेयरों के बड़े ब्लॉक खरीदने और भारतीय कंपनी पर कब्जा करने का प्रयास करके भारतीय कंपनी को अस्थिर करने से रोकना था। हम पहले ही एक प्रतिशत लगाने की निरर्थकता को समझा चुके हैं।

चूंकि यह सीमा प्रभावी रूप से भारतीय मूल के विदेशी निवेशकों के एक समूह को शेयरों में निवेश करने से नहीं रोकेगी

भारतीय कंपनी उनमें से प्रत्येक द्वारा एक प्रतिशत शेयर खरीदती है। हमने यह भी बताया कि विभिन्न विदेशी कंपनियों, जिनमें रहने वाले भारतीयों के कई अलग-अलग समूह हैं और एक व्यक्ति सभी के लिए समान है, के पास 60 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, में निवेश की सुविधा से इनकार नहीं किया जा सकता है।

केवल विदेशी कंपनियों के कारण भारतीय कंपनियों के शेयर

एकल आम गैर-निवासी व्यक्ति का वर्चस्व था। यह विदेशी कंपनियों के अन्य अनिवासी भारतीय शेयरधारकों के लिए अनुचित होगा, जो अन्यथा उन विदेशी कंपनियों के माध्यम से भारतीय कंपनियों में निवेश के लाभ के हकदार होंगे, जिनमें उनके शेयर थे। जाहिर है कि

द.

एक प्रतिशत की सीमा की निरर्थकता का एहसास जिसके कारणपाँच प्रतिशत की कुल सीमा लागू करना। पाँच प्रति

प्रतिशत कुल सीमा प्रभावी रूप से किसी भी एकल विदेशी एल. आई. सी. को रोकेगी।

एस्कॉर्ट्स [चिनाफ्फा रेली, जे।]

निवेशक या विदेशी निवेशकों का एक संयोजन भारतीय कंपनियों के बड़े खंडों को खरीदकर उन्हें अस्थिर करने का प्रयास करना।शेयर। अगर इसे ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि

वर्तमान मामले में निगमित पर्दा उठाना आवश्यक और अनुमत है, केवल भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने की इच्छा रखने वाली विदेशी कंपनियों के शेयरधारकों की राष्ट्रीयता या मूल का पता लगाने के लिए और शेयरधारकों की व्यक्तिगत पहचान का पता लगाने के लिए नहीं। हम यह नहीं सोचते कि केवल इसलिए कि अनुमति के लिए आवेदन करने वाली कई विदेशी कंपनियों के 60 प्रतिशत से अधिक शेयर एक ट्रस्ट के पास हैं, जिसके श्री स्वराज पॉल और उनके परिवार के सदस्य लाभार्थी हैं, कंपनियों को भारतीय कंपनियों में निवेश करने की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। वास्तव में, यदि न्यास के छह लाभार्थियों में से प्रत्येक ने भारतीय कंपनियों के शेयर खरीदने की अनुमति के लिए अलग-अलग आवेदन किया होता, तो उन्हें इस तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता था

अनुमति ली। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल उसी पर पोर्टफोलियो निवेश योजना का कोई उल्लंघन हुआ है।खाता या कि दी गई अनुमति अवैध है।

अब हम भारतीय जीवन बीमा निगम के खिलाफ एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के मामले की ओर रुख करते हैं। के अनुक्रम का वर्णन करते हुए

घटनाएँ, हमने मूल रूप से दायर की गई रिट याचिका के कुछ महीनों बाद भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का उल्लेख किया। भारतीय जीवन बीमा निगम पर जो प्राथमिक आरोप लगाया गया था, वह यह था कि भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और जीवन बीमा निगम के बीच कपारो समूह की कंपनियों के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए एस्कॉर्ट्स लिमिटेड पर दबाव बनाने के लिए टकराव हुआ था। मिलीभगत और साजिश का निष्कर्ष कुछ घटनाओं के अनुक्रम से निकाला गया था जिसका हम तुरंत उल्लेख करेंगे। रिट याचिका दायर करने से कुछ दिन पहले वित्त मंत्री के एक भाषण की रिपोर्ट थी, जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि उनके पास अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी हथियार है। रिट याचिका दायर किए जाने के बाद और इसे स्वीकार किए जाने से पहले, 6 जनवरी, 1984 को एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक हुई, जिसमें श्री एल. एन. डावर ने एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 52 प्रतिशत शेयरों वाले वित्तीय संस्थानों के लिए बोलने का दावा करते हुए तीन नोट प्रसारित किए और प्रस्ताव पेश किए, जिसका उद्देश्य था कि रिट याचिका को वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि यह वित्तीय संस्थानों से परामर्श किए बिना दायर की गई थी और मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के लिए मामले को बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए और यह कि कुछ संस्थानों के ऋणों के आंशिक भुगतान में भेजे गए चेक को सर्वोच्च न्यायालय सुधार (1985) एस. यू. एफ. पी. के रूप में वापस लिया जाना चाहिए।

1010

सवाल अभी भी विचाराधीन था। श्री डावर द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। 9 जनवरी, 1984 को श्री नंदा ने श्री पुंजा को आईडी1 पर बोर्ड की बैठक में हुई घटनाओं के बारे में सूचित करते हुए लिखा कि पिछले 20 वर्षों में ऐसा एक भी अवसर नहीं आया है जब वित्तीय संस्थानों के पास प्रबंधन द्वारा लिए गए या प्रस्तावित किसी भी निर्णय के खिलाफ कहने के लिए एक शब्द भी न हो। प्रबंधन द्वारा अतीत में एक-दूसरे पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया था

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और वित्तीय संस्थान। श्री नंदा ने वित्तीय संस्थानों के ऋणों के पूर्व भुगतान और रिट याचिका दायर करने के संबंध में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के प्रबंधन की स्थिति के बारे में बताया। श्री नंदा ने बताया कि

रिजर्व बैंक ने कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज को शेयर खरीदने की अनुमति दी थी, उसने पहले से की गई किसी भी अवैधता को माफ नहीं किया था और यह अजीब बात थी कि वित्तीय संस्थानों को शेयर खरीदने के लिए दबाव डालना जारी रखना चाहिए।

शेयर पंजीकृत करने के लिए कंपनी। श्री नंदा ने यह भी कहा कि उन्होंने बार-बार श्री पुंजा और अन्य लोगों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि कपारो समूह की कंपनियों द्वारा प्रेषित धन से कहीं अधिक धन शेयरों की खरीद में निवेश किया गया था और इसलिए, विदेशों में प्रत्यावर्तन लाभ।

ऐसे शेयरों को उनके हस्तांतरण को पंजीकृत करके विनिमय की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। श्री नंदा ने शिकायत की कि उन्हें यह मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि संस्थान स्वराज पॉल की कंपनियों द्वारा खरीदे गए शेयरों के सम्मान-पंजीकरण के परिणामस्वरूप संस्थानों पर लाए गए बाहरी दबाव के कारण कंपनी के खिलाफ यह रवैया अपना रहे हैं। श्री पुंजा ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 13.1.1984 पर, श्री फंजा ने एस्कॉर्ट्स को सूचित किया कि वित्तीय संस्थानों ने प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया है

बकाया ऋण के पूर्व भुगतान के लिए एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। इस स्तर पर, यानी आईडी1 पर, जीवन बीमा निगम के बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई और यह संकल्प लिया गया कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को नौ गैर-कार्यकारी निदेशकों को हटाने और उनके स्थान पर वित्तीय संस्थानों के नए निदेशकों, अधिकारियों और नामितों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए एक असाधारण आम बैठक बुलाने के लिए एक अनुरोध किया जाना चाहिए। यह विषय जीवन बीमा निगम राशन बोर्ड की बैठक के एजेंडे में सूचीबद्ध मामलों में से एक नहीं था। एक को छोड़कर निगम के सभी अधिकारियों के बैठक से चले जाने के बाद प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक के कार्यवृत्त में कोई चर्चा दर्ज नहीं की गई। लेकिन कार्यवृत्त से पता चलता है कि आईडी1 के श्री फंजा जीवन बीमा निगम के निदेशक के रूप में अपनी क्षमता में मौजूद थे। इसके बाद जीवन बीमा निगम ने एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की एक असाधारण आम बैठक बुलाने की मांग की।

कंपनी।

1011

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्फा रेली, जे।]

घटनाओं का क्रम क्या दिखाता है? यह दर्शाता है कि वित्तीय संस्थान जिनके पास 52 प्रतिशत शेयर थे

कंपनी और इसलिए, इसके कामकाज और भविष्य में बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी, इस बात से व्यथित थे कि प्रबंधन ने उनसे परामर्श करने या उन्हें सूचित करने का विकल्प भी नहीं चुना कि एक रिट याचिका दायर करने का प्रस्ताव था जो कंपनी को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ कठिन और महंगी मुकदमेबाजी में शामिल करेगी। वित्तीय संस्थान श्री नंदा के दोहरेपन से प्रभावित हुए होंगे, जो उनके साथ चर्चा कर रहे थे, जब वे एक साथ उस कंपनी का शुभारंभ कर रहे थे, जिसमें वे बहुसंख्यक शेयरधारक थे और उन्हें सूचित किए बिना किसी मुकदमेबाजी में संभवतः परेशान कर रहे थे। वित्तीय संस्थान राज्य के सहायक थे और रिजर्व बैंक भी और इस तरह की मुकदमेबाजी शुरू करना मूर्खतापूर्ण समझा गया होगा। इसलिए संस्थान रिट याचिका को वापस लेने और इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए उत्सुक थे। चूँकि प्रबंधन इस मार्ग के लिए सहमत नहीं था, जीवन बीमा निगम ने सोचा कि उसके पास गैर-कार्यकारी निदेशकों को हटाने की मांग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि नया बोर्ड इस सवाल पर विचार कर सके कि मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने के निर्णय को उलट दिया जाए या नहीं। जाहिर है कि वित्तीय संस्थान चाहते थे कि

सरकार और रिजर्व बैंक के साथ टकराव से बचें और अधिक सुलहकारी दृष्टिकोण अपनाएं। साथ ही, जीवन बीमा निगम के प्रस्ताव में कार्यकारी निदेशकों को हटाने की मांग नहीं की गई थी, जाहिर है क्योंकि उनका इरादा कंपनी के प्रबंधन को बाधित करने का नहीं था। इसलिए, भारतीय जीवन बीमा निगम पर नौ गैर-कार्यकारी निदेशकों को हटाने और उन्हें वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिस्थापित करने की मांग में दुर्भावनापूर्ण कार्य करने का आरोप लगाना मुश्किल है। के खिलाफ कोई आक्षेप नहीं लगाया गया था

निदेशकों को हटाने का प्रस्ताव रखा गया। यह एकमात्र तरीका था जिसके द्वारा बोर्ड द्वारा मुकदमेबाजी शुरू करने में अपनाई गई नीति पर पुनर्विचार किया जा सकता था और यदि आवश्यक हो तो उसे उलट दिया जा सकता था। यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। सत्ता की काठी में अल्पांश शेयरधारकों को एक मुकदमे में प्रवेश करने की नीति को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जिसके लिए अधिकांश

शेयरधारकों ने इसका विरोध किया। कॉरपोरेट लोकतंत्र इस तरह से काम नहीं कर सकता है।

एक कंपनी, कुछ मामलों में, एक राज्य जैसी संस्था है जो अपने आधार संविधान के तहत काम कर रही है। कंपनी अधिनियम और संगठन ज्ञापन। संवैधानिक कानून की उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, गोवर बताते हैं

" सामान्य बैठक में सदस्य "और निदेशालय एक कंपनी के दो प्राथमिक अंगों के रूप में और उनकी तुलना कानून 1012 से करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. 3 एस सी आर।

संसदीय लोकतंत्र के स्थानीय और कार्यकारी अंग जहां विधायी संप्रभुता संसद के पास होती है, जबकि प्रशासन कार्यकारी सरकार पर छोड़ दिया जाता है, जो सरकार को बदलने के लिए मजबूर करने की अपनी शक्ति के माध्यम से संसद द्वारा नियंत्रण के एक उपाय के अधीन होता है। सरकार की तरह, निदेशक आम बैठक द्वारा गठित 'संसद' के प्रति जवाबदेह होंगे। लेकिन व्यवहार में (सरकार की तरह) वे संसद पर उतना ही नियंत्रण रखेंगे जितना उन पर। हालाँकि सामान्य बैठक में कंपनी के लिए सभी शक्तियों का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से संभव होगा।

कंपनी, यह स्पष्ट रूप से व्यावहारिक नहीं होगा (एक या दो-आदमी कंपनियों के मामले को छोड़कर) इस तरह की बोझिल मशीनरी द्वारा किए जाने वाले दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए। इसलिए आधुनिक प्रथा निदेशकों को अधिकार प्रदान करना है

सामान्य कानून को छोड़कर कंपनी की सभी शक्तियों का प्रयोग करें।

सामान्य बैठक में स्पष्ट रूप से प्रावधानों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक कंपनी कानून के गोवर के सिद्धांत। बेशक, जो शक्तियां सख्ती से विधायी हैं, वे निदेशकों को शक्तियों के प्रदान करने से प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 31 में प्रावधान है कि किसी अनुच्छेद में परिवर्तन के लिए सामान्य बैठक में कंपनी के विशेष संकल्प की आवश्यकता होगी। लेकिन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि कई मायनों में कंपनी की तुलना में निदेशालय की स्थिति संसद की तुलना में सरकार की स्थिति से अधिक शक्तिशाली है। संसदीय संप्रभुता का सख्त सिद्धांत किसी कंपनी के लिए सादृश्य से लागू नहीं होगा क्योंकि कंपनी अधिनियम के तहत, निदेशकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई शक्तियां हैं जिनके साथ सामान्य बैठक में सदस्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वे सबसे अधिक निदेशालय को बर्खास्त कर सकते हैं और उनके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, या अनुच्छेदों में बदलाव कर सकते हैं ताकि भविष्य के लिए निदेशकों की शक्तियों को प्रतिबंधित किया जा सके। गोवर स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि आम बैठक में सदस्यों और कंपनी के निदेशकों के संबंध में विधायिका और कार्यपालिका का सादृश्य एक अति-सरल कथन है और कहते हैं कि "कुछ हद तक अधिक सटीक सादृश्य संघीय संविधान के तहत संघीय और राज्य विधानमंडल के बीच शक्तियों का विभाजन होगा।" जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, आम बैठक में सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से निदेशालय पर अपने नियंत्रण का प्रयोग करने का एकमात्र प्रभावी तरीका लेखों में बदलाव करना है ताकि भविष्य के लिए निदेशकों की शक्तियों को प्रतिबंधित किया जा सके या निदेशालय को बर्खास्त किया जा सके और उनके स्थान पर अन्य लोगों की नियुक्ति की जा सके। निगम के अधिकांश स्टॉक के धारकों के पास चुनाव द्वारा अपनी पसंद के निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति होती

है और उन्हें हटाने के लिए एक प्रस्ताव द्वारा उन्हें विनियमित करने की शक्ति होती है। और, एक निदेशक को हटाने और दूसरे को नियुक्त करने के लिए एक आम बैठक के आयोजन को रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

1013

शॉ एंड संस (सैल्फोर्ड) लिमिटेड बनाम शॉ 1935 2 के. बी. 113, ग्रीर, एल. जे. ने व्यक्त किया:

" एकमात्र तरीका जिसमें सामान्य निकाय

शेयरधारक निदेशकों में लेखों द्वारा निहित शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित कर सकते हैं लेख या, यदि लेखों के तहत अवसर उत्पन्न होता है, तो उन निदेशकों को फिर से चुनने से इनकार करके जिनकी कार्रवाई पर

उन्होंने अस्वीकार कर दिया। "

आइल ऑफ वाइट रेलवे कंपनी बनाम। ताबोरदीन (1883) 25 चांसरी डिवीजन 320, कॉटन एल. जे. ने कहा:

" फिर एक दूसरा उद्देश्य है, "किसी भी वर्तमान निदेशक को हटाना (यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए), और किसी भी रिक्ति को भरने के लिए निदेशकों का चुनाव करना।

बोर्ड "। नीचे के विद्वान न्यायाधीश ने सोचा कि यह बहुत अनिश्चित है, लेकिन मेरी राय में "किसी भी वर्तमान निदेशक" को हटाने का नोटिस उन सभी को हटाने के प्रस्ताव को उचित ठहराएगा जो वर्तमान में निदेशक हैं।

समय; "कोई भी" में "सभी" शामिल होंगे। मुझे लगता है कि एक नोटिस

उस रूप में सभी व्यावहारिक के लिए काफी हैउद्देश्य।

फ्राय, एल. जे. ने कहा,

" दूसरी आपत्ति यह थी कि "किसी भी वर्तमान निदेशक को हटाने (यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए) के लिए" बैठक बुलाने की मांग बहुत अस्पष्ट है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस कथन में पर्याप्त विशिष्टता है। कहा जाता है कि प्रत्येक निर्देशक को पता नहीं होता कि उस पर हमला किया गया है या नहीं। जवाब यह है कि सभी निर्देशकों को पता है कि वे हमले के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि किसी भी अन्य प्रकार की मांग शर्मनाक होगी, क्योंकि यह स्पष्ट है कि बैठक किसी निदेशक को हटाने या उसे उसके व्यवहार के अनुसार रहने की अनुमति देने के लिए उचित मान सकती है और

प्रस्तावों के संबंध में बैठक में व्यवहार

उस पर बनाया गया "।

इसी मामले में इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या आम बैठक के आयोजन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए, बैठक का एक उद्देश्य एक

कंपनी के प्रबंधन को पुनर्गठित करने वाली समिति, कॉटन एल. जे. ने कहा:

" इसे रोकना वास्तव में एक बहुत मजबूत बात है।

शेयरधारकों को कंपनी की बैठक आयोजित करने से, जब ऐसी बैठक ही एकमात्र तरीका है जिसमें वे कर सकते हैं

हस्तक्षेप करें यदि उनमें से अधिकांश सोचते हैं कि

निदेशक द्वारा लिया गया पाठ्यक्रम, एक मामले में अधिकार के भीतर

निदेशकों का, लाभ के लिए नहीं है

कंपनी "।

इंदरविक बनाम। स्नेल, 42 अंग्रेजी रिपोर्ट 83, का विलेख

"कार्यालय में लापरवाही, दुराचार या किसी अन्य उचित कारण" के लिए किसी भी निदेशक को हटाने के लिए कंपनी का समझौता। कुछ निदेशकों को हटा दिया गया और अन्य को नियुक्त किया गया। जिन निदेशकों को हटा दिया गया था, उन्होंने नए निदेशकों को इस आधार पर कार्य करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया कि उन्हें हटाने का कोई उचित कारण नहीं था। न्यायालय ने हटाने के कारणों की न्यायिक समीक्षा के दावे को अस्वीकार कर दिया और

निम्नलिखित दिलचस्प टिप्पणियाँ:

" वादी वादी के लिए तर्क इस आरोप पर आधारित था कि हटाने का सामान्य कारण संदर्भित किया गया था

खंड में 'उचित' के रूप में व्यक्त किया जा रहा है जो निर्दिष्ट शक्ति को एक शक्ति होने से रोकता है

खुशी में मनमाने ढंग से या मनमौजी तरीके से हटा दें, और

यह आवश्यक बना दिया कि शक्ति का प्रयोग करने के लिए कार्यवाही अपनी प्रकृति में न्यायिक होनी चाहिए, और यह कि उचित कारण ऐसा होना चाहिए जैसे कि

न्याय को अच्छा और पर्याप्त माना जाएगा। अगर यह तर्क को कायम रखा जा सकता है, ऐसी बैठकों में सभी कार्यवाहियां न्यायालयों की समीक्षा के अधीन होंगी, जिन्हें यह जांच करनी होगी कि क्या

हटाने का कारण जो आरोप लगाया गया था उनमें थाउचित, क्या आरोप प्रामाणिक थे। आगे, क्या उन्हें आवश्यक मामले की प्रकृति के रूप में ऐसे साक्षय द्वारा प्रमाणित किया गया था, और

क्या निष्कर्ष देय पर आया था

आरोप और साक्षय पर विचार करना। लेकिन कर्म

इन मामलों के बारे में चुप है, और सवाल है

क्या न्याय के न्यायालयों में नियंत्रण की ऐसी किसी शक्ति का अनुमान 27वें खंड में निहित "उचित कारण" शब्दों से लगाया जाना है; क्या व्यापार साझेदारी के ऐसे विलेख में निहित "उचित खंड" अभिव्यक्ति को ऐसा माना जा सकता है -

कारण, जैसा कि न्यायालय में जाँच पर

पर्याप्त साक्षय और न्यायपूर्ण आधार पर प्रामाणिक माना जाना चाहिए; या क्या इसका अर्थ ऐसा कारण नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि 1015 की राय में है।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

विधिवत एकत्रित शेयरधारकों को उचित माना जाएगा। हम सोचते हैं कि बाद वाला ही विलेख का वास्तविक निर्माण और प्रभाव है।

नैतिक दृष्टिकोण से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हटाने के कारण के प्रत्येक आरोप को प्रामाणिक बनाया जाना चाहिए।

पर्याप्त साक्षय द्वारा प्रमाणित, और निर्धारित किया गया आरोप और साक्षय पर उचित विचार करने पर; और जो अन्य सिद्धांतों पर कार्य करते हैं वे दोषी हो सकते हैं

नैतिक अपराध; वे बहुत अन्यायपूर्ण हो सकते हैं, और जो लोग (उन्हें दिए गए बयानों से गुमराह किए जा रहे हैं, उन्हें कोई संदेह नहीं है कि शिकायत करने का न्यायसंगत अधिकार है कि उन्हें एक अन्यायपूर्ण कार्य में सहमति देने के लिए प्रेरित किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस विलेख के माध्यम से एक

आम बैठक में विधिवत रूप से इकट्ठे हुए शेयरधारकों को एक ऐसे कारण के लिए निदेशक को हटाने का अधिकार नहीं था, जो उन्होंने सोचा था।

यह तर्कसंगत है कि इस या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष यह साबित करना उनके लिए बाध्यकारी नहीं है कि आरोप सही था और निर्णय न्यायसंगत था, या कि साक्षय और आरोप पर उचित विचार करने के बाद मामले की पुष्टि की गई थी। हम यह कहने के लिए खुद को नहीं ले सकते कि एक व्यापारिक साझेदारी के मामले में जैसे

यह, इस न्यायालय के पास साझेदारी क्षेत्राधिकार या प्राधिकरण के विलेख में ऐसा खंड है जो निर्धारित करने के लिए है

चाहे, आरोप के किसी भी समर्थक के निराधार भाषण से, उपस्थित शेयरधारकों को गुमराह या अनुचित रूप से प्रभावित नहीं किया गया हो।

ऐसी सभी बैठकें झूठे या गलत बयानों से गुमराह होने के लिए उत्तरदायी हैं, और इस तरह की त्रुटि या अन्याय की मात्रा की शायद ही कभी सराहना की जा सकती है। यह न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि क्या बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती थी, और धोखाधड़ी के मामलों में स्पष्ट रूप से साबित होता है, शायद किए गए कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है; लेकिन यह मानते हुए कि बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है।

ऐसी बैठक में एकत्रित और आयोजित शेयरधारक विलेख द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। भाषणों और अभ्यावेदनों के प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और उन लोगों के लिए जो खुद को इस तरह के अभ्यावेदनों से व्यथित मानते हैं, या निष्कर्ष को अनुचित मानते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र उपाय सत्य बताते हुए बचाव प्रस्तुत करना और जांच और सबूत के लिए समय की मांग करना, या दूसरी बैठक बुलाना है, जिस पर पूरे मामले पर फिर से विचार किया जा सकता है।

वादी, इस सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1.85] प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए। 3 एस सी आर।

1016

बैठक और इसे अवैध मानते हुए, विरोध किया

यह, लेकिन भाग लेने से परहेज किया और, इसलिए, बनाया गया

इसका कोई जवाब या बचाव नहीं है और इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

उन पर लगाए गए आरोप। इस पाठ्यक्रम को अपनाना

दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन इसके लिए कोई आधार नहीं है

इस न्यायालय का हस्तक्षेप "।

फिर से बेंटले में-स्टीवंस बनाम। जोन्स, 1971 (2) ऑल ई. आर. 653,

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक शेयरधारक को एक निदेशक को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का वैधानिक अधिकार था और यह कि अदालत को इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा देने का अधिकार नहीं था। निदेशक का एक उचित किराया इस आधार पर समापन आदेश के लिए आवेदन करना था कि इस तरह का आदेश देना अदालत के लिए न्यायसंगत और न्यायसंगत था। इब्राहिमी बनाम का मामला। वेस्टबोर्न गैलरीज लिमिटेड, 1972 (2) ऑल ई. आर. 492 को एक ऐसे मामले के रूप में समझाया गया था जिसमें समापन आदेश की मांग की गई थी। एब्रेहिमी बनाम के मामले में। वेस्टबोर्न गैलरीज लिमिटेड

(ऊपर), निदेशकों को हटाने के लिए आम बैठक के पूर्ण अधिकार को मान्यता दी गई थी और यह बताया गया था कि यह निदेशक के लिए खुला होगा जिसे कंपनी न्यायालय को समाप्त करने के आदेश के लिए इस आधार पर हटाने की मांग की गई थी कि ऐसा करना 'न्यायसंगत और न्यायसंगत' होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा,

" मेरे स्वामी, यह निष्कासन का मामला है, और मुझे ऐसा करना चाहिए।

ऐसे मामले में आवेदन को संक्षेप में उचित ठहराएँ

न्यायसंगत और न्यायसंगत खंड।

कई में

कंपनियों का कानून अधिकार को मान्यता देता है,वैसे, बोर्ड से एक निदेशक को हटाने के लिए। धारा 184

कंपनी अधिनियम 1948 का यह अधिकार प्रदान करता है -

सामान्य बैठक में कंपनी जो भी कलाकार कर सकते हैं

उदाहरण के लिए, एक शासी निदेशक के पास शक्ति हो सकती हैहटाएँ (आर. एफ. री वोंडोफ्लेक्स टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड)। और काफी

हटाने की शक्तियों के अलावा, आम तौर पर हैं

आवर्तन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान

कि उनके पुनर्निर्वाचन का विरोध किया जा सकता है और पराजित किया जा सकता है बहुमत, या यहां तक कि एक निर्णायक वोट से भी। इन सब में

जिस तरह से एक विशेष निदेशक-सदस्य खुद को नहीं पा सकता है

निदेशक को हटाने के माध्यम से, या गैर-पुनःचुनावः इस स्थिति को उसे आम तौर पर स्वीकार करना चाहिए,

जब तक कि वह धोखाधड़ी प्रदान करने का बोझ नहीं उठाता है या

दुर्भावनापूर्ण। न्यायसंगत और न्यायसंगत प्रावधान:

फिर भी अगर वह इशारा कर सकता है तो उसकी मदद के लिए आता है

कुछ विशेष अंतर्निहित दायित्वों को सिद्ध करना और

उसके साथी सदस्य (ओं) सद्भावना में, या विश्वास में,

जब तक उसका उपयोग जारी रहेगा भागीदारी प्राप्त करने का हकदार, एक दायित्व इसलिए एल. आई. सी. v.

एस्कॉर्ट्स [चिनाप्फा रेली, जे।]

1017

बुनियादी है कि अगर टूट गया है, तो निष्कर्ष यह होना चाहिए कि

संगठन को भंग किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि किसी कंपनी के प्रत्येक शेयरधारक के पास

वैधानिक रूप से निर्धारित प्रक्रियात्मक और संख्यात्मक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक असाधारण आम बैठक बुलाने का अधिकार। उन्हें बैठक बुलाने से रोका नहीं जा सकता है और वह बैठक में प्रस्तावित प्रस्तावों के कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। न ही संकल्पों के कारण विषय हैं।

को

न्यायिक समीक्षा। यह सच है कि एस के तहत। 173 (2) कंपनी अधिनियम की बैठक की सूचना के साथ संलग्न किया जाएगा

प्रत्येक वस्तु से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों को निर्धारित करना

सामान्य बैठक से पहले शेयरधारकों को उनके सामने व्यवसाय पर निर्णय लेने में सक्षम बनाना। इसके लिए शेयरधारकों को बैठक बुलाकर उन प्रस्तावों के कारणों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें वे बैठक में पेश करने का प्रस्ताव करते हैं। एस्कॉर्ट्स के शेयरधारक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, प्रत्येक शेयरधारक को कॉल करने का समान अधिकार है

कुछ निदेशकों को हटाने और उनके स्थान पर अन्य लोगों को नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव लाने के उद्देश्य से कंपनी की असाधारण आम बैठक। भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है और न ही वह प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के अपने कारणों का खुलासा करने के लिए बाध्य है।

हालाँकि, विद्वान वकील द्वारा इसका आग्रह किया गया था

कंपनी ने कहा कि जीवन बीमा निगम राज्य का एक साधन था और इसलिए, कला द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। 14 मनमाने ढंग से कार्य करने से। इसलिए, यह एक दायित्व के तहत था कि अदालत को एक बार नियम निसी जारी किए जाने के बाद प्रस्ताव के लिए अपने कारणों को बताए। यदि वह अपने कारणों का खुलासा करने में विफल रहा

न्यायालय यह मान लेगा कि उसके पास देने के लिए कोई वैध कारण नहीं था और इसलिए उसकी कार्रवाई मनमाना थी। विद्वान वकील ने सुखदेव सिंह, मेनका गांधी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अजय हासिया में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया। दूसरी ओर, विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि राज्य की कार्रवाई या राज्य का एक साधन जो ठीक से सार्वजनिक कानून के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, लेकिन निजी कानून के क्षेत्र से संबंधित है, न्यायिक के अधीन होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

समीक्षा करें। उन्होंने ओ 'रेली बनाम पर भरोसा किया। हैकमैन [1982] 3 ऑल ई. आर. 1124,1018

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. 3 एस सी आर।

डेवी वी. वर्तनी [1983] 3 ऑल ई. आर. 278, आई. कांग्रेस डेल पार्टिडो 1981 2 ऑल ई. आर. 1064, आर. वी. ईस्ट बर्कशायर स्वास्थ्य प्राधिकरण

[1984] 3 सभी ई. आर. 425, और राधा कृष्ण अग्रवाल और अन्य। V. बिहार राज्य [1977] 3 एस. सी. आर. 249. यद्यपि हम विद्वान महान्यायवादी के तर्क में काफी बल पाते हैं, हमारे लिए इस विषय पर किसी भी लंबी चर्चा में प्रवेश करना आवश्यक नहीं हो सकता है, जैसा कि हम वर्तमान में देखेंगे। हम संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून और सार्वजनिक कानून के प्रश्नों पर अंग्रेजी मामलों को आसानी से संदर्भित करने के खिलाफ खुद को चेतावनी देना चाहते हैं क्योंकि इन शाखाओं में भारत में कानून इंग्लैंड में कानून से पहले बना है, जैसा कि हम अपने संविधान द्वारा निर्देशित हैं और बिना किसी बाधा के हैं क्योंकि हम उन तकनीकी नियमों द्वारा हैं जिन्होंने अंग्रेजी कानून के विकास में बाधा उत्पन्न की है। हालांकि हमें एक पल के लिए भी संदेह नहीं है कि राज्य की हर कार्रवाई या राज्य की एक साधनता

कारण द्वारा सूचित किया जाता है और यह कि, उचित मामलों में, कारण से अनजान कार्यों को कला के तहत आगे बढ़ने में मनमाना माना जा सकता है। 226 या कला। 32 संविधान के अनुसार, हम राज्य के कार्यों की न्यायिक समीक्षा के लिए एक चार्टर के रूप में नहीं समझते हैं और राज्य से इस तरह के कार्यों के कारण बताते हुए अपनी कई गतिविधियों में अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होने का आह्वान करते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि राज्य की कार्रवाई राजनीतिक या संप्रभु है, तो अदालत इससे दूर रहेगी। न्यायालय शैक्षणिक मामलों पर बहस नहीं करेगा या व्यापार और वाणिज्य की पेचीदगियों से संबंधित नहीं होगा। यदि राज्य की कार्रवाई अपकृत्य से उत्पन्न होने वाले संविदात्मक दायित्वों या दायित्वों से संबंधित है, तो न्यायालय सामान्य रूप से इसकी जाँच नहीं कर सकता है जब तक कि कार्रवाई से कुछ सार्वजनिक कानून का चरित्र न जुड़ा हो। मोटे तौर पर, न्यायालय राज्य की कार्रवाइयों की जांच करेगा यदि वे सार्वजनिक कानून क्षेत्र से संबंधित हैं और यदि वे निजी कानून क्षेत्र से संबंधित हैं तो उनकी जांच करने से बचें। कठिनाई इसमें होगी

सार्वजनिक कानून क्षेत्र और निजी कानून क्षेत्र के बीच की सीमा का सीमांकन करना। रेखा खींचना असंभव है

सटीकता और हम इसका प्रयास नहीं करना चाहते हैं। प्रत्येक मामले में प्रश्न का निर्णय उस विशेष कार्रवाई, उस गतिविधि के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें राज्य या राज्य का साधन कार्रवाई करते समय लगा हुआ है, कार्रवाई की सार्वजनिक कानून या निजी कानून की प्रकृति और कई अन्य प्रासंगिक परिपथ स्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। जब राज्य या राज्य का कोई साधन निगम जगत में उद्यम करता है और किसी कंपनी के शेयरों की खरीद करता है, तो वह खुद को एक शेयरधारक की सामान्य भूमिका मानता है, और एक शेयरधारक के वस्त्र धारण करता है, जिसमें ऐसे शेयरधारक को सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक शेयरधारक के रूप में राज्य से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि जब वह प्रबंधन को बदलना चाहता है तो कंपनी के किसी भी प्रस्ताव के माध्यम से अपने कारणों को बताए।

अन्य शेयरधारक।

1019

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

जानबूझकर इसके बारे में अंधेरे में रखा गया। रिट याचिका से पहले निदेशकों की बैठक में भी इस मामले पर चर्चा नहीं की गई थी दाखिल किया गया। यह एक भद्दे तरीके से दायर किया गया था, जबकि श्री नंदा श्री पुंजा और अन्य लोगों के साथ चर्चा करने का इरादा रखते थे। और यही सब नहीं है। श्री नंदा कुछ मामलों में भी अनावश्यक रूप से प्रयास कर रहे थे जिससे बहुसंख्यक शेयरधारकों को नुकसान हो रहा था। हम तुरंत उन मामलों का उल्लेख करेंगे।

भारतीय जीवन बीमा निगम की दुर्भावना को स्थापित करने के लिए निर्भर परिस्थितियों में से एक, एक विचार

जिनमें से हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि बूट दूसरे चरण में था, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा (i) इक्विटी-लिंक्ड डिबेंचर के मुद्दे के संबंध में लिया गया रवैया था; (ii) भारतीय वित्तीय संस्थानों को ऋणों

का पुनर्भुगतान; और (iii) एस्कॉर्ट्स के साथ गोएट्ज़ के विलय का प्रस्ताव। यह तर्क दिया गया था कि तथ्यों ने स्पष्ट रूप से एक

भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से एस्कॉर्ट्स लिमिटेड पर दबाव बनाने का प्रयास। प्रस्तुतिकरण से सहमत होना असंभव है।

इक्विटी-लिंक्ड डिबेंचर जारी करने के प्रस्ताव के संबंध में तथ्य इस प्रकार हैं: एस्कॉर्ट्स ने प्राप्त किया

मोटर साइकिल/स्कूटर के निर्माण के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए M.R.T.P अधिनियम के तहत सरकार की मंजूरी। एस्कॉर्ट्स के अनुसार, इक्विटी जारी करने का प्रस्ताव-जुड़ा हुआ है

नई परियोजना की लागत को पूरा करने के लिए ऋणपत्रों की कल्पना की गई थी। जीवन बीमा निगम के अनुसार, यह मुद्दा पूरी तरह से जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं की हिस्सेदारी के प्रतिशत को कम करने की चिंता से प्रेरित था

कम्पनीक इक्विटी पूँजीमे संस्थासभ। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से अंततः सामने आए प्रस्ताव की सबसे बड़ी जांच एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के खेल को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। प्रस्ताव, जैसा कि यह अंत में एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से सामने आया, प्रत्येक Rs.100 के डिबेंचर 17,50,000 सिक्योर रिडीमेबल डिबेंचर और 500 करोड़ रुपये के मूल्य के इक्विटी शेयर जारी करना था। 17.50 करोड़ रुपये प्रति शेयर Rs.10 के प्रीमियम पर नकद के लिए Rs.10 के 87,50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित। यह प्रस्ताव किया गया था कि नए निर्गम का 20 प्रतिशत एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और गोएट्ज़ लिमिटेड के मौजूदा निवासी इक्विटी शेयरधारकों को (समामेलन प्रस्ताव के अनुसार) वरीयता के आधार पर किसी भी एकल शेयरधारक को अधिकतम 100 डिबेंचर और 500 इक्विटी शेयरों के आवंटन के अधीन पेश किया जाएगा। प्रवर्तक, निदेशक और उनके मित्र और रिश्तेदार, व्यावसायिक सहयोगी और कर्मचारी 1020 होने वाले थे।

तरजीही आधार पर नए निर्गम के 15 प्रतिशत की पेशकश की गई, लेकिन उनके मामले में शेयरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए जो उनमें से किसी एक को आवंटित की जा सकती है। 30 नए निर्गम का प्रतिशत जनता को दिया जाना था। मौजूदा इक्विटी शेयरधारकों को आवंटन के मामले में प्रस्तावित 500 शेयरों की सीमा को ध्यान में रखते हुए, जीवन बीमा

निगम, इस तथ्य के बावजूद कि उसके पास एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के 30 प्रतिशत शेयर हैं, नए निर्गम में केवल 500 शेयरों का हकदार होगा। परिणाम यह होगा कि इसकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से घटकर

18.14 प्रतिशत हो जाएगी। सभी वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी 51.62 से घटाकर 31.21 प्रतिशत कर दी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप न केवल कंपनी के पूंजी स्टॉक में वित्तीय संस्थानों की हिस्सेदारी के प्रतिशत में कमी आएगी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप संस्थानों को निम्नलिखित तरीके से भारी वित्तीय नुकसान भी होगा: यदि मौजूदा शेयरधारकों को उनके मौजूदा निर्गम के आधार पर नए निर्गम में तरजीही आवंटन दिया जाना था

होल्डिंग्स, बिना किसी सीमा के, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थान प्रत्येक अल्प 500 शेयरों के हकदार नहीं होंगे, बल्कि नए निर्गम में कुछ टन हजारों शेयरों के हकदार होंगे। प्रति शेयर Rs.50 पर शेयरों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय संस्थानों को नुकसान लगभग ks के आसपास होगा। 10 करोड़। हमें नहीं लगता कि कोई भी वित्तीय संस्थान थोड़ा भी व्यावसायिक कौशल वाला हो।

संभवत: प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था क्योंकि यह अंतत: एस्कॉर्ट्स लिमिटेड से सामने आया था। साधारण विवेक वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। वित्तीय संस्थानों से सहमत होने की अपेक्षा करना

यह प्रस्ताव, हमें कहना होगा, प्रस्ताव बनाने वालों की ओर से सरासर दुस्साहस था। स्पष्ट रूप से यही कारण था कि सभी प्रारंभिक चरणों में, प्रस्ताव का विवरण कभी भी वित्तीय संस्थानों या बोर्ड के समक्ष नहीं रखा गया था। निदेशक। श्री नरीमन ने आग्रह किया कि निदेशक मंडल में वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री लावार ने भी शुरुआती चरणों में प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और इसलिए यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थानों की ओर से बाद में दृष्टिकोण में बदलाव सही नहीं था। हमें डर है कि हम श्री नरीमन से सहमत नहीं हो सकते। निदेशक मंडल के प्रस्ताव ने केवल वित्तीय संस्थानों के अनुमोदन के अधीन कंपनी द्वारा आवश्यक वित्त जुटाने के लिए परिवर्तनीय डिबेंचर के मुद्दे को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। उस स्तर पर प्रस्ताव का कोई विवरण बोर्ड के समक्ष नहीं रखा गया था और तब भी यह आरक्षण था कि यह इसके अधीन था

वित्तीय संस्थानों की मंजूरी। हम सोचते हैं कि श्री नंदा और उनके सहयोगियों के लिए यह उम्मीद करना बहुत अधिक था कि वित्तीय संस्थान या उस मामले में कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले किसी अन्य शेयरधारक प्रस्ताव पर सहमत होंगे क्योंकि यह अंतत: सामने आया था। जब हम 1021 की शिकायत सुनते हैं तो हम सीमा तक पहुँच जाते हैं।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

श्री नंदा और उनके सहयोगियों ने कहा कि वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करना दुर्भावनापूर्ण था। यह श्री नंदा और उनके सहयोगियों की ओर से खुद तक पहुंचने के प्रयास

का एक स्पष्ट मामला है। हमें नहीं लगता कि इक्विटी-लिंक्ड-डिबेंचर मुद्दे के संबंध में हमारे लिए किसी और विवरण में जाना आवश्यक है।

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के साथ गोएत्ज़े के विलय के प्रस्ताव पर भी पहली बार में सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी थी। हालांकि, हिस्सेदारी

उस समय भी वित्तीय संस्थानों द्वारा विनिमय अनुपात पर स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दी गई थी। यह पत्र से स्पष्ट है। श्री नंदा ने श्री नधरना आई. सी. आई. सी. आई. को दिनांकित आई. डी. 1 दिया जिसमें उन्होंने कहा:

" चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की रिपोर्ट और निदेशक मंडल के प्रस्ताव के साथ प्रस्ताव आईसीआईसीआई और आईएफसीआई के पास हैं और हम समझते हैं कि इस मामले पर वित्तीय संस्थानों की अंतर-संस्थागत बैठक में चर्चा की गई है। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सभी वित्तीय संस्थानों से उनकी मंजूरी में तेजी लाने के लिए कई अनुरोध किए हैं ताकि उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद दोनों कंपनियों की असाधारण शेयरधारकों की बैठक के बाद विलय की अन्य प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकें। वित्त संस्थानों के अध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यकारी के साथ कल की बैठक में, मुझे पहली बार सूचित किया गया कि वित्तीय संस्थान अभी भी जांच कर रहे हैं

अनुमोदन के लिए हमारा अनुरोध वे मुख्य रूप से विलय के बाद सभी निवेश वित्तीय संस्थानों (एल. आई. सी., जी. आई. सी., यू. टी. आई.) की 53 प्रतिशत हिस्सेदारी के बारे में चिंतित थे। लगभग 49 प्रतिशत।

पत्र से पता चलता है कि श्री नंदा इस आधार पर आगे नहीं बढ़ रहे थे कि वित्तीय संस्थान पहले ही सहमत हो चुके थे

विलय का प्रस्ताव था, लेकिन वास्तव में उनकी मंजूरी का इंतजार था। जब उन्हें प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए वित्तीय संस्थान की हिचकिचाहट का कारण पता चला, तो उन्होंने अपने विचारों को समझाते हुए 30.12.1983 पर एक पत्र लिखा और वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव की मंजूरी में तेजी लाने का अनुरोध किया। इसलिए, श्री नंदा के लिए यह कहना व्यर्थ है कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के साथ गोएट्ज़ के विलय का प्रस्ताव एक ऐसा लाभ था जिसका उपयोग वित्तीय संस्थान उन पर दबाव बनाने के लिए कर रहे थे ताकि वे कपारो समूह की कंपनियों के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए सहमत हो सकें। यह समझना मुश्किल है कि किसी कंपनी की अधिकांश इक्विटी पूंजी रखने वाले किसी व्यक्ति को ऐसा क्यों करना चाहिए।

स्वयं को अल्पांश शेयरधारक बनने की अनुमति दें।

संस्थागत ऋणों के पूर्व भुगतान का प्रस्ताव, हालांकि अंततः संस्थानों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, उतना सीधा नहीं था।

जैसा कि एस्कॉर्ट्स ने दावा किया है। सबसे पहले, एस्कॉर्ट्स ने भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों का पूर्व भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन विदेशी मुद्रा ऋण के लिए नहीं। दूसरा, संस्थागत ऋणों के पूर्व-भुगतान की लागत को डिबेंचर इश्यू के हिस्से से पूरा किया जाना था, जिसमें 14 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होता था, जबकि संस्थागत ऋणों पर केवल 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता था। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय वित्तीय संस्थानों को देय दर से अधिक दर पर ब्याज देना कंपनी के हित में है। जाहिर है कि पूर्व-भुगतान का उद्देश्य उन निदेशकों से छुटकारा पाना था जिन्हें वित्तीय संस्थानों को नामित करने का अधिकार था। ट्रू एस्कॉर्ट्स ने श्री डावर को निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पेशकश की, भले ही वित्तीय संस्थानों को उन्हें नामित करने का कोई अधिकार न हो। लेकिन निर्देशक को नामित करने का अधिकार होना एक बात है और पीड़ित होने पर निर्देशक के लिए यह बिल्कुल अलग बात है।

हम नहीं समझते कि इन पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

जितना हमने किया है, उससे अधिक विस्तार से प्रस्ताव। दोनों पक्षों के बीच जो पत्राचार हुआ और जो हमें पढ़ा गया है, उससे पता चलता है कि श्री नंदा निश्चित रूप से वित्तीय संस्थानों को प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे।

हमने व्यापक परिप्रेक्षय में हमें दी गई प्रस्तुतियों पर चर्चा की है। हमने उन असंख्य बारीकियों का उल्लेख नहीं किया है जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई थीं, क्योंकि हम ऐसा करने को अनावश्यक मानते हैं और हम पहले से ही लंबे निर्णय को और लंबा नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने उन सभी छोटी-छोटी दलीलों और तुच्छ विवरणों को ध्यान में नहीं रखा है जो हमारे लिए लाए गए थे।

नोटिस करें।

अब हम अपने निष्कर्ष इस प्रकार बता सकते हैं:

1. एफ. ई. आर. ए. द्वारा अनुध्यात रिजर्व बैंक की अनुमति पूर्व-कार्योत्तर और सशर्त हो सकती है।

2. 17.9.83 दिनांकित प्रेस विज्ञप्ति (Ex. A), 19.9.83 दिनांकित परिपत्र (Ex. B) और 19.9.83 दिनांकित पत्र (Ex. C) सभी मान्य हैं।

3. इस योजना के तहत, कोई भी विदेशी कंपनी जिसके शेयरों का स्वामित्व 60 प्रतिशत से अधिक भारतीय व्यक्तियों के पास था।

राष्ट्रीयता या मूल द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या अलग-अलग कंपनियों में शेयरधारकों का एक ही समूह था।

एल. आई. सी. वी. एस्कॉर्ट्स [चिनाप्पा रेड्डी, जे।]

1023

4. जहां कोई भी खरीद 2.5.83 के बाद की गई थी, वे 5 प्रतिशत की सीमा के अधीन थे।

कुल मिलाकर।

5. भारतीय रिजर्व बैंक कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज को अनुमति देने में किसी भी दुर्भावना का दोषी नहीं था। न ही यह दिमाग का उपयोग न करने का दोषी था।

6. किसी भी दुर्भावना का श्रेय भारत संघ को नहीं दिया जा सकता है

भी।

7. पंजाब नेशनल बैंक की ओर से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कुल और संकेत विफलता थी

एफ. ई. आर. ए. के तहत अधिकृत डीलर और इस योजना के परिणामस्वरूप कपारो ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से की गई शेयरों की खरीद की कोई निगरानी नहीं थी।

8. भारतीय जीवन बीमा निगम के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप निराधार थे।

9. भारतीय जीवन बीमा निगम की कंपनी की बैठक की मांग करने वाला नोटिस उत्तरदायी नहीं था

उन आधारों में से किसी के बारे में पूछताछ की गई जिन पर रिट याचिका में सवाल उठाने की मांग की गई थी।

हमारे इस निष्कर्ष पर कि कपारो समूह की ओर से की गई शेयरों की खरीद की कोई निगरानी नहीं थी

पंजाब नेशनल बैंक की कंपनियाँ और हमारे आगे के निष्कर्ष पर कि हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक दुर्भावना से प्रेरित नहीं था और विवेक का उपयोग न करने का दोषी नहीं था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर रखी गई निर्भरता इस स्थिति में गलत थी कि पंजाब नेशनल बैंक ने अधिकृत डीलर के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से छोड़ दिया था।

कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता के आलोक में रिजर्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति पर रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, भारत संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम की अपीलों को स्वीकार करते हुए और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड की अपील को खारिज करते हुए और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए, हम भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश देते हैं कि वह कपारो समूह की कंपनियों द्वारा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के शेयरों की खरीद की पूरी और विस्तृत जांच करे और इस सवाल पर नए सिरे से विचार करे कि क्या अनुमति दी जानी चाहिए थी या नहीं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट है कि अनुमति

सायन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, यह पहले से दी गई अनुमति को रद्द कर सकता है और ऐसी आगे की कार्रवाई कर सकता है जो एफ. ई. आर. ए. के तहत आवश्यक हो यदि यह मानता है कि कोई उल्लंघन हुआ है 1024

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1985] एस. यू. पी. 3 एस सी आर।

एफ. ई. आर. ए. या योजना: यदि भारतीय रिजर्व बैंक का विचार है कि अनुमति प्रतिबंधों के अधीन दी जा सकती है, तो वह इस शर्त के अलावा ऐसे प्रतिबंध और शर्तें लगा सकता है जो वह उचित समझे, कि पूंजी या लाभ या दोनों को वापस नहीं किया जा सकता है। . हम उत्तरदाताओं को 3 से 17,20 और 21 (लिखित याचिका में), अर्थात पंजाब नेशनल बैंक, तेरह कपारो समूह की कंपनियों, श्री स्वराज पॉल, मैसर्स राजा राम भसीन एंड कंपनी और मैसर्स भारत भूषण एंड कंपनी को निर्देश देते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक को तेरह कपारो समूह की कंपनियों की ओर से शेयरों की खरीद के लिए किए गए प्रेषण और उनकी ओर से किए गए शेयरों की खरीद से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। उन्हें प्रत्येक दस्तावेज प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। रिजर्व बैंक द्वारा जांच आज से तीन महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

हम भारतीय रिजर्व बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के आचरण की जांच करने और ऐसी कार्रवाई करने का भी निर्देश देते हैं जो हो सके

धारा के तहत दिए गए प्राधिकरण को रद्द करने सहित आवश्यक है। 6 विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। लागतों के संबंध में, भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम निश्चित रूप से उनके हकदार हैं।

लागतें। हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी की लागत पर विचार क्यों किया जाना चाहिए। मुकदमा श्री नंदा द्वारा शुरू किया गया था और उन्हें व्यक्तिगत रूप से लागत के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। हम यह भी सोचते हैं कि श्री स्वराज पॉल और राजा काम भसीन एंड कंपनी द्वारा अदालत के समक्ष उपस्थित होकर सहयोग करने में विफलता के कारण मुकदमेबाजी अनावश्यक रूप से जटिल हो गई है। हम सोचते हैं कि उन्हें लागत के एक हिस्से के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक भी। भारतीय संघ, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दायर अपीलों को निम्नलिखित देय लागतों के साथ अनुमति दी गई है: प्रत्येक मामले में कर लागत का तीन-पाँचवाँ हिस्सा हर प्रसाद नंदा द्वारा, एक-पाँचवाँ हिस्सा स्वराज पॉल द्वारा और एक-पाँचवाँ हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक द्वारा देय होगा। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और नंदा द्वारा दायर क्रॉस अपील को भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम के खर्च के साथ खारिज कर दिया जाता है। भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम उच्च लागत में अपनी लागत के हकदार हैं।

न्यायालय, नंदा द्वारा देय तीन-पाँचवाँ, स्वराज पॉल द्वारा देय एक-पाँचवाँ और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा देय एक-पाँचवाँ। हमारे आदेश के संशोधन में dt. 4.4.85 सी. एम. पी. नं. <आई. डी. 1 में हम श्री एच. पी. नंदा और राजन नंदा को प्रबंध निदेशक के रूप में तब तक बने रहने का निर्देश देते हैं जब तक कि निदेशक मंडल इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेता।